चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 23 जनवरी– 29 जनवरी 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

नोटबंदी के बाद बेनामी सम्पत्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई

अब शत्रु सम्पत्ति पर नज़र

प्रभात रंजन दीन

पांच सौ और हजार के नोटों पर ग्रहण लगाने के बाद अब केंद्र सरकार ने अवैध सम्पत्तियों के अधिग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसकी पहली खेप में वे सम्पत्तियां जब्त या नीलाम की जाएंगी जो देश विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए लोगों की हैं. ऐसी सम्पत्तियों में अधिकांश पर माफिया तत्वों या संदिग्ध गतिविधियों में लगे लोगों का कब्जा पाया गया है. नोटबंदी का आदेश जारी होने के महीने भर बाद ही खुफिया एजेंसियों को देशभर में मौजूद ऐसी सम्पत्तियों, जिन्हें सरकारी शब्दावली में 'शत्रु सम्पत्ति' कहा जाता है, की ताजा स्थिति के बारे में छानबीन कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था. अधिकांश रिपोर्टें केंद्र सरकार के पास आ गई हैं. अब उन सम्पत्तियों पर काबिज लोगों से कब्जे का कानूनी आधार मांगा गया है. केंद्रीय खुफिया एजेंसी का मानना है कि कई ऐसी सम्पत्तियां हैं, जिन पर पाकिस्तान भाग गए माफिया सरगना दाऊद इब्राहीम के गुर्गों, सम्बन्धियों या दाऊद से जुड़े लोगों का कब्जा पाया गया है. इसी तरह शत्रु सम्पत्ति के नाम पर ऐसी भी तमाम सम्पत्तियां मिली हैं, जिन पर दशकों से संदेहास्पद लोगों का कब्जा है, जिन्हें अब सरकार अपने कब्जे में लेकर या तो नीलाम करेगी, या सरकारी इस्तेमाल में लाएगी. केंद्र सरकार ने दिसम्बर (2016) में ही शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश लाकर अपना कानूनी पक्ष मजबूत कर लिया था. शत्रु सम्पत्तियों पर सरकार के अधिग्रहण या उसकी नीलामी की प्रक्रिया में निचली अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं. शत्रु सम्पत्ति का पता लगाने का काम पहले से चल रहा था. ताजा पड़ताल के बाद पाया गया कि शत्रु सम्पत्ति जितनी अब तक बताई जा रही थी, उससे कहीं अधिक है. अभी इसकी संख्या बढ़ ही रही है. केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि सरकारों ने शत्रु सम्पत्ति का पता लगाने में रुचि नहीं ली. अभी भी कई राज्य सरकारें इसकी छानबीन में सहयोग नहीं कर रही हैं. अधिकारी कहते हैं कि केंद्र की यह कार्रवाई अवैध और बेनामी सम्पत्तियों पर कार्रवाई का पहला कदम है.

सभी सम्बद्ध राज्यों के जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश भेजा गया था कि वे अपने-अपने जिले की शत्रु सम्पत्तियों पर काबिज लोगों से कब्जे का कानूनी आधार हासिल करें. जो कब्जे कानून सम्मत पाए जाएंगे उनका किराया बाजार दर और निर्धारित सरकारी शर्तों पर लागू किया जाएगा और जिन कब्जों का कोई कानूनी आधार नहीं होगा, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. उत्तर प्रदेश में एक हजार 468 शत्रु सम्पत्तियों पर जो लोग काबिज हैं, उन्हें सरकारी नोटिस दी जा चुकी है. इनमें लखनऊ के हजरतगंज जैसे बेशकीमती इलाके में स्थित लारी बिल्डिंग, महमूदाबाद मेंशन, मौलवीगंज स्थित लाल कोठी, चारबाग गंगा प्रसाद रोड स्थित सिद्दीकी बिल्डिंग, गोलागंज इमामबाड़ा स्थित मलका जमानिया जैसी कुछ प्रमुख सम्पत्तियां भी शामिल हैं, जिस पर लोग दशकों से काबिज हैं. अधिकांश लोग किराया भी नहीं देते, जो देते हैं वे भी कभी कभार वाले ही हैं. बेशकीमती इलाकों में स्थित इन सम्पत्तियों पर काबिज लोगों को कौड़ियों का किराया जमा करने में भी तकलीफ होती है. इनमें हजरतगंज के मशहूर कपूर होटल, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठान हलवासिया ग्रुप, घनश्याम ऑप्टिकल्स, शर्मा एसोसिएट्स, मेसर्स ओरिएंट मोटरकार, कोहली ब्रदर्स जैसे प्रतिष्ठानों के धनपति मालिकों के नाम शामिल हैं. इनमें से कई लोगों ने तो कभी किराया दिया ही नहीं. अब इन्हें बकाये का किराया भी जमा करना होगा और सरकार को यह भी बताना होगा कि शत्रु सम्पत्ति पर उनके कब्जे का कानूनी आधार क्या है. इस तरह की नोटिसें प्रदेशभर में गई हैं. शत्रु सम्पत्ति के दायरे में रिहाईशी इमारतें, व्यवसायिक इमारतें, कृषि भूमि वगैरह आते हैं. लखनऊ जिला प्रशासन का कहना है कि राजधानी स्थित शत्रु सम्पत्तियों पर काबिज 35 प्रमुख डिफॉल्टर्स के खिलाफ पहली खेप की नोटिस जारी की गई है. इनके कब्जे के कानूनी आधार की पड़ताल की जा रही है. पुख्ता कानूनी आधार पाए जाने पर उनका सारा लंबित किराया वसूल किया जाएगा अन्यथा सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. जिन कब्जों का कोई कानूनी आधार नहीं पाया गया उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. लखनऊ जिला प्रशासन ने कहा कि लखनऊ की सदर तहसील की करीब डेढ़ सौ से भी अधिक शत्रु सम्पत्तियों का भौतिक निरीक्षण कराया गया है और उन पर काबिज लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी की गई है.

> **“देशभर में शत्रु सम्पत्तियों पर लोगों का क़ब्ज़ा है. इनमें से अधिकांश क़ब्ज़े ग़ैरक़ानूनी और संदेहास्पद हैं. क़ब्ज़ा करने वाले लोग कभी किराया भी नहीं देते. भूमाफिया शत्रु सम्पत्तियों को बेचने का धंधा भी कर रहे हैं. शत्रु सम्पत्तियों पर क़ब्ज़ा जमाए लोगों को नोटिसें दी गई हैं और उनसे क़ब्ज़े का क़ानूनी आधार मांगा गया है. उत्तर प्रदेश में भी तक़रीबन डेढ़ हज़ार शत्रु सम्पत्तियों पर लोग क़ाबिज़ हैं. अब शत्रु सम्पत्ति पर क़ब्ज़े का क़ानूनी आधार साबित करना पड़ेगा, अन्यथा शत्रु सम्पत्तियां ज़ब्त कर ली जाएंगी.”**

अध्यादेश लागू होने के बाद न केवल सिविल प्रशासन बल्कि सेना ने भी शत्रु सम्पत्ति का ब्यौरा लेना शुरू किया है. मध्य कमान मुख्यालय खास तौर पर इस मामले में सक्रिय है, क्योंकि मध्य कमान के दायरे में आने वाले सात राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओड़ीशा में से यूपी, एमपी और उत्तराखंड में सबसे अधिक शत्रु सम्पत्तियां हैं. सेना के मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में है. यूपी में लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, सीतापुर, कानपुर, फतेहगढ़, रामपुर, कासगंज, मुरादाबाद, मेरठ, झांसी जैसे इलाकों, उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, मसूरी और मध्य प्रदेश में भोपाल, महू, जबलपुर, इंदौर जैसे इलाकों में शत्रु सम्पत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में सेना खास तौर पर जुटी है. भोपाल के नवाब की सम्पत्ति भी शत्रु सम्पत्ति के रूप में घोषित है, लिहाजा वहां भी सेना ने जिला प्रशासन से सम्पत्ति का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा है. गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को इन सम्पत्तियों पर कब्जे का निर्देश भी जारी कर दिया था, लेकिन विस्तृत जांच बढ़ने पर फिलहाल इस कार्रवाई को रोक दिया गया है. भोपाल में ऐसी करीब डेढ़ सौ शत्रु सम्पत्तियों पर कार्रवाई लंबित पड़ी हुई है.

गृह मंत्रालय के दस्तावेज बताते हैं कि देश में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल शत्रु सम्पत्ति है. करीब तीन हजार (शेष पृष्ठ 2 पर)

त्रिकोणीय मुक़ाबले में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना | P-4

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड भ्रम और भटकाव में चुनाव | P-5

स्कूलों के लिए ज़मीन नहीं, सरकार बांट रही रेवड़ी | P-6

अब शत्रु सम्पत्ति पर नज़र

पृष्ठ 1 का शेष

करोड़ रुपये की चल सम्पत्ति के होने का अब तक प्रमाण मिला है. इसकी पड़ताल और आकलन का काम चल रहा है और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. शुरुआत में 2186 शत्रु सम्पत्ति का ही पता लगा था, जो अब 16 हजार का आंकड़ा पार कर रहा है. शत्रु सम्पत्ति का पता लगाने में कई राज्यों ने केंद्र का सहयोग नहीं किया. इनमें पश्चिम बंगाल अव्वल है. उसके बाद बिहार का नम्बर आता है. शत्रु सम्पत्ति के पांच हजार से अधिक मामले पश्चिम बंगाल सरकार की फाइल में बंद पड़े हुए हैं. शत्रु सम्पत्ति के पहले वाले आंकड़े यानि, कुल 2186 शत्रु सम्पत्तियों में से 1468 सम्पत्तियां अकेले उत्तर प्रदेश में थीं, जिसकी संख्या बढ़ रही है. अन्य राज्यों में मसलन, पश्चिम बंगाल में 351, दिल्ली में 66, गुजरात में 63, बिहार में 40, गोवा में 35, महाराष्ट्र में 25, केरल में 24 व शेष शत्रु सम्पत्तियां कुछ अन्य राज्यों में थीं, लेकिन बाद में गहनता से कराई गई छानबीन में शत्रु सम्पत्तियों की संख्या 16 हजार के पार चली गई. गृह मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक देश की 31 शत्रु सम्पत्तियों का इस्तेमाल केंद्रीय सुरक्षा बल कर रहे हैं. इनमें से 12 का इस्तेमाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सात का इस्तेमाल नेशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी), छह का इस्तेमाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ), चार का इस्तेमाल सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और दो शत्रु सम्पत्तियों का इस्तेमाल नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) कर रहा है. उल्लेखनीय है कि नवम्बर महीने में नोटबंदी लागू किए जाने के बाद 23 दिसम्बर 2016 की देर रात से शत्रु संपत्ति (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश लागू किया गया. 22 दिसम्बर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 दिसम्बर 2016 को अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दी थी. उसके बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था. यह अध्यादेश पांचवीं बार लाया गया. संसद से पारित होने के बाद यह विधेयक बन जाएगा. नोटबंदी के बाद लागू होने वाले इस अध्यादेश को मंजूर नहीं करने की राष्ट्रपति से अपील भी की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उन अपीलों पर ध्यान नहीं दिया.

जहां तक माफिया और आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम की भारत में अवैध सम्पत्ति का मसला है, इसे भी शत्रु सम्पत्ति के दायरे में रखा जा रहा है. भारत में रियल इस्टेट के धंधे में कई प्रमुख और मशहूर कंपनियों में दाऊद का पैसा लगा हुआ है. केंद्रीय खुफिया एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम की ऐसी नौ विशाल सम्पत्ति का पता लगाया था जिसे बेचने का कुचक्र चल रहा था. हालांकि दाऊद ने केंद्र के सतर्क होने के पहले अपनी कई सम्पत्तियां बेच भी डालीं. ये सम्पत्तियां मुम्बई, पुणे, मैसूर, मसूरी, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता शहर में हैं. उत्तराखंड के मसूरी में होटल, लखनऊ में होटल और रियल इस्टेट के साथ-साथ कई फार्म हाउस और रिज़ॉर्ट्स में भी दाऊद का धन लगा है, जिसे बाहर से सफेदपोश चला रहे हैं. वर्ष 2015 के दिसम्बर महीने में ही सरकार ने मुम्बई के नागपाड़ा में दाऊद के एक होटल 'दिल्ली जायका' को जब्त कर उसे नीलाम कर दिया था. दिल्ली के सदर बाजार स्थित बेलीराम मार्केट की लगभग 200 दुकानों को लेकर भी शत्रु सम्पत्ति का विवाद चल रहा है. दिल्ली के बल्लीमारान स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाना भी लंबे अर्से तक शत्रु सम्पत्ति विवाद में फंसा रहा था. शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश के तहत भोपाल में पूर्व नवाब की अरबों रुपये की सम्पत्ति भी शत्रु सम्पत्ति में शुमार है. भोपाल नवाब परिवार की सम्पत्ति भोपाल और उसके आसपास के तीन विधानसभा क्षेत्रों में फैली है. भोपाल शहर के कई मोहल्ले नवाब की सम्पत्ति पर ही बसे हुए हैं.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

ब्रिटेन के बैंक में फंसे हैं करोड़ों रुपये

शत्रु सम्पत्ति विवाद में प्रमुख रूप से महमूदाबाद रियासत, भोपाल नवाब, मुम्बई में मोहम्मद अली जिन्ना का घर और लंदन के एक बैंक में जमा हैदराबाद फंड का मसला शुमार है. ब्रिटेन के रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (जो पहले नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक के नाम से जाना जाता था) में तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की रकम 1948 से ही जमा है. इस पर पाकिस्तान भी दावा करता रहा है, लेकिन ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तानी दावे को अनुचित करार दिया है. हैदराबाद के विलय के समय तत्कालीन निजाम के वित्त मंत्री ने ब्रिटेन के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में 1,007,940 पौंड और 9 शिलिंग पाकिस्तानी उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतउल्लाह के खाते में जमा करवा दिए थे. इसकी सूचना मिलते ही निजाम ने बैंक को वह रकम वापस उनके खाते में ट्रांसफर करने का संदेश भेजा, लेकिन बैंक ने मना कर दिया. निजाम ने अदालत की शरण ली तो पाकिस्तान ने भी दावा ठोक दिया. मामला इंग्लैंड के न्यायालय के ट्रिब्यूनल में चला गया. भारत भी दावेदार था. अदालती कार्रवाई के कारण खाता फ्रीज कर दिया गया था. भारत का कहना है कि हैदराबाद फंड हैदराबाद की जनता का पैसा है और रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद पूरी रकम भारत को मिलनी चाहिए. 2008 में भारत सरकार ने फंड के बंटवारे पर सहमति कायम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इन्कार कर दिया और 2013 में गुपचुप तरीके से फिर कानूनी पहल शुरू कर दी. लेकिन तब तक पाकिस्तान को हैदराबाद फंड की सुरक्षा के अधिकार से वंचित किया जा चुका था. पाकिस्तान सरकार अपने यहां सारी शत्रु सम्पत्तियां जब्त कर चुकी है, जबकि भारत में शत्रु सम्पत्तियों के मसले में भी सियासत ही होती रही है. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 47
23 जनवरी- 29 जनवरी 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

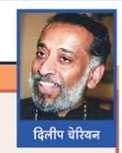
दिलीप चेरियन

बाबू पर बवाल

ममता बनर्जी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों में अकेली ऐसी नेता हैं, जो हाल के महीनों में केंद्र की मोदी सरकार से दो-दो हाथ करने के मूड में दिखीं. यह सियासी कड़वाहट कई क्षेत्रों में नजर आई, खासकर टी-बोर्ड के संचालन को लेकर. विवाद टी-बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन पद को लेकर था. डिप्टी चेयरमैन बोर्ड का कार्यकारी प्रधान होता है. चाय उद्योग के प्रोत्साहन में उसकी भूमिका को देखते हुए डिप्टी चेयरमैन के पद को एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है. पहले चेयरमैन ही टी-बोर्ड का कार्यकारी प्रधान होता था. लेकिन पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए डिप्टी चेयरमैन को बोर्ड का कार्यकारी प्रधान बना दिया था. इसी पद पर नियुक्ति को लेकर यह विवाद सामने आया है. 1991 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर अर्णव रॉय की इस पद पर नियुक्ति होनी थी. लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि अर्णव रॉय टी-बोर्ड के चेयरमैन बनें. सूत्रों का कहना है कि चेयरमैन के पद पर राजनीतिक व्यक्ति को बैठाने के लिए उसे गैर कार्यकारी बनाने का केंद्र का फैसला ममता बनर्जी को नागवार गुजरा है. सीधी बात यह है कि ममता बनर्जी नहीं चाहतीं कि स्टेट कैडर का कोई अधिकारी भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के अंदर काम करे. अब केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि यदि अर्णव रॉय की इस पद पर नियुक्ति नहीं होती है, तो पश्चिम बंगाल कैडर के किसी और अधिकारी के नाम पर भी विचार नहीं किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो चाय उद्योग में राज्य के हित को देखते हुए यह फैसला पश्चिम बंगाल के लिए सही नहीं होगा. ■

नाराज़ हैं बाबू

एक ब्यूरोक्रेटिक गलती ने राजस्थान सरकार के लिए शर्मिंदगी खड़ी कर दी है. चूक सामने आया है, आईजी रैंक के दो आईपीएस अफसरों के प्रमोशन के मामले में, जिसमें ज्वाइनिंग की तिथि समान होने के बावजूद 6 अफसरों को नजरअंदाज किया गया है.

सूत्रों का कहना है कि चूक इसलिए हो गई क्योंकि आईपीएस ऑफिसर संजय अग्रवाल और हेमंत प्रियदर्शी ने 1 साल बाद सर्विस ज्वाइन किया था. ये दोनों अफसर 1992 बैच के हैं, लेकिन उन्होंने सेवा में अपना योगदान दिया एक साल बाद. यह महज इत्तेफाक है कि छह अन्य अफसरों तन्मय कुमार, अखिल अरोड़ा, आलोक, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, और संदीप वर्मा ने भी उसी दिन ज्वाइन किया. अब कार्मिक विभाग इस गलती को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास दो विकल्प हैं. या तो दोनों अफसरों के प्रमोशन को वापस लिया जाय या फिर उन सभी 6 अफसरों को गृह सचिव के पद पर प्रोन्नत किया जाय, जिनकी अनदेखी हुई है. सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है. ■

थॉमस सब पर भारी

केरल के आईएएस अफसरों के सामूहिक अवकाश की धमकी का असर कुछ समय के लिए थमता दिख रहा है. लेकिन बाबूओं की नाराजगी ने केरल की वाम सरकार की मुश्किलें तो बढ़ी ही दी है. राज्य सतर्कता आयोग के मुखिया जैकब थॉमस द्वारा राज्य के कई वरिष्ठ बाबूओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए जाने का ये बाबू विरोध कर रहे हैं.

इन बाबूओं का कहना है कि उन्हें पीड़ित बनाने की कोशिश की जा रही है और थॉमस अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. बाबूओं के बीच यह गुस्सा तब पनपा जब पिछले साल थॉमस ने तीन नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की. लेकिन हाल ही में बाबूओं ने सामूहिक रूप से छुटटी पर जाने की घोषणा इस वजह से की क्योंकि सतर्कता विभाग ने पॉल एंटोनी को उद्योग विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने का निर्णय लिया. पॉल पूर्व उद्योग मंत्री ई.पी जयनारायण के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सह अभियुक्त हैं. लेकिन सूत्रों का कहना है कि थॉमस, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं. सतर्कता निदेशक पद के लिए ये मुख्यमंत्री विजयन की पहली पसंद थे. फिलहाल थॉमस को जब तक सीएम का वरदहस्त प्राप्त है, तब तक सतर्कता विभाग इसी तरह से काम करता रहेगा. ■

अब शत्रु सम्पत्ति पर नज़र

पृष्ठ 2 का शेष

सम्पत्तियां अकूत, पर राजस्व शून्य

उत्तर प्रदेश के 'राजा' महमूदाबाद उर्फ़ आमीर मोहम्मद ख़ान की लखनऊ समेत उत्तरप्रदेश के कुछ अन्य जिलों और उत्तराखंड राज्य में स्थित अकूत सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति के रूप में घोषित है. शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश के तहत शत्रु सम्पत्तियों का मालिकाना हक केंद्र सरकार को तो मिल गया है, लेकिन अधिकांश सम्पत्ति अवैध कब्जे में है और उससे सरकारी राजस्व कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है. यही हाल प्रदेश की अन्य सभी शत्रु सम्पत्तियों का भी है, जहां लोग कब्जा जमाए बैठे हैं और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. राजा महमूदाबाद (लखनऊ के नज़दीक सीतापुर जिले की तहसील का नाम है मुरादाबाद) की ऐसी सम्पत्तियों की कुल संख्या 936 है. यह सम्पत्ति लखनऊ, सीतापुर और नैनीताल में है, जो अब शत्रु सम्पत्ति के दायरे में है. लखनऊ में राजा महमूदाबाद की सम्पत्तियों में मशहूर बटलर पैलेस, महमूदाबाद हाउस और हज़रतगंज की आलीशान दुकानें

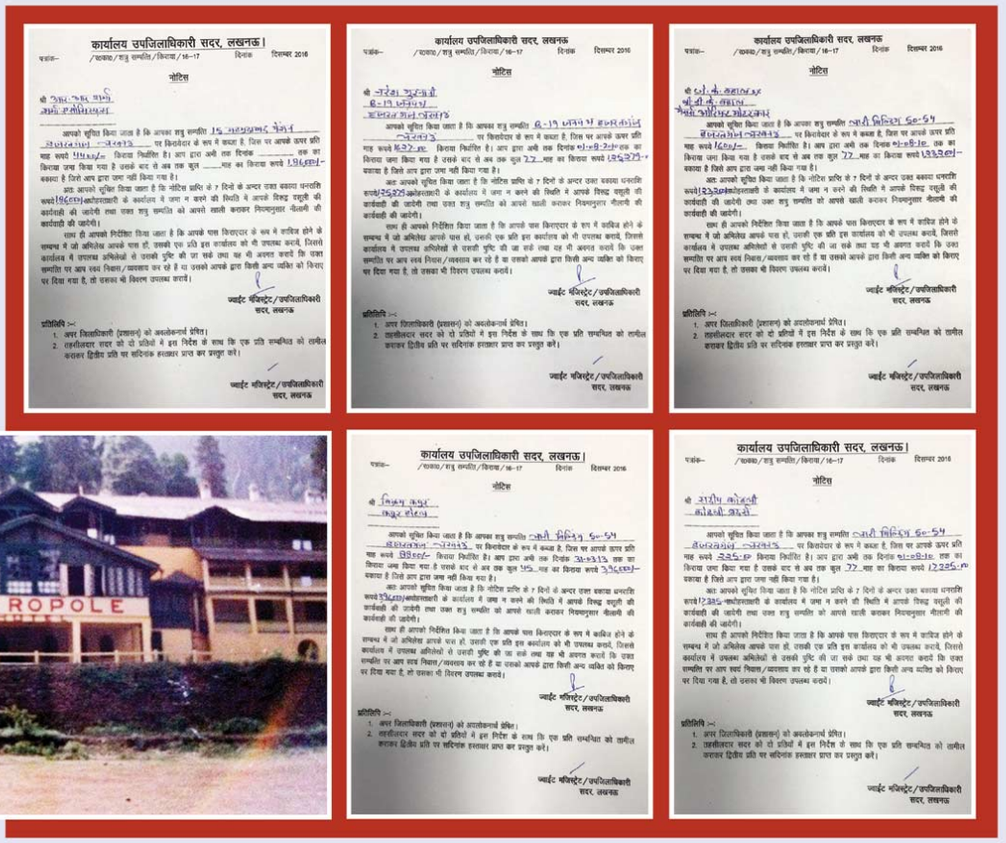
कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

नोटिस

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

नोटिस

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

नोटिस

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

नोटिस

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

नोटिस

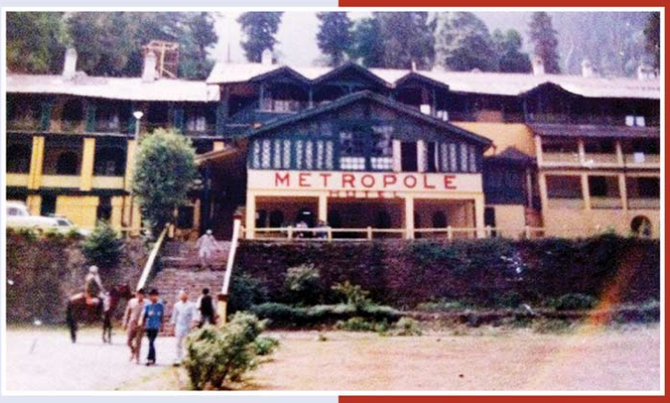

आमिर अहमद खान (तत्कालीन राजा महमूदाबाद) के भारत-पाकिस्तान दोनों ही देशों में अच्छे राजनीतिक संपर्क थे. उनका दोनों ही देशों में आना-जाना लगा रहता था. भारत विभाजन के बाद से वे ईराक में रह रहे थे. 1957 में उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकता ले ली. भारत ने देश छोड़कर पाकिस्तान जा बसे लोगों की सम्पत्तियां भारत के रक्षा नियम (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स) 1962 के तहत अपने संरक्षण में ले लीं. भारत सरकार ने यह कार्रवाई 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद की, जबकि पाकिस्तान यह काम पहले ही कर चुका था.

और होटल्स हैं. सीतापुर के जिलाधिकारी, एसएसपी और सीएमओ के आवास भी राजा महमूदाबाद की सम्पत्तियों का ही हिस्सा हैं.

राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान (तत्कालीन राजा महमूदाबाद) के भारत-पाकिस्तान दोनों ही देशों में अच्छे राजनीतिक संपर्क थे. उनका दोनों ही देशों में आना-जाना लगा रहता था. भारत विभाजन के बाद से वे ईराक में रह रहे थे. 1957 में उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकता ले ली. भारत ने देश छोड़कर पाकिस्तान जा बसे लोगों की सम्पत्तियां 'भारत के रक्षा नियम (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स) 1962' के तहत अपने संरक्षण में ले लीं. भारत सरकार ने यह कार्रवाई 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद की, जबकि पाकिस्तान यह काम पहले ही कर चुका था. 1973 में राजा महमूदाबाद की लंदन में मौत हो गई. उनके बेटे मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने पिता की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार का दावा पेश किया. लखनऊ सिविल कोर्ट ने उन्हें सम्पत्ति का वारिस माना, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ. 2001 में मुम्बई हाईकोर्ट ने भी महमूदाबाद के पक्ष में फैसला दिया. सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महमूदाबाद वारिस को सम्पत्ति का अधिकार मिल गया. 2010 में कांग्रेस सरकार शत्रु सम्पत्ति अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश लाई और सभी सम्पत्तियों को फिर से कब्जे में ले लिया.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत से पलायन कर पाकिस्तान चले गए लोगों की छोड़ी गई अधिकांश सम्पत्तियों पर भू माफियाओं और संदेहास्पद तत्वों का कब्जा है. कई स्थानों पर भू माफियाओं द्वारा शत्रु सम्पत्तियां बेची जा रही हैं. लखनऊ समेत फैजाबाद, कासगंज, बरेली, रामपुर जैसे कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं. राजनीतिक छत्र-छाया वाले माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा. शत्रु सम्पत्ति पर काबिज लोग सरकारी राजस्व के भी शत्रु बन गए हैं और सरकारी कर जमा नहीं कर रहे हैं. प्रदेश के राजस्व विभाग के अधिकारी ने कासगंज जिले का हवाला देते हुए बताया कि जिले में 152 शत्रु सम्पत्तियां चिन्हित की गई थीं, इन पर करोड़ों का राजस्व बकाया है. इन शत्रु सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा है. कासगंज तहसील के किनावा में एक, वाहिदपुर माफी में एक, ढोलना में तीन, खेड़िया में छह, रहमतपुर माफी में छह, विरहरा में एक, तालिकपुर सराय में 10, नरायनी में सात, मुबारिकपुर में चार, भिटौना में 19 और टंडोली माफी में 50 शत्रु सम्पत्तियां शिनाख्त की गईं, लेकिन इनमें से अधिकांश सम्पत्तियां अनाप-शनाप लोगों को बेच डाली गईं. खरीद-बिक्री भी अवैध तरीके से हुई, जिसका कोई राजस्व रिकार्ड नहीं है. अब सरकार के सामने उन सम्पत्तियों के मालिकाना हक की पहचान करने की भारी समस्या है. ऐसा ही हाल नैनीताल स्थित महमूदाबाद की सम्पत्ति का भी हुआ. नैनीताल स्थित मेट्रोपोल होटल भी शत्रु सम्पत्ति घोषित है, लेकिन अरबों की इस सम्पत्ति पर हुए कब्जे के खिलाफ नैनीताल जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया. मल्लीताल कोतवाली में एक प्राथमिकी दर्ज कर जिला प्रशासन मस्त हो गया. मेट्रोपोल होटल अपने जमाने में नैनीताल का सबसे बड़ा होटल हुआ करता था. 41 कमरों के इस होटल का निर्माण एक अंग्रेज मिस्टर रेंडल ने किया था. बाद में यह राजा महमूदाबाद की सम्पत्ति हो गई. इस पर अनेक लोगों का कब्जा रहा. 1995 तक यह होटल के रूप में चलता रहा, फिर 2010 में अदालत के आदेश पर जिला प्रशासन ने बतौर कस्टोडियन इसे कब्जे में ले लिया. जिला प्रशासन ने इस पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन इसकी देखरेख में कोई दिलचस्पी नहीं ली. भूमाफियाओं ने होटल में आग लगवा दी, जिसमें बॉयलर रूम, बैडमिंटन कोर्ट और 14 कमरों वाला हिस्सा खाक हो गया. सम्पत्ति पर कब्जे के इरादे से ही यह आग लगवाई गई थी. इसमें जिला प्रशासन की संदेहास्पद भूमिका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता. शत्रु सम्पत्ति का कानूनी संरक्षक जिला प्रशासन ही होता है लेकिन सम्पत्तियों के नाम जोड़ने-घटाने का भी खेल प्रशासन ही करता रहता है. सामर्थ्यवान लोग शत्रु सम्पत्ति की लिस्ट से अपनी सम्पत्ति हटवाने में कामयाब हो जाते हैं. ऐसे भी कई उदाहरण सामने आ रहे हैं.

लखनऊ में पहली खेप में जिनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी हुई

1. संदीप कोहली, कोहली ब्रदर्स लारी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ
2. विक्रम कपूर, कपूर होटल - लारी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ
3. जेके बहल, ओरिएंट मोटरकार - लारी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ
4. नरेश गुरनानी, घनश्याम ऑप्टिकल्स - लारी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ
5. सावित्री देवी महमूदाबाद मेंशन, हजरतगंज, लखनऊ
6. गिरजा शंकर हलवासिया - महमूदाबाद मेंशन, हजरतगंज, लखनऊ
7. आरआर शर्मा, शर्मा एंड एसोसिएट्स - महमूदाबाद मेंशन, हजरतगंज, लखनऊ
8. गौहर अली पुत्र अरशद अली - लाल कोठी, मौलवीगंज, लखनऊ
9. केडब्लू चंद्रा पुत्र अब्दुल वाहिद सिद्दीकी - लाल कोठी, मौलवीगंज, लखनऊ
10. अजीज अहमद पुत्र मतलूब आलम - लाल कोठी, मौलवीगंज, लखनऊ
11. हाजी इस्माइल पुत्र हाजी सिकंदर बख्श - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
12. जफरुल इस्लाम पुत्र जैनुब आयदीद - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
13. मूसा पुत्र दुलारे - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
14. जब्बार हुसैन पुत्र मुर्तजा हुसैन - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
15. अतीक अहमद पुत्र लईक अहमद - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
16. ताहिर हुसैन पुत्र अफसर हुसैन - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
17. अनीस बानो पत्नी जब्बार हुसैन - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
18. शरफ जहां पत्नी राशिद अली - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
19. मोहम्मद मूसा पुत्र अफसर हुसैन - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
20. बदरुल हसन पुत्र मेहदी हसन - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
21. मोहम्मद खलील पुत्र मो. हाबी - सिद्दीकी बिल्डिंग, गंगा प्रसाद रोड, अस्तबल, चारबाग, लखनऊ
22. मौलाना साजिद - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
23. शाकिर हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
24. राम जानकी पुत्र महावीर - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
25. आनंद अग्रवाल पुत्र रामदास - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
26. हरीराम - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
27. अब्दुल हई पुत्र मुन्ने - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
28. रयाज हैदर पुत्र मुख्तालिस हुसैन - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
29. मिर्जा वसी हसन पुत्र मिर्जा आगा हसन - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
30. गुलाम मुहम्मद पुत्र मुहम्मद हुसैन - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
31. नसीर उर्फ मुन्ने पुत्र छुट्टन - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
32. मोहम्मद मजीद - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
33. शकीरा बेगम पत्नी गुलाम रसूल - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
34. मोहम्मद हलीम पुत्र अब्दुल शकूर - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ
35. इरफान अप्पू पुत्र कल्लू टेनी - मलका जमानिया, इमामबाड़ा, गोलागंज, लखनऊ

बेनामी सम्पत्तियों पर गिरेगी गाज, पहले से था अंदेशा

नोटबंदी के बाद अगला नम्बर बेनामी और अवैध सम्पत्तियों का आने वाला है, इसका पहले से अंदेशा भी था और बाद में इसका औपचारिक तौर पर ऐलान भी हुआ. बेनामी सम्पत्तियों पर केंद्र सरकार की निगाह 2015 से ही थी. सरकार ने 13 मई 2015 को लोकसभा में बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट पेश किया था. 01 नवम्बर 2016 से देश में बेनामी सम्पत्ति निषेध कानून लागू हो गया था. इस कानून के जरिए चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी खरीद-फरोख्त आधार कार्ड और पैन कार्ड से जोड़ दिए जाएंगे. साथ ही जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों को इसका विस्तृत ब्यौरा आयकर विभाग को देना होगा.

इस कानून में संशोधन के जरिए बेनामी ट्रांजेक्शन की परिभाषा बदलने, बेनामी ट्रांजेक्शन करने वाले लोगों पर अपीलीय ट्रिब्यूनल और सम्बद्ध संस्था की तरफ से जुर्माना लगाए जाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है. इस कानून के मुताबिक बेनामी सम्पत्ति वह है जिसे किसी दूसरे के नाम पर लिया जाए और उसकी कीमत का भुगतान कोई और करे. अब उन सारी सम्पत्तियों को बेनामी माना जाएगा जो किसी फर्जी नाम से खरीदी गई हो और जिसके असली मालिक का पता न चले. इसके अलावा दूसरे नामों से बैंक खातों में किए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी काले धन के दायरे में आएंगे. केंद्र सरकार को ऐसी सारी सम्पत्तियां जब्त कर लेने का अधिकार है. इसके अलावा बेनामी सम्पत्ति के तहत ट्रांजेक्शन करने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. दोषी पाए गए व्यक्ति पर भारी जुर्माना और सात साल तक की कैद हो सकती है. बेनामी सम्पत्ति के खिलाफ कार्रवाई में आयकर विभाग ने 3,185 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है. इसके अलावा 428 करोड़ रुपये की नकदी और गहने जब्त किए हैं. बेनामी सम्पत्तियों को लेकर आयकर विभाग की ओर से तीन हजार से ज्यादा नोटिसें जारी की गई हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

त्रिकोणीय मुक़ाबले में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना

शफ़ीक़ आलम

गोवा के विधानसभा के पिछले कुछ चुनावों में आम तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुक़ाबला रहा है. क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर इन दोनों पार्टियों में से किसी एक की सरकार बनवाने में निर्णायक भूमिका में रही हैं. भाजपा में अंदरूनी विद्रोह है. इसके बावजूद पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर एकला चलो की राह पर निकल चुकी है. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 2014 के आम चुनावों की हार के बाद कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश रही है. वर्ष 2014 के बाद पुद्दुचेरी को छोड़कर कांग्रेस को किसी भी राज्य में कामयाबी नहीं मिली है. पिछले वर्ष 4 अप्रैल से 16 मई के बीच संपन्न पांच राज्यों के चुनावों के बाद भाजपा ने सबसे अधिक विधायकों के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था. ज़ाहिर है कांग्रेस को गोवा से काफी उम्मीदें होंगी. लेकिन गोवा चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू आम आदमी पार्टी का मुकाबले में शामिल होना है. चुनाव पूर्व कराये गए किसी भी सर्वेक्षण ने आम आदमी पार्टी को नज़रअंदाज़ नहीं किया है. बल्कि कौटिल्य ने अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया है. लिहाज़ा यह आसानी से कहा जा सकता है कि गोवा में त्रिकोणीय मुकाबला तय है.

बहरहाल, गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खेमा भले ही आत्मविश्वास से भरा नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार उसके लिए रास्ता आसान नहीं है. एक तरफ जहां आरएसएस के पूर्व राज्य प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने बगावत का झंडा उठा रखा है, वहीं मुख्यमंत्री लक्ष्मीकान्त पार्सेकर द्वारा एमजीपी के दो मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किये जाने से भाजपा-एमजीपी गठबंधन समाप्त हो गया है. समीक्षकों का मानना है कि यदि भाजपा-एमजीपी का गठबंधन नहीं टूटता तो भाजपा का रास्ता बहुत आसान हो जाता. गौरतलब है कि 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 21 सीटें जीत कर एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी, जबकि पहली बार कांग्रेस राज्य में एक अंक में सिमट गई थी. कांग्रेस को 9 सीटें मिली थीं, जबकि एमजीपी को 3 सीटें प्राप्त हुई थीं.

ताज़ा घोषणा के मुताबिक़, भाजपा राज्य के 40 सीटों में से 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और बाक़ी की तीन सीटें, जो इसाई बहुल हैं, वहां निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देगी. 2012 में पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन इस बार भाजपा ने 2012 के विपरीत किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है. हालांकि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसी को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया है. उत्तर प्रदेश का चुनाव पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सकता है कि उसी रणनीति के तहत इसे बरकरार रखने की कोशिश की गई हो. मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने की नीति भाजपा के लिए कई राज्यों में कारगर साबित हुई है, लेकिन यह रणनीति बिहार में बुरी तरह से नाकाम हो गई थी. जहां तक भाजपा की चुनावी तैयारियों का सवाल है, तो पार्टी ने अब तक 35 विधानसभा क्षेत्रों में मनोहर पर्रीकर और मुख्यमंत्री लक्ष्मीकान्त पार्सेकर की संकल्प रैलियां आयोजित की हैं.

पिछले तीन चुनावों में गोवा विधानसभा की दलगत स्थिति

वर्ष	भाजपा	कांग्रेस	एमजीपी	अन्य
2002	17	16	2	5
2007	14	16	2	8
2012	21	9	3	7

जिस तरह से एमजीपी के साथ गठबंधन टूटने से भाजपा को नुकसान की आशंका है, उसी तरह आरएसएस के पूर्व राज्य प्रमुख सुभाष वेलिंगकर के आरएसएस और भाजपा से बग़ावत के कारण भी हैं. सुभाष वेलिंगकर की मांग थी कि भाजपा सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को अनुदान देना बंद करे और मराठी व कोंकणी भाषा के विकास के लिए प्रयास करे, लेकिन मनोहर पर्रीकर और बाद में लक्ष्मीकान्त पार्सेकर की सरकार ने भी उनकी मांगों की अनदेखी की. इससे नाराज़ होकर उन्होंने भाजपा और आरएसएस से बग़ावत कर गोवा सुरक्षा मंच नाम का संगठन बना लिया और चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली. अब राज्य की तीन हिन्दुत्ववादी पार्टियां एमजीपी, गोवा सुरक्षा मंच और शिवसेना ने एक गठबंधन बनाने की घोषणा कर दी है. एमजीपी नेता सुदीन धवलीकर इस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. गठबंधन ने राज्य की 40 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. समीक्षकों का मानना है कि इस गठबंधन में भाजपा का खेल बिगाड़ने की पूरी क्षमता है.

उधर ज़मीनी हकीकत को समझते हुए कांग्रेस ने शुरू में आनाकानी की, लेकिन बाद में एनसीपी और गोवा फॉरवर्ड और अतनसिओ मोसेराटे के साथ गठबंधन करने का मन बना लिया. दरअसल 2012 के चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद प्रदेश कांग्रेस पुन: पार्टी को राज्य में स्थापित करने में जुटी है. वहीं 2014 के आम चुनाव में मिली हार और एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में मिल रहे पराजय के बाद केंद्रीय नेतृत्व यहां हर संभावना को तलाशने में जुटा है, ताकि पार्टी को लड़ाई लड़ने की स्थिति में खड़ा किया जा सके. लिहाज़ा गोवा में कांग्रेस के अध्यक्ष लुइज़िनो फलेरो और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी गिरीश चोदनकर काफी दिनों से इन पार्टियों से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में वैसे ही वादे किए हैं, जैसे भाजपा ने 2012 में किए थे. दरअसल कांग्रेस अपने गठबंधन दलों के साथ भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकती है. चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में भी कांग्रेस को ख़ारिज नहीं किया गया है.

दिल्ली और पंजाब में अपने क़दम ज़माने के बाद आम आदमी पार्टी गोवा में भी अपनी ज़मीन तलाश रही है. दरअसल गोवा के ऐसे दल और संगठन, जो न कांग्रेस के साथ थे और न ही भाजपा के साथ, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है. आम आदमी पार्टी ने पूर्व ब्यूरोक्रेट एल्विस गोमेज को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है. हालांकि ऐसी खबर आ रही है कि गोमेज़ को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी के अन्दर का एक पक्ष खुश नहीं है. कुछ महीनों के दौरान केजरीवाल ने राज्य के कई दौरे किए हैं, कई रैलियां की हैं जिनमें अच्छी खासी भीड़ जमा हुई. राज्य में कार्यकर्ताओं की एक टीम भी खड़ी हो गई है. आम आदमी पार्टी राज्य की कुल 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है. दरअसल आम आदमी पार्टी के मैदान में आ जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आम तौर पर होने वाला द्विपक्षीय मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है.

हालांकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सभी भारी बहुमत से अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन राज्य में चुनाव के इतिहास और मौजूदा राजनीतिक समीकरण को देखते हुए यही लगता है कि राज्य एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नाकेबंदी के बीच शांतिपूर्ण होगा चुनाव!

एस. बिजेन सिंह

मणिपुर में 11वीं विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है. राज्य में दो चरणों में 4 और 8 मार्च को चुनाव होंगे. मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीट हैं. पहले चरण में घाटी के 38 विधानसभा सीट और दूसरे चरण में पहाड़ के 22 विधानसभा सीट पर चुनाव होगा. 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है. यहां फिलहाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. मणिपुर में मुख्य नेशनल पार्टी कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई (एम) है. स्थानीय पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनपीएफ, जदयू, आम आदमी पार्टी, पीपुल्स रिसर्जेन्स एंड जस्टिस एलाइन्स (प्रजा) आदि हैं.

इरोम शर्मिला के चुनाव में हिस्सा लेने के कारण इस बार मणिपुर का चुनाव काफी दिलचस्प होगा. शर्मिला अफस्पा के खिलाफ 16 वर्षों से आमरण अनशन कर रही थीं. अब उन्होंने अपने आंदोलन का माध्यम राजनीति को चुना है. सत्ता के जरिए अब वे अफस्पा की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी. उनकी प्रजा पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मजे की बात तो ये है कि शर्मिला मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी के विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. शर्मिला के चुनाव में उतरने से कांग्रेस को नुकसान होना तय है. हालांकि, शर्मिला राजनीति में नई हैं और उनके राजनीति में आने के फैसले से लोग नाराज भी हैं, इसके बावजूद वे चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होंगी. एक राजनेता के रूप में देखने से ज्यादा उनको लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए उनके राजनीति में आने के फैसले से लोग आहत हैं. सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर शर्मिला पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं, लेकिन उस लोकप्रियता को वे चुनाव में कितना भुना पाती हैं, इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं. वे भी सच है कि शर्मिला की हार एक तरह से मणिपुरी जनता की हार होगी, क्योंकि अब तक वे जोशो-खरोश के साथ जनता की लड़ाई लड़ रही थीं. लेकिन जब उन्होंने इस लड़ाई को राजनैतिक रूप से जारी रखने की घोषणा की, तो वही जनता बिदक गई.

भाजपा ने भी इस सियासी जंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है. भाजपा मैरीकॉम को स्टार प्रचारक बनाने जा रही हैं. राज्य में मैरी की छवि शर्मिला से कमतर नहीं है. वे ट्राइबल समुदाय से हैं, इसलिए भाजपा को उम्मीद है कि मैरी को स्टार प्रचारक बनाने से कांग्रेस के विरोधी पहाड़ी क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग भाजपा की तरफ खींचेंगे. वैसे भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है. मणिपुर में पहले विधानसभा चुनावों में भाजपा को एक भी कैंडिडेट खड़ा करने के लिए लोग नहीं मिलते थे, लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदली हैं. असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद पूर्वोत्तर में भाजपा का मनोबल और भी मजबूत हुआ है. मणिपुर के निवासियों की भी भाजपा में रुचि बढ़ी है. राज्य में कांग्रेस की सरकार लंबे समय से होने के बाद भी भाजपा इस बार मुकाबले में होगी. भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों का मणिपुर के गांव-गांव जाकर प्रचार करने में जुटे हैं. केंद्रीय मंत्री भी हर दो माह में पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर लोगों का हालचाल ले रहे हैं. लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत रेल लाइनों पर खूब काम हो रहा है. त्रिपुरा और मिजोरम तक रेल पहुंच गया है. मणिपुर में भी जिरिबाम तक रेल लाइनें बिछ गई हैं. उम्मीद है कि दो तीन-साल में राजधानी इंफाल तक रेलवे ट्रैक पहुंच जाएंगे. राज्य में चल रहे इन विकास कार्यों को देखकर लोगों में भी एक बदलाव की लहर चल पड़ी है. लोग महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा राज्य के लिए कुछ तो कर रही है. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे. साथ में मैरीकॉम की बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन होगा. भाजपा का नया अध्यक्ष भवानंद के बनने के बाद इंफाल के म्यूनिसिपल चुनाव में चार जगहों पर भाजपा की जीत हुई है. कुल मिलाकर भाजपा की स्थिति राज्य में मजबूत दिख रही है.

कांग्रेस सरकार से राज्य के लोग खफा हैं. लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. लोगों को लगता है कि कांग्रेस सरकार केवल वादे करती है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखता है. हाल में नए सात जिलों की घोषणा भी चुनाव के नजदीक आने पर की गई. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घोषणा 2011 में ही की जा सकती थी, तब राज्य को ब्लॉकेड का सामना नहीं करना पड़ता. 2011 में 120 दिन की आर्थिक नाकेबंदी हुई थी, उसमें भी सरकार ने लूंज-पूंज तरीके से काम किया. आम लोगों को आज भी इसकी जानकारी नहीं दी गई कि यूएनसी के साथ किन शर्तों पर समझौता किया गया. वहीं, अफस्पा के मामले में भी कांग्रेस सरकार ने कोई ठोस कार्य नहीं किया. शर्मिला 16 सालों से भूख हड़ताल पर थीं, लेकिन राज्य का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं गया. इसे लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी थी. यहां पुलिस और टीचर की नौकरी के नाम पर भी खूब हंगामा होते रहा. इंटरव्यू होने के बाद भी नतीजों की घोषणा नहीं की गई. इसे लेकर युवाओं में खासी नाराजगी थी. हाल में जब लोग आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे थे, तब भी सरकार सोई रही. राजनीति के कुछ जानकारों का कहना है कि राज्य में भाजपा की टक्कर सिर्फ कांग्रेस से है. मणिपुर में आम आदमी पार्टी के पास कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है, जिसके बूते चुनावी मैदान में उतरा जा सके. पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप का परफॉर्मेंस बुरा रहा था. लोग आम आदमी पार्टी में पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण यह भी है कि मणिपुर की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है. आम आदमी पार्टी राज्य में अभी शुरुआती स्टेज पर है. बाकी पार्टियां सीपीआई एम, तृणमूल कांग्रेस, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, लोक जन शक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि की भी कोई मजबूत स्थिति नहीं है. इन दलों को कुछ सीटें भी मिल जाएंगी, लेकिन वे सरकार बनाने की स्थिति में कतई नहीं होंगी. इस मामले में मणिपुर में एक अनूठा समीकरण बनता है. यहां सभी राजनीतिक दल कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं. भाजपा और वाम दल भी एक साथ हो जाते हैं. एमपीपी, जो मणिपुर की स्थानीय पार्टी है, उसकी स्थिति भी कमजोर हुई है. अधिकतर स्थानीय पार्टियों के मजबूत दावेदार कांग्रेस और भाजपा में शामिल हो गए हैं. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मणिपुर के चुनाव की स्थिति सत्ता पाने और बचाने के लिए संघर्ष होगी. ■

चुनाव की तिथि तय होने के बाद भी नाकेबंदी वापस नहीं लेंगे : यूएनसी

इधर, चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद यूएनसी ने कहा है कि नेशनल हाईवे से ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा. मणिपुर में नगा बहुल इलाकों में अशांति को दूर किए बिना शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं होगा. यूएनसी के पूर्व अध्यक्ष केएस पोल लियो ने कहा कि नाकेबंदी वापस लेने की अपील राज्य सरकार ने कभी नहीं की है. सरकार की तरफ से राजनीति तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. चुनाव आयोग की तरफ से राज्य में चुनाव की तारीख तय की गई है. हमारे पास आर्थिक नाकेबंदी को और तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में रह रहे नगाओं को उपेक्षा की नजर से देखती है. राज्य में सात नए जिले बनाने में नगाओं की राय नहीं ली गई. अब राज्य के नगा बहुल इलाकों में चुनाव शांति से हो पाएगा, यह प्रशासन के लिए भी चिंता की बात होगी. ■

मणिपुर विधानसभा चुनाव की अनुसूची

	फेज 1	फेज 2
अधिसूचना की तारीख	8.2.2017 (बुधवार)	11.2.2017 (शनिवार)
नामांकन की अंतिम तिथि	15.2.2017 (बुधवार)	18.2.2017 (शनिवार)
नामांकन की जांच	16.2.2017 (गुरुवार)	20.2.2017 (सोमवार)
उम्मीदवारी वापसी लेने की तारीख	18.2.2017 (शनिवार)	22.2.2017 (बुधवार)
चुनाव की तारीख	4.3.2017 (शनिवार)	8.3.2017 (बुधवार)
मतगणना की तारीख	11.3.2017 (शनिवार)	11.3.2017 (शनिवार)
समापन की तिथि	15.3.2017 (बुधवार)	15.3.2017 (बुधवार)

sbijensngh@gmail.com

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

भ्रम और भटकाव में चुनाव

सूफी यायावर

भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए पांच राज्यों में होनेवाला विधानसभा चुनाव किसी अग्नि-परीक्षा से कम नहीं है. इन चुनावों से 2019 के लोकसभा चुनाव का तापमान मिलने वाला है. यही वजह है कि सभी विपक्षी दल और खास कर कांग्रेस किसी भी तरह 2017 के विधानसभा चुनावों में पैवस्त भाजपा के ख्वाब को ध्वस्त करना चाहती है. इसमें सबसे खास है उत्तरप्रदेश का विधानसभा चुनाव, जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जीतने के बाद भाजपा ने यह तय मान लिया था कि विधानसभा चुनाव में तो भाजपा की जीत पक्की है. लेकिन आज लोकसभा चुनाव के समय का राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य नहीं है. आज की स्थितियां बदली हुई और घालमेल से भरी हुई हैं, जिसमें कोई भी दल अपनी जीत का दावा नहीं कर सकता.

उत्तर प्रदेश में भाजपा अपना कोई चुनावी चेहरा तय नहीं कर पाई. लिहाजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे ही वह चुनाव लड़ेगी. प्रधानमंत्री के लिए पांच राज्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश ही है. इसकी मुख्य वजह मोदी का वाराणसी का सांसद होना भी है. इसीलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को आगे कर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है. भाजपा यह मान कर चल रही है कि मोदी के नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले का फायदा विधानसभा चुनावों में मिलेगा, लेकिन विपक्ष इस कोशिश में है कि नोटबंदी के मसले पर ही भाजपा को चित किया जाए. योगी महंत आदित्यनाथ की उपेक्षा का मसला भी भाजपा की जीत की संभावनाओं पर काली छाया की तरह मंडरा रहा है. जिन योगी आदित्यनाथ को पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात की जा रही थी, उन्हें चुनाव समिति तक में शामिल नहीं किया गया, इसे भाजपा नेता ही दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं. भाजपा नेतृत्व ने योगी को प्रत्याशियों के चयन में हिस्सेदारी लेने लायक भी नहीं रहने दिया, जबकि बाहरी दलों से टपके नेताओं को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया. इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है.

उधर, उत्तर प्रदेश में सपा के भीतर जारी पिता-पुत्र कलह से भाजपा और बसपा दोनों ही उम्मीद लगाए हैं कि इस कलह का उन्हें

राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी निर्णायक रूप से कहना मुश्किल है. सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया, तो बसपा को नुकसान होना तय हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विकास का मुद्दा आम लोगों को दो तरफ जरूर खींच रहा है. इसमें बसपा का हाल, उस जीव जैसा हो रहा है, जो दो जीवों के भिड़ंत में गिरने वाले टुकड़े पर ध्यान लगाए बैठा रहता है. समाजवादी पार्टी की टूट से मुस्लिम वोट के संभावित विभाजन पर बसपा ध्यान लगाए बैठी है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का चुनावी भविष्य कहीं से भी दीर्घजीवी नहीं दिखाई दे रहा है. उसकी एकमात्र उम्मीद इसी पर टिकी है कि सपा में होनेवाले विभाजन से मुस्लिम समुदाय का वोट बसपा की झोली में गिर जाए. भाजपा भी यह कयास लगा रही है कि मुस्लिम वोटों का विभाजन उसे फायदा पहुंचा सकता है. मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे का नहीं चुना जाना भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे में अखिलेश यादव की लोकप्रियता भाजपा पर भारी पड़ सकती है.

मुस्लिम वोटों की खींचतान में यूपी की पूरी सियासत उलझी पड़ी है. सारे दल इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि कैसे मुस्लिम वोट हासिल हो. बसपा और कांग्रेस इसे लेकर अधिक आग्रही हैं. अखिलेश खेमे और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाएं बनी हुई हैं. कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होता है, तो बसपा के मंसूबों पर पानी पड़ जाएगा, क्योंकि तब मुस्लिम वोट नहीं बिखेरेगा. अखिलेश यादव खुद भी यह कह चुके हैं कि कांग्रेस से चुनावी गठबंधन हो गया तो गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी. कांग्रेस, सपा के अखिलेश गुट के साथ जाने को अधिक प्राथमिकता दे रही है. उसकी वजह यह भी है कि सपा कांग्रेस के लिए सौ से अधिक सीटें छोड़ सकती है, जबकि मायावती इसके लिए राजी नहीं हुईं. बसपा अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, जबकि कई बड़े दल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासा प्रभाव छोड़ने वाले छोटे दलों को भी अपने साथ लेकर चलने का जतन कर रहे हैं. यह सही भी है कि यूपी में रालोद, पीस पार्टी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम), आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अपना दल, जनता दल (युनाईटेड), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल (सेकुलर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), इत्तेहाद-ए-मिल्लत जैसी छोटी पार्टियां अपनी सीट भले न जीतें, पर दूसरों को हराने की क्षमता जरूर रखती हैं, लिहाजा बड़े दल उनके साथ तालमेल कर चलना चाहते हैं. तभी सपा ने अखिलेश की इच्छा को दरकिनार कर कौमी एकता दल का अपनी पार्टी में विलय कराया और भाजपा ने अपना दल या भारतीय समाज पार्टी के साथ तालमेल बनाया. छोटे दलों के कारण ही पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग दो दर्जन सीटों पर सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक हजार या उससे भी कम वोट से चुनाव हार गए थे. उस चुनाव में रालोद नौ सीटों पर दूसरे स्थान पर, 14 पर तीसरे स्थान और पांच सीटों पर चौथे स्थान पर रहा था. पीस पार्टी तीन सीटों पर दूसरे स्थान पर, आठ सीटों पर तीसरे और 24 सीटों पर चौथे स्थान पर रही थी. इसके अलावा कौमी एकता दल ने एक सीट पर दूसरा स्थान, चार सीटों पर तीसरा और एक सीट पर चौथा स्थान प्राप्त कर कई बड़े दलों के प्रत्याशियों की जीत में बाधा डाल दी थी. 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल ने 76 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे. अपना दल का केवल एक ही प्रत्याशी जीता, लेकिन अपना दल दो सीटों पर दूसरे, सात सीटों पर तीसरे और सात सीटों पर चौथे स्थान पर रहा. इसी तरह कई अन्य छोटे दलों ने भी व्यापक पैमाने पर बड़े दलों के वोट काटे थे. यही कारण है कि कोई भी बड़ा दल इन छोटे दलों की उपेक्षा नहीं कर सकता.■

पर्वतीय प्रदेश में अंतर्विरोधों का पहाड़

उत्तराखंड में भी सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस अपनी सत्ता सलामत रखने के अथक प्रयास में लगी है. मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसी जुगत में हैं कि उनका मुख्यमंत्रित्व कायम रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई सारे अंतर्विरोधों से गुजर रही है. कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में कई समानान्तर ताकतों पर एक साथ जोर-आजमाइश कर रही है. पर्वतीय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दो किशोर आमने-सामने हैं. एक तरफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय तो दूसरी तरफ चर्चित चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर. दो किशोरों के बीच बनी तल्खियों से कांग्रेस के जीत के आकलन पर सीधे सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड में हमेशा दो परस्पर विरोधी स्थितियां बनाए रखीं. मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीच का टशन लगातार सुर्खियों में रहा. अब दो किशोर आमने-सामने हैं, तो हरीश रावत राहत में हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष की तनातनी फरवरी 2014 से ही चल रही है. किशोर गुट कहता है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत संगठन के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं और अपने फैसलों के आगे पार्टी की प्राथमिकताओं को भी नहीं समझते. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के खेमे का कहना है कि किशोर उपाध्याय ही पार्टी के खिलाफ काम करते हैं. इसी कारण 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था. एक निर्दलीय उम्मीदवार से वे चुनाव हार गए थे. कांग्रेस आलाकमान ने अब प्रशांत किशोर (पीके) को विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान सौंपी है. हरीश रावत प्रशांत किशोर की तरफ खड़े हैं. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कांग्रेस के लिए सियासी सलाह देने और बिसात बिछाने का पवित्र कर्म कर रहे हैं. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी अंबिका सोनी मानती हैं कि प्रशांत किशोर पहाड़ी राज्य में कांग्रेस का बेड़ा पार कराने में कारगर साबित होंगे. अंबिका सोनी पंजाब कांग्रेस की प्रचार कमेटी की भी अध्यक्ष हैं. अंबिका सोनी ही सूत्रधार बनी हुई हैं. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली को भी चुनाव पर्यवेक्षक बना कर पर्वतीय कांग्रेसी सियासत में लाकर खोंस दिया है. इसे लेकर भी पहाड़ पर तमाम कानाफूसियां हो रही हैं.

दूसरी तरफ भाजपा भी कई अंतर्विरोधों से गुजर रही है. बड़े व्यक्तित्वों के छोटे-छोटे टकराव भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसी का नतीजा है कि चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन अभी टिकटों को लेकर ही माथापच्ची बनी हुई है. भाजपा आलाकमान को भी एक निर्णय पर आने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. टिकट वितरण की अंदरूनी रार अब सतह पर आ रही है. केवल बसपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. कांग्रेस भी अनिर्णय की स्थिति में है. अपने ऐतिहासिक झगड़े में फंसी समाजवादी पार्टी उत्तराखंड को लेकर भी दो पाटों पर है. उत्तराखंड भाजपा में हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलारानी रावत, सुबोध उनियाल, प्रदीप बत्रा जैसे बड़े बागियों के नाम आलाकमान के लिए विचारणीय हैं. बागियों को टिकट नए सिरे से तनाव और गुटबाजी बढ़ाएगा. इससे उलट कांग्रेस ने घर वापसी करने वालों और बागियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं.■

पांच मुद्दों पर टिका है यह त्रिकोणीय मुक़ाबला

चौथी दुनिया ब्यूरो

हर चुनाव किसी न किसी मुद्दे पर लड़ा जाता है, भले ही वे मुद्दे महत्वपूर्ण हों या महत्वहीन. फिर भी, जब चुनावी रिपोर्ट लिखी जाती है, तो उसमें ऐसे मुद्दों को शामिल किया जाता है, जो सीधे जनता से जुड़े हों. अब, जब पंजाब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तब ऐसे में सभी दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं, अपने-अपने वादे कर चुके हैं, लेकिन ये जानना अधिक जरूरी है कि इन वादों के मुकाबले जनता की असल समस्या क्या है? क्या कोई राजनीतिक दल पंजाब की जनता के असल समस्या के समाधान की बात कर रही है और अगर कर रही है, तो क्या उसके पास इसके लिए कोई प्लान भी है या फिर ये चुनावी वादे, बाद में चुनावी जुमले भर बन कर रह जाएंगे.

सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स व नशे के रैकेट की. पंजाब में भले ही उस स्तर तक नशे का कारोबार न हो, जिस स्तर पर इसे मीडिया या फिल्मों में दिखाया गया है, फिर भी नशा वहां की एक अहम और सबसे बड़ी समस्या जरूर है. पंजाब की ताकत व पहचान उसकी खेती रही है, लेकिन नशे ने उस पहचान पर एक काला धब्बा लगा दिया है. पंजाब आज युवाओं में ड्रग्स की समस्याओं को लेकर खबरों में रहता है. एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के 10 जिलों की कुल 1.23 करोड़ युवा आबादी नशे की गिरफ्त में है. पंजाब में नशे से संबंधित करीब 15 हजार एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. नशे के इस कारोबार के लिए सत्ताधारी शिरोमणी अकाली दल के कुछ नेताओं पर ही आरोप लग रहे हैं. ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने काफी हमलावर तरीके से नशे के मुद्दे को अपना चुनावी शस्त्र बनाया है. भाजपा ने भी कहा है कि अगर वो फिर सत्ता में आती है, तो एक महीने के भीतर नशे पर लगाम लगाएगी. आम आदमी पार्टी ने तो सीधे-सीधे इस कारोबार के लिए अकाली दल के एक कद्दावर नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को जिम्मेदार बताया है. पार्टी ने ये वादा किया है कि सत्ता मिली तो मजीठिया का कॉलर पकड़ कर उसे जेल में डालेंगे. वैसे, इसे आप आम आदमी पार्टी मार्का वादा भी समझ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये पार्टी शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात कहती थी. ये अलग बात है कि सत्ता के दो साल पूरे होने के बाद भी वो अपना वादा पूरा नहीं कर सकी. फिर भी, आम आदमी पार्टी नशे और मजीठिया को लेकर जो वॉर्डो लैंग्वेज पंजाब में दिखा रही है, वो अभी सबसे आक्रामक है. देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की जनता और खास कर युवा वर्ग इस मुद्दे पर किस तरह से रिएक्ट (प्रतिक्रिया) करते हैं.

पंजाब चुनाव कार्यक्रम (117 सीट)

अधिसूचना जारी होने की तिथि	-	11 जनवरी 2017
नामांकन की अंतिम तिथि	-	18 जनवरी 2017
नामांकन की जांच की तिथि	-	19 जनवरी 2017
नामांकन वापस लेने की तिथि	-	21 जनवरी 2017
मतदान की तिथि	-	4 फरवरी 2017
मतगणना की तिथि	-	11 मार्च 2017

पंजाब चुनाव का दूसरा सबसे अहम मुद्दा है दलित मुद्दा. यहां दलित आबादी 32 फीसदी है. जाहिर है, ये आबादी किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़े आकर्षण का केन्द्र है. पंजाब में दलितों पर अत्याचार, नौकरी और उनके जमीन का मसला एक अहम मुद्दा है. जाहिर तौर पर, पंजाब में दलित मुद्दे पर सबसे मुखर अभी आम आदमी पार्टी ही दिख रही है. कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से अभी कोई खास एलान नहीं हुआ है. लेकिन, आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर दलित उपमुख्यमंत्री बनाने की बात जरूर कही है. आप ने दलितों के लिए अलग से घोषणापत्र बनाने की भी बात कही है. पंजाब में एक आम धारणा बनी है कि सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों ने यहां अपना सिक्का जम कर चलाया है. कभी पंजाब आतंक से ग्रस्त था, अभी यहां पर अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है. विपक्षी दल इसके लिए सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. फिलहाल, पंजाब में 5 दर्जन अपराधियों के गैंग हैं. पंजाब से कई बार जेल ब्रेक की खबरें भी आती रही हैं. इसके बाद भी कानून-व्यवस्था की समस्या का बेहतर समाधान देने की दिशा में कोई ठोस घोषणा या योजना का एलान किसी दल की ओर से होता नहीं दिख रहा है.

इसके अलावा, पंजाब के युवा भारत के बाकि हिस्सों की तरह ही भारी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं. 2015 में यहां के रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों के 3,61,299 आवेदन लंबित थे. जाहिर है, ये आंकड़े भी बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत कम युवा ही रोजगार कार्यालय में खुद को पंजीकृत कराते हैं. दूसरी तरफ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, यह आंकड़ा 55 लाख है. इनमें से 72 फीसदी शिक्षित, जबकि 22 फीसदी तकनीकी रूप से कुशल हैं. यहां बेरोजगारी का आंकड़ा करीब-करीब बिहार के बराबर है, जो प्रति हजार 60 है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने युवा वोटरों को रिझाने के लिए यहां नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा तो की है, लेकिन ये अपने इस वादे को कैसे पूरा करेंगे, इसका कोई रोडमैप नहीं दिखा है. आमतौर पर ये माना जाता है कि पंजाब खेती-किसानी में काफी संपन्न है. बहुत हद तक यह बात सही भी है, लेकिन अब पंजाब किसान आत्महत्या के मामले में भी रिकॉर्ड बना रहा है. इसकी वजह भी खेती ही है. कृषि आधारित राज्य होने के बाद भी यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जितनी जरूरत है, उतनी लगाई नहीं जा रही है. किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है. कर्ज अलग से इन्हें परेशान करता है. यहां के किसानों पर बैंकों और देनदारों के 69355 करोड़ रुपये का कर्ज है. मौजूदा राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसानों की हालत सुधार सके. ऐसे में अगर कोई राजनीतिक दल ये घोषणा भी करे कि वो किसानों का कर्ज माफ कर देगी तो ऐसे में सवाल ये है कि इस वादे को पूरा कैसे किया जाएगा.

इधर वादों की झड़ी लगाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है. कांग्रेस ने हर घर में नौकरी, किसानों के कर्ज माफी और चार हफ्ते में नशामुक्त पंजाब का वादा किया है. भाजपा ने भी नशामुक्त राज्य बनाने की बात कही है. आम आदमी पार्टी भी सत्ता पाने के लिए हर एक दांव खेलने से पीछे नहीं हट रही है. इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक रैली में यहां तक बोल दिया कि लोग आम आदमी पार्टी को यही मान कर वोट दें कि वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हैं. हालांकि, सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी होगी कि जो वादे किए जा रहे हैं, उन्हें पूरा किया जाए. वाद में इस पर खुद केजरीवाल ने भी स्पष्टीकरण दिया और यह साफ किया कि वे दिल्ली छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे हैं. बहरहाल, पंजाब चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि क्योंकि यहां अब तक द्विपक्षीय लड़ाई होती रही है, लेकिन इस बार यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. आम आदमी पार्टी एक अहम ताकत के तौर पर मैदान में है और यह अकाली व कांग्रेस दोनों के लिए एक चुनौती बनी हुई है. इस बात को कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणी अकाली दल भी समझ रहे हैं. अकाली दल के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी फैक्टर काम कर रहा है. भाजपा के पास यहां कुछ खास करने को है नहीं. लिहाजा, आप और कांग्रेस के बीच एक जोरदार टक्कर होने की संभावना अधिक है. लेकिन, सवाल अब भी वही है कि चाहे जो जीते, जिसे सत्ता मिले क्या वो जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करेगी, जनता की समस्याओं का समाधान निकालेगी या फिर अपने ही वादों को भूल कर बाद में उसे एक जुमला भर बता कर पल्ला झाड़ लेगी.■

आरएसएस संगठनों को ज़मीन आवंटन पर इतनी हड़बड़ी क्यों

स्कूलों के लिए ज़मीन नहीं, सरकार बांट रही रेवड़ी

चंदन राय

हाल दो घटनाक्रमों पर एक नजर डालते हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 आरएसएस से जुड़े संगठनों को दिल्ली में जमीन आवंटन पर मुहर लगा दी है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया, जब हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है. इतना ही नहीं, यूपीए-वन ने इस जमीन आवंटन के संबंध में अनियमितता की रिपोर्ट मिलने के बाद 2004 में इसे खारिज कर दिया था. सरकार इन संगठनों को जमीन देने के लिए इतनी हड़बड़ी में थी कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा. अब शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू इस सरकारी फैसले की जानकारी देने हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं. लेकिन यही सरकार ऐसे समय तत्पर नजर नहीं आती, जब दिल्ली में स्कूल और अस्पताल खोलने के लिए जमीन आवंटन की मांग की जाती है. तब डीडीए का बयान आता है कि दिल्ली में जगह उपलब्ध नहीं है. ऐसे में दिल्ली सरकार को सरकारी स्कूलों में मोहल्ला अस्पताल खोलना पड़ता है. डीडीए का यही रुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कूड़ा निस्तारण के मामले में जमीन आवंटन को लेकर भी है.

इन दो घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों से आगे बढ़कर भी फैसले लेने को तैयार रहती है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है. अब ये कोई कूढ़ मगज भी बता सकता है कि दिल्ली को स्कूल, अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व कूड़ा निस्तारण जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है या फिर पार्टी समर्थित सोशल, कल्चरल संगठनों के विस्तार की. अब इन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठनों पर भी एक नजर डालते हैं, जिन्हें जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है. इनमें से कुछ संगठन हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास, विश्व संवाद केंद्र, धर्म यात्रा महासंघ और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद इत्यादि. 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इन संगठनों को जमीन आवंटित करने का फैसला किया था. यूपीए सरकार ने 2004 में इन संगठनों के जमीन आवंटन पर रोक लगा दी. यूपीए सरकार ने बताया कि इन संगठनों को मनमाने तरीके से जमीन का आवंटन किया गया था. यह तथ्य एक जांच समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड आईएएस योगेश चंद्रा कर रहे थे. चंद्रा कमिटी ने विभिन्न संगठनों से जुड़े 100 से अधिक जमीन आवंटन के मामलों की जांच की. समिति ने बताया कि 32 जमीन आवंटन के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. जमीन आवंटन में अनियमितता बरते जाने के कारण 29 संगठनों को जमीन का आवंटन नहीं किया जा सका. इस फैसले के विरोध में 23 संगठन हाईकोर्ट पहुंच गए.

नई समिति बनाकर ख़ारिज की रिपोर्ट

मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही इन संगठनों को उम्मीद बंधी कि अब जमीन आवंटन के रास्ते में आ रही बाधाओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा. इन संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल वेंकैया नायडू से मिला. सरकार ने जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर अटार्नी जनरल की सलाह ली. इस सलाह के बाद ही दो सदस्यीय कमिटी बनाए जाने की बात सामने आई. समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार व उनके मातृ संगठन अपनी बातों को जायज ठहरा सकते थे. सरकार ने आनन-फानन में इस मामले की जांच के लिए पिछले साल दो रिटायर्ड सचिवों की एक समिति का गठन कर दिया. रिटायर्ड आईएएस एलके जोशी और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव आर नारायणस्वामी को जांच रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय को सौंपनी थी. समिति को इस बात की भी जांच करने को कहा गया कि यूपीए सरकार द्वारा जमीन आवंटन रद्द किए जाने का फैसला कितना न्यायोचित था. समिति को यह भी बताना था कि क्या तत्कालीन सरकार ने जान-बूझकर इन संगठनों को टारगेट किया था.

समिति ने भी बिना विलंब के एक साल में ही यह फैसला सुना दिया कि अगर एक-दो मामलों को छोड़ दें, तो इन संगठनों को जमीन आवंटन में कोई अनियमितता नहीं बरती गई थी. इतना ही नहीं, समिति ने यह भी कहा कि इन संगठनों के जमीन आवंटन को रद्द करने का फैसला भेदभावपूर्ण था. लिहाजा, सरकार ने जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले को रद्द करने का निर्णय लिया. समिति का फैसला आने के बाद सरकार ने भी देर नहीं की और जमीन आवंटन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तत्क्षण मंजूरी दे दी. अब सरकार के लिए यह जरूरी हो गया था कि दस साल पुराने फैसले को बदले जाने के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट को पैनल रिपोर्ट की सूचना से अवगत कराया जाए, ताकि आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. लिहाजा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी में हैं. इसमें अदालत से आवंटन रद्द किए जाने के फैसले को खारिज करने की अनुमति मांगी जाएगी.

सामाजिक हितों के आड़ में चल रहा धंधा

ऐसे ट्रस्ट और कल्चरल संगठनों को जमीन आवंटन का मकसद सरकार बताती है कि वे संगठन सरकार के ट्रस्टी के तौर पर काम करते हैं और सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, जो सरकार खुद नहीं कर सकती है. इन संगठनों को मार्केट रेट पर ही सब्सिडी नहीं दी जाती, बल्कि पचास साल पुराने बाजार दर पर सब्सिडी दी जाती है. जैसा कि हेमामालिनी को जमीन आवंटन के मामले में किया गया. उन्हें 1976 के मार्केट रेट पर जमीन का आवंटन किया गया. साथ ही उस दर पर भी केवल 25 प्रतिशत चार्ज किया गया. वास्तव में इन संगठनों को जमीन आवंटन का मकसद सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक हितों के आड़ में अपने पोषित संगठनों व अपने लोगों को उपकृत करना होता है.

आप ने भी उठाया मुद्दा

आप सरकार ने आरोप लगाया कि सरकार अपने मातृ संगठनों को राजनीतिक अनुशंसा के आधार पर रियायती दरों पर जमीन बांट रही है. आप के कुछ नेताओं ने इस मसले को डीडीए के इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट कमिटी के सामने भी उठाया. सरकार का कहना है कि इन संगठनों को जमीन आवंटन के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कूड़ा निस्तारण के लिए जब आप सरकार ने जमीन की मांग की, तो डीडीए के वाइस चेयरमैन बलविंदर कुमार ने शहरी विकास मंत्रालय को जानकारी दी कि हमारे पास शहर में बस पार्किंग व कूड़ा निस्तारण के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध नहीं है. बसों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग महंगा तो होगा, लेकिन यही एकमात्र विकल्प है. यह बयान ऐसे समय आया है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए परिवहन मंत्रालय से दस हजार नई बसों के लिए एक डिटेल प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं. वहीं शहर में दस हजार टन रोज निकल रहे कूड़े के निस्तारण के लिए भी अतिरिक्त जमीन की जरूरत है.

ज़मीन की लूट में सभी दल साथ

हरियाणा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को व्यावसायिक और निजी कार्यों के लिए जमीनों का आवंटन किया था. जस्टिस ढींगरा ने अनियमितता के सवाल पर कहा था कि अगर अनियमितताएं नहीं होतीं, तो वे 182 पेज की रिपोर्ट नहीं सौंपते. वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 7.5 करोड़ में जमीन खरीद कर लैंड यूज बदलवा दिया और फिर उसी जमीन को 55 करोड़ में बेच दिया था.

राजस्थान में भी दीनदयाल ट्रस्ट को जमीन आवंटन करने पर निचली अदालत ने हाल में भाजपा व संघ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे. बाद में ट्रस्ट ने जमीन सरकार को लौटा दी थी. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया था. भाजपा की सांसद व अभिनेत्री हेमामालिनी को मुंबई में अंधेरी में डांस एकेडमी खोलने के लिए दो हजार स्क्वायर मीटर जमीन का आवंटन किया गया. 50 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन को महज 70,000 रुपए में राज्य सरकार ने दे दिया. इतना ही नहीं, बोनस के तौर पर 30,000 स्क्वायर मीटर का एक गार्डन भी मेंटेनेस के लिए सौंप दिया गया. यह तय था कि बाद में इस जमीन का इस्तेमाल निजी तौर पर किया जाता और भविष्य में इस पर कंस्ट्रक्शन कर आवंटित जमीन के साथ अटैच कर दिया जाता. मणिपुर में भी भाजपा की नेता व बॉक्सर मैरीकॉम को बॉक्सिंग क्लब खोलने के लिए जमीन का आवंटन किया गया है. भाजपा शासित राज्यों में बाबा रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को जमीन आवंटन का मामला हमेशा सुर्खियों में रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

फैसिलिटीलेस देश कैसे बनेगा कैशलेस

निरंजन मिश्रा

नए साल की शुरुआत आपने जिस भी सपने के साथ की हो, लेकिन एक सपना है, जिसके लिए सरकारी मुनादी है कि उसे पूरा करने में आपका योगदान अनिवार्य है. वह सपना है डिजिटल और कैशलेस इंडिया का. कल तक जेब देखकर खरीददारी करने वाले उपभोक्ता को आज पेमेंट से पहले नेटवर्क और इंटरनेट देखना पड़ रहा है. यह बात अलग है कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की आबादी 35 फीसदी से भी कम है. हालांकि सरकार बिना इंटरनेट के ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध होने का दावा कर रही है. लेकिन हाल में डिजिटल ट्रांजेक्शन में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए सरकारी दावे वाली सुविधा की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है.

पंजाब के जोगिंदर दिल्ली में ऑटो चलाते हैं. 7 जनवरी को कनॉट प्लेस में उनके ऑटो पर तीन सवारियां बैठीं, जिन्हें अक्षरधाम जाना था. पहुंचने पर भाड़े के 250 रुपए के लिए उन लोगों के पास कैश नहीं था, तो उन्होंने पेटीएम किया. उनके मोबाइल पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आया, पैसे कट गए लेकिन वे जोगिंदर के पेटीएम एकाउंट तक नहीं पहुंचे. नेटवर्क की खामी जानकर जोगिंदर और वे सवारियां अक्षरधाम के बाहर एक घंटे तक खड़ी रहीं, लेकिन तब भी पैसे नहीं आ पाए. उनकी तरफ से यह तर्क दिया जा रहा था कि हमारे एकाउंट से तो पैसे कट गए, अब हमारी कोई गलती तो है नहीं. पेटीएम कस्टमर केयर सर्विस में बात करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंत में जोगिंदर को खाली हाथ लौटना पड़ा. हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ मेट्रो शहरों की समस्या है. छोटे शहरों और गांवों में तो डिजिटल इंडिया की स्थिति और भी दयनीय है. उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी देवेंद्र नाथ तिवारी ने कैशलेस भारत की गाड़ी को गति देने के लिए कार्ड पेमेंट का सहारा लिया. देवरिया के वी-मार्ट से खरीदे गए कंबल के लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से पीओएस मशीन के जरिए 3940 रुपए का पेमेंट किया. देवेंद्र के बैंक खाते से तो पैसे कट गए, लेकिन पीओएस मशीन ने पेमेंट डिक्लाइन का मैसेज दिखा दिया. पीओएस मशीन में एक बार और कार्ड स्वाइप किया गया, फिर से उतने ही पैसे कटे, लेकिन फिर पेमेंट डिक्लाइन का मैसेज. बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर सर्विस को फोन करने पर करीब आधे घंटे तक कॉल होल्ड पर रहा, लेकिन किसी से बात ही नहीं हो पाई. देवेंद्र अब भी अपने पैसों को पाने का रास्ता तलाश रहे हैं. आए दिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें लोगों की गाढ़ी कमाई कैशलेस इंडिया में योगदान की भेंट चढ़ती दिख रही है.

कैशलेस की राह में बाधक

भारतीय इंटरनेट बाजार में भले ही मोबाइल कंपनियों ने 4जी का शोर मचा रखा है, लेकिन हकीकत यही है कि यहां आज भी औसत इंटरनेट स्पीड 2जी के समकक्ष ही है. फेसबुक द्वारा हाल में किए गए एक शोध के मुताबिक भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं में से मात्र 13 फीसदी ही असली 3जी और 4जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. आइसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स-2016 की रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 138वां है. मोबाइल नेटवर्क की स्थिति भी कम दयनीय नहीं है.

मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद नेटवर्क एरिया में आने के लिए हाथ ऊपर कर के मोबाइल हिलाते दृश्य आज भी हमारे यहां देखे जा सकते हैं. हाल का एक अध्ययन बताता है कि भारत में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय पेज लोड होने में लगने वाला औसत समय 5.5 सेकेंड है, जबकि चीन में यह समय 2.6 सेकेंड है. हकीकत पर गौर करें तो इन आंकड़ों की सच्चाई में कोई संदेह नहीं है. हालांकि समस्या यहीं तक सीमित नहीं है, उपर्युक्त तो उदाहरण बताने के लिए काफी हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ किस तरह की समस्याएं जुड़ी हुई हैं. हाल यह है कि इन समस्याओं के हल के लिए जिम्मेदार संस्थाएं भी अपना काम नहीं कर रहीं.

कैशलेस इंडिया के सपने में उन्हें भी शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने आज तक बैंक भी नहीं देखा, मोबाइल बैंकिंग या पीओएस मशीन तो दूर की बात है. 20 दिसंबर 2016 को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग के लिए सरकारी बाबू नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बालोद पहुंचे थे. 9 लाख की आबादी में 5 लाख बीपीएल वाला बालोद जिला देश का वह हिस्सा है, जहां की एक बड़ी आबादी दो जून की रोटी का जुगाड़ भी बमुश्किल कर पाती है. आंकड़े बताते हैं कि देश के 93 फीसदी ग्रामीण इलाके बैंकों की पहुंच से दूर हैं. अब सवाल उठता है कि जहां बैंक नहीं पहुंच पाए, वहां ऑनलाइन बैंक कैसे पहुंचेंगे.

जनता कहां जाए

आरबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक 2015-16 में बैंकों ने एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स से जुड़े फ्रॉड के 11,997 मामले दर्ज कराए. ऐसी ठगी का शिकार हुए लोगों में एक बड़ी संख्या उनकी है, जो अब भी अपने पैसों को पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. बैंक ऐसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते देर नहीं लगाते, नतीजतन मामला लंबी न्यायिक प्रक्रिया की भेंट चढ़ जाता है. कहने को तो देश में साइबर थाने भी हैं, लेकिन पूरे देश को मिलाकर उनकी संख्या मात्र 40 है, वह भी आधे से भी कम राज्यों में. बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए 2006 में साइबर अपिलेट ट्राइब्यूनल की भी स्थापना की गई. लेकिन ऐसे मामलों के निष्पादन में इस ट्राइब्यूनल की भूमिका को इस बात से समझा जा सकता है कि 30 जून 2011 के बाद से इसमें जज ही नहीं हैं. यानी बीते साढ़े पांच साल में इस ट्राइब्यूनल ने साइबर अपराध के किसी मामले की सुनवाई ही नहीं की. ऐसे में यह सवाल उठता है कि ऑनलाइन बैंकिंग की ठगी के बाद न्यायालय से आस लगाने वाली जनता अब कहां जाए? ■

डराते हैं ठगी के आंकड़े

फरवरी 2016 में राज्यसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया था कि अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच बैंकिंग फ्रॉड के 12,000 केस दर्ज किए गए. हाल में एसोचैम की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2017 में मोबाइल पेमेंट से ठगी के मामलों में 67 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है. बीते कुछ सालों में डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के आंकड़ों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए हम इस आशंका को नकार भी नहीं सकते. राष्ट्रीय अपराध शाखा के अनुसार 2013 में साइबर क्राइम के 4,356 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,021 हो गया. सीईआरटी-आईएन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में साल 2015 में हर तरह के साइबर अपराध के 49,455 मामले दर्ज हुए थे. भयावह आंकड़ों की यह फेहरिश्त ही कैशलेस इंडिया की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं.

कैशलेस भारत में योगदान के प्रयास जिस तरह से परेशानियां लेकर आ रहे हैं, उसे देखते हुए जेब में बिना कैश रखे कैशलेस ट्रांजेक्शन को टाड़ी करना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है. अब बात ये है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन के समय अगर विकल्प के रूप में कैश रखना पड़े, तो फिर ये किस तरह का कैशलेस. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार भाजपा का रूपान्तरण

बिहार की गैर भाजपाई राजनीति में सेंधमारी की मोदी की रणनीति की झलक तो इस यात्रा के हफ्ते भर के भीतर दिखी. जनता दल (यू) ने सूबे में पूर्ण शराबबंदी को लेकर जनजागरण अभियान के तहत 21 जनवरी को दो करोड़ लोगों की मानव-श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है. भाजपा ने इस कार्यक्रम के समर्थन की ही नहीं, बल्कि इसमें भाग लेने की भी घोषणा की है. क्या यह अनायास है? ऐसा लगता नहीं है. नोटबंदी को लेकर हिन्दी पट्टी के कद्दावर नेता नीतीश कुमार से बिना शर्त मिले समर्थन का यह प्रतिदान हो सकता है.

सुकान्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रकाश पर्व के अवसर पर कोई तीन घंटे का पटना-प्रवास बहुआयामी राजनीतिक संदेश देकर चला गया. इसने सूबे के सत्तारूढ़ महागठबंधन की आंतरिक राजनीति में तो हलचल मचा ही दी, भारतीय जनता पार्टी के भावी नेतृत्व और राजनीति को लेकर भी कई संकेत दिए. हालांकि प्रांतीय भाजपा के संदर्भ में केंद्रीय नेताओं की चिंता या रणनीति के संकेत गत एक साल में कई अवसरों पर मिलते रहे हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी की इस यात्रा के साथ पार्टी की आंतरिक राजनीति में उन संकेतों को बिहार ने जमीन पर उतरते देखा-प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर उनकी विदाई तक.

बिहार की गैर भाजपाई राजनीति में सेंधमारी की मोदी की रणनीति की झलक तो इस यात्रा के हफ्ते भर के भीतर दिखी. जनता दल (यू) ने सूबे में पूर्ण शराबबंदी को लेकर जनजागरण अभियान के तहत 21 जनवरी को दो करोड़ लोगों की मानव-श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है. भाजपा ने इस कार्यक्रम के समर्थन की ही नहीं, बल्कि इसमें भाग लेने की भी घोषणा की है. क्या यह अनायास है? ऐसा लगता नहीं है. नोटबंदी को लेकर हिन्दी पट्टी के कद्दावर नेता नीतीश कुमार से बिना शर्त मिले समर्थन का यह प्रतिदान हो सकता है. यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच विकसित हो रही नई राजनीतिक केमिस्ट्री की झलक हो सकती है. इस नई केमिस्ट्री का अंदाज बिहार की जमीन से लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कर्नाटक की सार्वजनिक सभा के भाषण और उससे पहले भी मिलता रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 दिसम्बर 2015 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन पर अचानक इस्लामाबाद पहुंचने का मामला हो या पाक की जमीन पर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का, नीतीश कुमार उनके साथ रहे. नोटबंदी के सवाल पर तो अन्य विपक्षी दल ही नहीं, महागठबंधन के अपने सहयोगियों से अलग होकर उन्होंने उनका समर्थन किया और अब भी उनके साथ हैं. प्रधानमंत्री ने पटना में शराबबंदी का पुरजोर समर्थन कर और नीतीश कुमार का सार्वजनिक तौर पर अभिनंदन कर इसकी कीमत चुका दी. अब शराबबंदी को लेकर जद(यू) के अभियान में भाजपा के शामिल होने से बहुत कुछ साफ हो रहा है. यह राजनीतिक सच्चाई है कि भाजपा ने बिहार में शराबबंदी का विधानमंडल में खुल कर समर्थन किया था. यह भी सही है कि शराबबंदी से संबंधित पहला विधेयक मार्च 2016 के अंतिम हफ्ते में, जब विधानमंडल में पारित कराया जा रहा था, तब सत्ता पक्ष की इच्छा के अनुरूप विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को शराब नहीं पीने और इससे लोगों को दूर रखने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई थी. यह शपथ भाजपा के सदस्यों ने भी ली थी. हालांकि यह भी सच है कि शराबबंदी के नए कानून के कई प्रावधानों को काले कानून की संज्ञा देकर भाजपा ने अगस्त में सदन का बहिष्कार किया था और विधेयक के खिलाफ राज्यपाल से गुहार लगाई थी. इस मसले पर प्रदेश भाजपा अब भी कड़े तेवर में है, लेकिन प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जिस भाव-भंगिमा के साथ शराबबंदी के लिए नीतीश का अभिनंदन किया और उनके साथ होने की घोषणा की, भाजपा के लिए अब शराबबंदी कानून के समर्थन के सिवाय कोई चारा नहीं बचा.

नरेन्द्र मोदी की इस यात्रा में प्रदेश भाजपा के लिए यह संकेत था कि यहां दल के भीतर नए युग की शुरुआत हो चुकी है. यह मात्र शब्दों में बयां नहीं किया गया, बल्कि आचरण में भी दिखा. पूरे प्रकरण पर नजर ऐसे डालिए. प्रकाश पर्व के सिलसिले में पांच जनवरी को गांधी मैदान के दरबार हॉल में आयोजित मुख्य समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और तख्त हरमिंदर साहिब प्रबंध कमिटी के अध्यक्ष थे. मंच पर बिहार सरकार के किसी मंत्री और बिहार भाजपा के किसी नेता के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई थी. हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) व बिहार सरकार की सहमति से किसी और की भी व्यवस्था की जा सकती थी, पर ऐसा नहीं किया गया. यह तो मंच की व्यवस्था थी. समारोह के बाद प्रधानमंत्री के भोजन का इंतजाम किया गया था. इसमें कोई दो दर्जन लोगों के लिए कुर्सियां लगी थीं और सभी पर आमंत्रितों के नाम थे. यहां प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली से आए मंत्रियों के अलावा बिहार और पंजाब के मुख्यमंत्रियों, लालू प्रसाद के साथ साथ उनके दोनों पुत्रों तेजस्वी प्रसाद यादव और तेजप्रताप यादव, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादल और केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के नाम लिखे थे. हालांकि कुशवाहा इस भोज में मौजूद नहीं हुए और कुर्सी खाली ही रह गई. यहां पर भी प्रदेश भाजपा के किसी नेता के लिए कोई जगह नहीं थी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता डॉ. प्रेम कुमार के लिए, न विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी के लिए. पर, इससे भी महत्वपूर्ण यह रहा कि बिहार में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर ख्यात सुशील कुमार मोदी के साथ-साथ डॉ. प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव सहित इन लोगों के किसी करीबी नेता को एयरपोर्ट पर स्वागत या विदाई का पास तक नहीं दिया गया. ऐसा पास प्रांतीय भाजपा के पदाधिकारी (अध्यक्ष कहना बेहतर होगा) की सहमति से ही जारी होना था. तो क्या सुशील कुमार मोदी या दल के बड़े और पुराने नेताओं को यह मौका नहीं देने का केंद्रीय नेतृत्व का कोई निर्देश था? इसका उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय या केंद्रीय कमिटी के लोग ही दे सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में पार्टी के सूबे के जमे-जमाए और शिखर नेताओं के साथ यह सलूक यदि कोई संकेत देता है तो यह कि नए नेतृत्व को इनकी छाया से पूरी तरह मुक्त करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है. देखना है, यह प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी हो जाती है.

यह नई परिघटना नहीं है और इसका संकेत भी नया नहीं है. विधानसभा चुनावों के बाद से केंद्रीय नेतृत्व अपने आचरण से यह जताता रहा है. विधानसभा चुनावों के तत्काल बाद विधायक दल के नेता के चयन में सुशील कुमार मोदी की रणनीति को झटका लगा था. उस समय सुशील मोदी-मंगल पांडेय की जोड़ी ने नंदकिशोर यादव

को इस पद पर बैठाने की तैयारी कर ली थी. उन दिनों विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी शिकस्त के बावजूद मोदी-मंगल-नंदकिशोर के गुट ने पटना से दिल्ली तक अपनी रणनीति की सफलता के लिए हरसंभव जुगाड़ कर लिया था. हालांकि डॉ. प्रेम कुमार अपनी उम्मीदवारी पर अड़े थे, पर उन्हें भी कोई आश्वासन नहीं था. केंद्रीय नेतृत्व ने अंतिम समय में प्रेम कुमार के दावे को स्वीकार कर स्थापित नेतृत्व को झटका दे दिया. फिर, राज्यसभा चुनाव के वक्त इन नेताओं के मत के विपरीत गोपाल नारायण सिंह को उम्मीदवारी दे दी. कहते हैं, सुशील मोदी ने बिहार से दिल्ली जाने की पूरी तैयारी की थी. केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे बड़ा झटका प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को लेकर सुशील मोदी व उनके समर्थकों को दिया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पिछली फरवरी में ही होना था, पर पंचायत चुनाव व अन्य कई कारणों से यह टलता रहा. हालत यह हो गई थी कि मंगल पांडेय को ही इस पद पर बने रहने की बात अनौपचारिक तौर पर कही जाने लगी, कामकाज भी इसी मिज़ाज से हो रहा था. जब कभी अध्यक्ष के चयन की बात चलती भी थी, तो ऊंची जाति- मुख्यतः भूमिहार मैथिल ब्राह्मण- को इस पर नवाजे जाने की बात चला करती थी. कुछ नाम सामने भी थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व खुल कर कुछ बोल नहीं रहा था और बिहार के प्रभारी भूपेन्द्र यादव की बिहार से प्रेषित नामों पर आपत्ति होती रही. वे यादव मतदाताओं को रिझाने के ख्याल से युवा यादव को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे. कहते हैं, नित्यानंद उनकी ही पसंद हैं. अर्थात केंद्रीय नेतृत्व ने बिहारी नेताओं की नहीं, प्रभारी पर ज्यादा भरोसा किया, जो उसका ही प्रतिनिधि होता है. मोदी-युग के अंत की यह ठोस अभिव्यक्ति थी और अब यह ताज़ा उदाहरण उससे भी बड़ा संकेत है. हालांकि कह सकते हैं कि राजनीति में जिस तरह कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, उसी तरह कोई स्थिति स्थायी नहीं होती. जब तक सांस, तब तक आस.

भाजपा के नेतृत्व और इस वजह से राजनीति में बदलाव पार्टी के लिए कैसा रहेगा, यह कहना कठिन है. अभी यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इससे भाजपा के नए समर्थक सामाजिक समूहों के मानस पर क्या असर पड़ेगा. यह एक तथ्य है कि कोई दो-ढाई दशक पहले तक भाजपा (जनसंघ के समय से ही) को जिस सामाजिक समूह का समर्थन था, आज वह पीछे है. कांग्रेस के निरंतर क्षरण के कारण सूबे की कांग्रेस समर्थक अगड़ी जातियों में भाजपा निरन्तर मजबूत होती गई. हालांकि यह विकल्पहीनता का ही परिणाम रहा है, पर बिहार का अगड़ा मतदाता कमोबेश भाजपा के साथ है. पिछले विधानसभा चुनाव के पहले तक तो यह आक्रामक रूप से मतदान केंद्र पर भाजपा के साथ था. हालांकि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर भी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की तरह पिछड़ावादी होने का आरोप लगता रहा और अपने आचरण से वह इसे दिखाता भी रहा. फिर भी, सूबे के अगड़े सामाजिक समूहों की यह सहज शरणस्थली रही. इसका एक कारण इसका उत्कट लालू विरोध रहा. इसकी समावेशी रणनीति भी कम महत्वपूर्ण कारण नहीं रही. कैलाशपति मिश्र, ताराकान्त झा, लालमुनि चौबे जैसों ने संगठन में सामाजिक समूहों के लिए समावेशी रणनीति अपनाई थी, वह उसी तरह बरकरार नहीं रही. पर सुशील कुमार मोदी ने उसे थोड़े बदलाव के साथ अपनाया. मोदी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा में कुछ बड़े पद, जिनमें पार्टी अध्यक्ष का पद भी शामिल है, अगड़ों के लिए ही रहते रहे. हालांकि, संगठन (और जब सरकार में रही तो वहां भी) महत्वपूर्ण व निर्णायक पदों को अगड़ों से मुक्त रखने की हसरत चेष्टा रहती थी. न बनने पर ही कोई ऐसा पद अगड़ों को मिलता था. ऐसी रणनीति के कारण बिहार के अगड़ों को बांध रखने में सुशील कुमार मोदी को कुछ हद तक सफलता मिलती रही. इस बार यह पहला मौका है कि अगड़े सामाजिक समूहों को भाजपा ने कोई पद नहीं दिया है. पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष का नेता पद पिछड़े समुदाय को है, तो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता पद अति पिछड़ा समुदाय को. अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद में सभापति हैं. पर वह पद भाजपा की नहीं, एनडीए की देन है. सो, बिहार भाजपा का रूपान्तरण हो रहा है. यह रूपान्तरण पार्टी को क्या देता या क्या लेता है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल सभी छोटे-बड़े नेता दिल थाम कर आनेवाले दौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

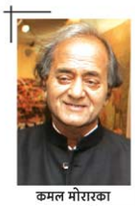

कमल मोरारका

सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीमा समझनी चाहिए

भाजपा की पहली परीक्षा विमुद्रीकरण पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल की हैसियत से उत्तर प्रदेश में है. वे ऐसी धारणा पैदा कर रहे हैं, जैसे बीएसपी और समाजवादी पार्टी धोखेबाजों की पार्टी है, केवल वे ही (भाजपा) निष्पाप, निष्कलंक हैं. मुझे नहीं लगता है कि लोग उनकी इस धारणा पर विश्वास करेंगे. भाजपा के लिए एक चेतावनी वाला संदेश यह है कि हर किसी को चोर कहना समझदारी नहीं है. खुद उनकी पार्टी के लोगों पर भी आरोप है. मोदी भले ही साफ छवि के हों, लेकिन मैं देश के अलग-अलग राज्यों में भाजपा के लोगों से मिला हूं. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे कांग्रेस के नेता से कहीं से भी कमतर नहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी में ये फैशन बन गया है कि देश की हर गलत चीज का आरोप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के ऊपर लगा दिया जाए. इससे कोई फायदा नहीं होगा. ये समय बताएगा कि मनमोहन सिंह का दस साल का कार्यकाल, मौजूदा सरकार के कार्यकाल से बेहतर था. मीडिया ही इस बात की तस्दीक करेगा.

पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसमें चुनाव और चुनाव नतीजे जारी करने की तारीख इंगित की गई है. समाजवादी पार्टी में चल रहे अंतर्कलह के कारण उत्तर प्रदेश की और लोगों का अधिक ध्यान है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में यह होता रहता है. असल मुद्दा यह है कि विमुद्रीकरण की वजह से 8 नवम्बर को अचानक लागू इस अनपेक्षित, अघोषित घोषणा से देश में उथल-पुथल मच गया. यह उथल-पुथल दो कारणों से था. पहला, पुराने नोटों का नए नोटों से तुरंत नहीं बदला जाना, अक्षम्य है. विमुद्रीकरण अच्छा था या बुरा, यह सरकार का फैसला है. इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह भी सरकार की परेशानी है, लेकिन किसी आम आदमी को उसके नोटों के बदले में नए नोट ज़रूर मिलने चाहिए. उसके पास प्रोमिसरी (प्रतिज्ञात्मक) नोटस हैं, जिस पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर है और आप उसके बदले नए नोट नहीं दे रहे हैं, यह बहुत खतरनाक बात है. इससे लोगों का मुद्रा में विश्वास समाप्त हो जाएगा. सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है. विपक्ष के विरोध करने पर यह कहकर उसकी जुबान पर ताला लगा दिया गया कि केवल वही लोग इस क़दम का विरोध कर रहे हैं, जिनके पास काला धन है. यहां काला और सफ़ेद का सवाल नहीं है. नोटों के ऊपर यह नहीं लिखा हुआ है कि पैसा सफ़ेद है या काला. सवाल यह है कि नोट के बदले मुझे नए नोट अवश्य मिलने चाहिए. यह मेरा फैसला होगा कि मैं उसे बैंक में रखूं या नहीं रखूं. आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते.

जब लम्बी लाइनें लगने लगीं और लोग मरने लगे, तो उन्होंने अपना सुर अचानक बदल दिया. अब यह कहने के बजाय कि यह क़दम काला धन, नक़ली नोट और आतंकवाद समाप्त करने के लिए उठाया गया है, यह कहा जाने लगा कि हम कैशलेस अर्थव्यवस्था या लेस कैश अर्थव्यवस्था की आदत डलवाना चाहते हैं. यह बेढंगी बातें हैं. यहां तक कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, वह जानता है कि यह गलत है. गांवों को भूल जाइए, मुंबई जैसे शहर में जो अत्याधुनिक शहर है, वहां कितने लोग मुद्रा के लिए प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको चुनौती दे सकता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के अतिरिक्त कोई भी प्लास्टिक कार्ड व्यापार में विश्वास नहीं करता. एक किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति कैश में विश्वास करता है. यहां तक कि उच्च वर्ग से संबंध रखने वाली गृहिणी भी कैश में विश्वास रखती है और कैश कालाधन नहीं है. अब लोगों को यह शिक्षा देनी ज़रूरी है कि कालाधन देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है.

मुझे यह कहना पसंद नहीं है, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि कालाधन और भ्रष्टाचार पर दिया जाने वाला जोर समाप्त होना चाहिए. जोर विकास पर होना चाहिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास पर होना चाहिए, जिस नारे के साथ नरेन्द्र मोदी चुन कर आए थे. कृपया आप उस पटरी पर वापस आइए. आप पटरी से उतर गए हैं. आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं. आपने ऐसी धारणा पैदा कर रखी है, जैसे सारे अमीर लोग मुसीबत में हैं, इसलिए गरीब लोग खुश हैं. आप जानते हैं कि यह गलत है. अमीरों को इस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क गरीबों पर पड़ने वाला है, जो केवल करेंसी नोट के रंग को पहचानते हैं, वो प्रभावित होंगे. मुझे यहां मीडिया के खिलाफ बोलना पड़ेगा. मीडिया को अब मैनेज किया जा सकता है. मीडिया अब लोगों की राय नहीं छाप रहा है. मीडिया यह मत तैयार कर रहा है कि विमुद्रीकरण का फायदा लॉन्ग रन में होगा. यह लॉन्ग रन क्या है? सरकार के पास तो केवल पांच साल का समय है. मोदी जी, पांच में से ढाई साल निकल गए. लॉन्ग रन क्या है? मान लिया जाय कि इसका फायदा पचास साल के बाद मिलता है, तो फिर आप अभी ये क्यों कर रहे हैं? क्या आपने 100 साल के लिए इस देश का ठेका ले रखा है? यह हास्यास्पद है. यह एक राजनैतिक विमर्श नहीं है. यह नहीं होना चाहिए.

लेकिन जो हो गया, वो हो गया. अब जीडीपी या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. इसका संबंध विमुद्रीकरण से नहीं है. अगर मान लिया जाए कि जीडीपी दो अंक नीचे चला जाता है, तो विपक्ष कहेगा

> **मैं समझ सकता हूं कि मोदी कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते होंगे और कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश कर रही होगी. यह ठीक है. यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि हमारी सीमाएं क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? जो काम लोगों को खुद अपने मूल्यों और समझ के हिसाब से करना है, उसे आप कानून द्वारा जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट यही करने की कोशिश कर रहा है. यह भारतीय लोकतंत्र का एक दुखद उदाहरण है.**

कि विमुद्रीकरण की वजह से हुआ है और सरकार कहेगी कि इसके दूसरे कारण हैं. अगर जीडीपी दो अंक ऊपर जाता है, तो सरकार कहेगी कि विमुद्रीकरण की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि विपक्ष कोई और कारण बताएगा. यह एक कभी न समाप्त होने वाली बहस है. एक देश, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जहां का लोकतंत्र 70 साल पुराना है, वहां हर फैसले पर बहस करना मूर्खतापूर्ण है. इसको यहीं छोड़ते हैं और इसके अपने स्वाभाविक अंजाम तक पहुंचने देते हैं.

भाजपा की पहली परीक्षा विमुद्रीकरण पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल की हैसियत से उत्तर प्रदेश में है. वे ऐसी धारणा पैदा कर रहे हैं, जैसे बीएसपी और समाजवादी पार्टी धोखेबाजों की पार्टी है, केवल वे ही (भाजपा) निष्पाप, निष्कलंक हैं. मुझे नहीं लगता है कि लोग उनकी इस धारणा पर विश्वास करेंगे. भाजपा के लिए एक चेतावनी वाला संदेश यह है कि हर किसी को चोर कहना समझदारी नहीं है. खुद उनकी पार्टी के लोगों पर भी आरोप है. मोदी भले ही साफ छवि के हों, लेकिन मैं देश के अलग-अलग राज्यों में भाजपा के लोगों से मिला हूं. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे कांग्रेस के नेता से कहीं से भी कमतर नहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी में ये फैशन बन गया है कि देश की हर गलत चीज का आरोप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के ऊपर लगा दिया जाए. इससे कोई फायदा नहीं होगा. ये समय बताएगा कि मनमोहन सिंह का दस साल का कार्यकाल, मौजूदा सरकार के कार्यकाल से बेहतर था. मीडिया ही इस बात की तस्दीक करेगा.

दूसरा अहम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविजम (अति सक्रियता) है. सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सुधार की जरूरत है. मैं जजों की नियुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसलों में निरंतरता का अभाव है. अति दुर्लभ मामले, जिसमें हत्या के आरोपी को मौत की सजा दी जाती है, इसमें भी अलग-अलग जज अति दुर्लभ मामलों की पहचान अलग-अलग तरीकों से करते हैं. मुझे नहीं मालूम कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही मनमाना, अतार्किक और व्यक्तिगत होता है. न्याय की भावना का अभाव है. हाल के दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा. पहला, सहारा प्रमुख सुब्रत राय को दो साल तक जेल में रखना है. यह बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वे मेरे मित्र हैं. वे मेरे मित्र नहीं हैं. सवाल ये है कि आपको कानून के शासन का पालन करना चाहिए. आपने उन्हें बिना आरोप पत्र के ही जेल में डाल दिया है. जब उनके वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो उनसे कहा गया कि अदालत ने उन्हें अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, सजा नहीं दी है. क्या सुप्रीम कोर्ट एक थानेदार बन गया है?

वीसीसीआई का मामला है. ईर्ष्या अलग चीज़ है. एक व्यक्ति की दूसरे के प्रति ईर्ष्या को मैं समझ सकता हूं, जो अरुण जेटली, राजीव शुक्ला या किसी और व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को न्यायोचित होना चाहिए. इस मामले को ईर्ष्यालु व्यक्तियों को आपस में सुलझा लेने देना चाहिए, जैसे कि राजनीति में होता है. सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति गठित की और लोढ़ा समिति किसी का पक्ष ले रही है. सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले यह जांच करनी चाहिए कि इस संबंध में जो याचिका दायर की गई है, उसे फाइनेंस कौन कर रहा है. वो महोदय, जिनका नाम वर्मा है, जिन्होंने याचिका दायर की है, उनके वकीलों की फीस कौन अदा कर रहा है? क्या कोई ललित मोदी या कोई विजय माल्या? सुप्रीम कोर्ट को यहीं याचिका ख़ारिज कर देनी चाहिए कि वो बेनामी केस की सुनवाई नहीं करता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केस की सुनवाई की, बल्कि लोढ़ा समिति ने ऐसे सुझाव दिए हैं, जिसके मुताबिक वीसीसीआई को प्लेट में सजाकर कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया जाएगा. अगर आप कहते हैं, मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं, तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की तरह कोई व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष और धांधली रहित हो सकें. लेकिन इस चीज़ को खत्म करने के लिए आप एक राज्य, एक वोट की व्यवस्था करना चाहते हैं. सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा सभी के पास एक वोट होगा. इन राज्यों में कोई भी शिकारी उद्यमी जाएगा, उनका वोट खरीदेगा और आने वाले समय के लिए बीसीसीआई को अपने पॉकेट में रख लेगा. क्या यही सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है? जस्टिस ठाकुर, जो अब रिटायर हो गए हैं, वो जस्टिस लोढ़ा के ऋणी हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस लोढ़ा उनसे सीनियर हैं. लेकिन जस्टिस लोढ़ा ने जो किया, उसमें क्रिकेट का अहित है, क्रिकेट प्रशासन का अहित है, कानून के शासन का अहित है. मैं आशा करता हूं कि जस्टिस खेहर, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, मामले की समीक्षा करेंगे. यह बिल्कुल ठीक है, यदि आप कहें कि यदि कोई 9 साल तक लगातार अपने पद पर रहता है, तो उसे ब्रेक लेना चाहिए. इसमें कोई बुराई नहीं है. 70 वर्ष की शर्त भी गलत है. 70 साल के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है और क्रिकेट के लिए उसके पास समय रहता है. उसे पद संभालने दीजिए. दुनिया भर में खेल संस्थाओं के प्रमुख 80 वर्ष की आयु तक होते हैं.

एक राज्य, एक वोट भारतीय क्रिकेट की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए खतरनाक मालूम पड़ती है. एक और जजमेंट आया है. सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के पहले खड़ा होने को लेकर. आप कैसे इस आदेश का क्रियान्वयन करवाएंगे? भाजपा के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक खुद मुख्तार बन जाएंगे. यह फासीवाद है. यह काम नहीं करेगा. अब 30 लाख एनजीओ ने अपने खाते की जानकारी नहीं दी है. अब इसके ऑडिट का आदेश दिया गया है. कौन ऑडिट करेगा इन 30 लाख खातों को? ऐसे ऑडिट की गुणवत्ता क्या होगी? कम से कम एक कट ऑफ प्वाइंट होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा भी है. वो जो भी बोलते हैं, वो कानून होता है. आज मैंने एक बहुत ही हास्यास्पद खबर पढ़ी. सुप्रीम कोर्ट ने बिड़ला सहारा डायरी केस की जांच करवाने से मना कर दिया है, जिसमें नेताओं के नाम आए हैं. इस केस को खारिज कर दिया है. फिर, हवाला डायरी क्या थी? वह सीबीआई द्वारा जब्त की गई थी, यह आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई है. हवाला डायरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, चार्जशीट फाइल हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पर्याप्त सबूत नहीं है. ये क्या है? इस तरह से तो देश नहीं चलेगा. ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन आएगा, जब इस देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करना बंद कर देंगे. क्रिकेट एक कम महत्व की चीज है. भारत इसमें बेहतर कर रहा है. आपको इसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? अगर किसी ने इसमें गलत पैसा लगाया है तो कानून अपना काम करेगी, आपको हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? हमलोग बहुत ही गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस सरकार की उन संवैधानिक मूल्यों को बदलने में सहायता कर रही है, जो पिछले 70 सालों से सही साबित होती आ रही है. मैं समझ सकता हूं कि मोदी कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते होंगे और कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश कर रही होगी. यह ठीक है. यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि हमारी सीमाएं क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? जो काम लोगों को खुद अपने मूल्यों और समझ के हिसाब से करना है, उसे आप कानून द्वारा जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट यही करने की कोशिश कर रहा है. यह भारतीय लोकतंत्र का एक दुखद उदाहरण है. जितनी जल्दी ये सब खत्म हो, उतना अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पिछले साल के हालात से सबक़ लेने की ज़रूरत

शुजात बुखारी

पिछला साल जाते-जाते अपने पीछे मौत, अंधेपन, निराशा और विवशता की एक लंबी दास्तान छोड़ गया है. इस साल के दौरान कश्मीर में उथल-पुथल रहा. हमारे दिल और जुबान पर ये घटनाओं इस कदर हावी रहीं कि कई बार ऐसा लगा कि दिल-दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है. बुरहान वानी की अचानक मौत के बाद 8 जुलाई से यहां के हालात हिंसक हो गए. इस घटना से लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं. यह स्थिति रातों रात पैदा नहीं हुई, बल्कि इसके लिए कई दशक पूर्व से बीज बोए जाते रहे हैं. लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर यहां असुरक्षा का माहौल बनाया, यह स्थिति भी यहां के निवासियों के लिए कोई नई बात नहीं थी. मार्च 2015 में जब पीडीपी के संरक्षक मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया, तब उनका एकमात्र दावा यह था कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो उस स्थिति में जम्मू क्षेत्र सरकार से बाहर रह जाता. इससे राज्य की अखंडता को खतरा हो सकता था. हालांकि उनके इंतेकाल के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती पहले कुछ महीनों तक सरकार का बोझ उठाने से इन्कार करती रहीं, लेकिन अंत में उन्हें भी इसी लाइन पर क़दम रखना पड़ा.

हालांकि खुद मरहूम मुफ्ती ने दस महीने तक शासन किया, इस दौरान भी कुछ अधिक नहीं बदला. जिस जम्मू क्षेत्र को उन्होंने साथ लेकर चलने का संकल्प किया था, वह कश्मीर से और दूर होता चला गया. शायद इस दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू की जनता दोनों ने मुफ्ती की दो क्षेत्रों को जोड़ने की इच्छा और कोशिश का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. ये दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र नज़दीक आने के बजाए एक-दूसरे से दूर होते चले गये. इतना ही नहीं, मुफ्ती सईद की ख्वाहिश के उलट भाजपा ने अपना तथ्युदा पार्टी एजेंडा अपनाकर राज्य को तोड़ने की कोशिशें जारी रखीं. भाजपा ने अदालतों का रुख़ किया और राज्य के विशेष दर्जे को चैलेंज किया. भाजपा की ओर से कई विवादित प्रस्ताव भी पेश किए गए, जिनमें पूर्व सैनिकों के लिए अलग कॉलोनियों का निर्माण करना, कश्मीरी पंडितों के लिए अलग बस्तियां बसाना और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए राज्य का निवासी होने का प्रमाणपत्र जारी करना आदि. यह एजेंडा ऑफ एलायंस के बजाय अपने पार्टी एजेंडे पर अमल करने पर ही अड़े रहे. एजेंडा ऑफ एलायंस में शामिल केवल तीन विषयों पर ध्यान दिया गया, जिनका संबंध जम्मू या गैर-मुस्लिमों के पक्ष में जाता था, यानी शरणार्थियों को राज्य का निवासी बनाना, पंडितों के लिए अलग कॉलोनियों का निर्माण करना और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पलायन करने वालों को बसाना.

महबूबा के सामने चुनौतियां

अब जबकि एक लंबे और भीषण तूफान के बाद कश्मीर धीरे-धीरे शांति की ओर लौट रहा है, तो सवाल पैदा होता है कि इस माहौल को किस प्रकार से स्थापित किया जाए? यह ख्वाब जनता को हालात बिगाड़ने के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के बजाय केवल और केवल राजनीतिक समस्याएं पैदा करते हैं, न कि उनका हल ढूंढते हैं. हालांकि पृथकतावादियों का नज़रिया उनके नज़रिये से काफ़ी दूर और अलग है. पीडीपी और एनसी, दोनों ने इसे बेदिली से अपना रखा है और वे इसे अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं. एक ओर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आंतरिक संप्रभुता के स्टैंड पर क़ायम है, दूसरी ओर पीडीपी भी भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बावजूद अपने मूल रुख़ 'सेल्फ रूल' से पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है. हकीकत यह है कि 'एजेंडा ऑफ एलायंस' में बहुत सारी ऐसी बातें शामिल हैं, जिनको सामने रखने से दोनों पार्टियों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि कश्मीर की राजनीतिक समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए. इनमें हुर्रियत लीडरों के साथ वार्ता का आग़ाज़, राज्य में लागू विशेष क़ानूनों का खात्मा और सेना की वापसी ऐसे तीन बड़े बिन्दु हैं, जिन पर भाजपा और पीडीपी के बीच सत्ता संभालने से पूर्व आपसी सहमति हुई है. इसको लेकर पीडीपी की यह धारणा काफी नहीं है कि जो हालात 8 जुलाई के बाद पैदा हुए, उनमें इसे लेकर कोई प्रगति संभव न थी, बल्कि एक माकूल सवाल उनसे यह पूछा जा सकता है कि इस तारीख़ से पूर्व इस संबंध में कौन सी और कितनी प्रगति हुई थी? इसके उलट भाजपा ने हर वह काम किया, जिससे श्रीनगर और नई दिल्ली के बीच फासले और बढ़ गए. महबूबा मुफ्ती का नए साल का एजेंडा इसी 'एजेंडा ऑफ एलायंस' को आगे बढ़ाना होना चाहिए, जिसके लागू होने के बारे में पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ सुना गया.

हुर्रियत में नेतृत्व की समस्या

यह सरासर नाइंसाफी होगी कि संयुक्त हुर्रियत नेतृत्व को 6 महीनों में होने वाली तमाम घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार क़रार दिया जाए. हमने उनसे निरंतर हड़तालों का मामला उठाया, हालांकि जवाब देर से ही मिला, लेकिन उन्हें इस बात का अहसास ज़रूर हुआ. दरअसल, घाटी में हालात उनके काबू से बाहर हो गए थे और वे बेबस थे. वर्ष 2017 में उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वे फिर ऐसे हालात पैदा न होने दें, जिनसे उन्हें पिछले वर्ष जैसी स्थिति से दो-चार होना पड़े. जनता ने बिना देर किए इनकी अपील और प्रोग्रामों पर हुंकार भरी है और उन पर अमल भी किया है. इस वर्ष उनका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वे एक ऐसी व्यवस्था या प्रोग्राम बनाएं, जो खुद को विपत्ति में डालने वाला न हो. विरोध-प्रदर्शन करने के हक़ का इस तरह से इस्तेमाल करना होगा, जिससे किसी निर्दोष की मौत न हो या किसी निर्दोष को बिना पर्याप्त कारणों के जेल में ठूंसने का मौक़ा न मिले. नई दिल्ली में भाजपा सरकार की ओर से हुर्रियत को नज़रअंदाज करने की निरंतर कोशिशों की वजह से यह समस्या और जटिल हो जाती है. हुर्रियत को अप्रभावी बनाने की कोशिशें के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो जनता के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. संयुक्त हुर्रियत नेतृत्व को वार्ता से दूर नहीं भागना चाहिए. जिस प्रकार उन्होंने घाटी में निजी तौर पर गए समूह, जिसका नेतृत्व पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा कर रहे थे, के साथ बात की, उन्हें सरकार की ओर से आने वाले किसी निमंत्रण का भी इसी प्रकार माकूल जवाब देना चाहिए. सबने देखा कि यह एक अच्छा फैसला था. इस प्रकार से दुनिया को एक संदेश भी मिला कि हुर्रियत नेतृत्व को वार्ता से कोई परहेज़ नहीं है. जहां तक दिल्ली वालों का सवाल है, वह मार्च तक कश्मीरियों को नज़रअंदाज़ करने का सिलसिला किसी भी कीमत पर जारी रखेगी, जब तक भारत के पांच राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती. लिहाज़ा विरोध-प्रदर्शन को अपना मकसद हासिल करने का हथियार बनाने की बजाय कश्मीरी नेतृत्व को चाहिए कि वह राजनीति का भी इस्तेमाल करे.

सिविल सोसायटी

जब सरकार, हुर्रियत और विपक्ष अपनी अलग-अलग राजनीति कर रहे हैं, तब स्थानीय सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह कुछ गंभीर बिन्दुओं पर आपसी सहमति पैदा करने की कोशिश करे. हालांकि 'सिविल सोसायटी' शब्द का यहां नकारात्मक अंदाज़ में प्रयोग किया गया है, लेकिन यह इतनी प्रभावशाली पहले कभी नहीं थी, जितनी कि पिछले कुछ वर्षों में बनी है. ऐसी कुछ समस्याएं, जिनकी वजह से कश्मीर में अतीत में विरोधाभास रहा है, को सिविल सोसाइटी ने बेहतर अंदाज में उठाया है. अब ज़रूरत इस बात की है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए जन सहमति कैसे पैदा की जाए. ऐसी कम ही समस्याएं होंगी, जिनका संबंध राजनीति के साथ नहीं होगा. लिहाज़ा विवादों और मुश्किल दौर में सिविल सोसायटी को एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की सर्वाधिक जरूरत होती है. ऐसे में बहस के लिए जगह बनाना, उसकी पहली ज़िम्मेदारी बन जाती है. कश्मीरियों की एक बात बहुत बुरी है कि वह खुद को असमंजस के ऐसे जालों में लपेट लेती है, जो इन तत्वों की ओर से बुने जा रहे होते हैं, जिनके अपने तुच्छ स्वार्थ इसके साथ जुड़े होते हैं. इन्हीं हालातों में सिविल सोसायटी का हस्तक्षेप बेहद ज़रूरी बन जाता है. लिहाज़ा पिछले कुछ वर्षों के दौरान कश्मीर की सिविल सोसायटी ने ऐसा किया है और सिविल सोसाइटी के सदस्य हालिया विरोध-प्रदर्शन के दौरान डब्ल्यूपीआर और शरणार्थियों और संपत्ति के हस्तानांतरण से संबंधित कानून 2002 के मामले में हस्तक्षेप किया. ये कानून राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करते हैं. इन कोशिशों को जारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में ऐसी समस्याएं और जटिल हो जाती हैं और विवाद अधिक बढ़ जाते हैं. अब जबकि हम एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस बहस के बीच कि पिछले साल राजनीतिक तौर पर किसका बोलबाला था, यह बात साफ है कि इस साल जो घाव लगे हैं, वो इतनी जल्दी भर नहीं पाएंगे. जनता एक ऐसे भविष्य की ज़रूर आस लगाए बैठी है, जो उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने का दावा करती हो. यह सपना कैसे साकार होगा, यह देखना उन लोगों का काम है, जो यह दावा करते हैं. नेताओं को चाहिए कि वह इस दिशा में प्रतिनिधित्व करें और जनता को एक सम्मानजनक जीवन देने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जो सवाल पूछेगा देशद्रोही मान लिया जाएगा

एक अद्भुत बाज़ीगरी पूरे देश के साथ हुई है. जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय पहले आडवाणी ने, फिर बाबा रामदेव ने और आखिर में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों से कहा कि विदेशों में इतना कालाधन जमा है, जिसे अगर हिन्दुस्तान ले आया जाए, तो हर व्यक्ति के खाते में 15 से 20 लाख रुपए जमा हो जाएगा. देश को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लोकसभा चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी ने रैलियों में यह खुलकर कहा कि अच्छे दिन आएंगे. उन्होंने पक्का वादा किया कि हम काला धन, जो विदेशी बैंकों में जमा है, उसे भारत लेकर आएंगे और हरेक के खाते में 15 से 20 लाख रुपए पहुंच जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में मौजूदा केंद्र सरकार यानी कांग्रेस की सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है. वह लाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसके संपर्क और निजी संबंधियों का पैसा ही विदेशों में जमा है, लेकिन हम इसे लेकर आएंगे. देश के लोगों ने इस बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया. उन्होंने नरेन्द्र मोदी में एक नया चेहरा देखा. उन्होंने ये मानने से इंकार कर दिया कि यह वादा झूठा भी हो सकता है, चुनाव प्रचार भी सकता है, वोट लेने के लिए लोगों को बरगलाना भी हो सकता है. सरकार बनने के बाद जब लोगों ने 15 या 20 लाख रुपए, जो चुनाव के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को देने की घोषणा की गई थी, तलाशने शुरू किए, तब पहली बार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह तो एक चुनावी जुमला था. मतलब चुनाव में हम जो कहेंगे या हमने जो कहा है, वह झूठ है. वो पूरा होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसके बाद ताबड़तोड़ 50 से ज्यादा घोषणाएं हुईं. देश के सामने एक नया नक्शा रखा गया. सत्ता में आने के ढाई साल बाद 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने कालाधन के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि हम 500 और हज़ार रुपए की सारी करंसी बंद करते हैं, ताकि आतंकवाद और कालाधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला पैसा जहां है, वहीं समाप्त हो जाए. हम नई करंसी लेकर आएंगे, जिसे बदलना है, वह तीन महीने के भीतर बदल ले.

इसके बाद शुरू हुआ भारत सरकार का अनिश्चय का खेल. हर रोज़ नियम बदले गए, हर रोज़ लोग कंफ्यूजन में रहे. लोग अपना ही पैसा बदलवाने के लिए बैंकों में लाइनों में खड़े हुए और फिर यह घोषणा की गई कि देखा, कालाधन रखने वाले लोग लाइनों में खड़े हैं. आज माहौल ऐसा बन गया है कि 125 करोड़ लोगों के देश में हर व्यक्ति चोर है. बैंक में कोई भी दस हज़ार रुपए लेकर जाए तो बैंक का अधिकारी पूछता है कि ये पैसे कहां से लाए. जो पांच लाख रुपए लेकर जाए, वो तो जा ही नहीं सकता है. वो सोचता है कि 20-20 हज़ार या 5-5 हज़ार के टुकड़ों में अपनी मेहनत का पैसा कैसे हम बैंक में जमा करें, निकालने पर तो सरकार ने रोक लगा दी. पहले चार हज़ार, फिर 2 हज़ार, फिर 24 हज़ार, फिर 49 हज़ार इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं यानी अपना खुद का कमाया हुआ मेहनत का पैसा, पीढ़ियों से बचाया हुआ पैसा, हमने बैंक में रखा है, लेकिन हम निकालने जाएंगे तो हम नहीं निकाल सकते हैं. सरकार ने उस पैसे के ऊपर क़ब्ज़ा कर लिया है और अब पैसा निकालकर हम किसको देते हैं, इसकी जानकारी हम सरकार को दें. सरकार को अगर नहीं देंगे तो हमारा पैसा ज़ब्त हो सकता है, ये माहौल सरकार ने बना दिया है. अब तक पिछले 70 सालों से इस देश के लोग ज़मीन या मकान में निवेश करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका निवेश वहां सुरक्षित है. इसी देश में बैंकों ने बड़े-बड़े स्कैम किए, बैंकों ने पैसा साइफन किया, इसी देश में सरकारी वित्तीय संस्थानों ने बॉन्ड्स निकाले, इसी देश में वित्तीय संस्थाओं ने बाज़ार आधारित निवेश प्रक्रिया शुरू की और लाखों-करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया. बहुत सारे लोग बाज़ार आधारित इकॉनामी का शिकार हमारे देश में हुए हैं, जिनमें से बहुतों ने आत्महत्या कर ली. इसी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसे मौजूदा सरकार के मंत्री फैशन बता रहे हैं. वे कहते हैं कि किसान का आत्महत्या करना एक फैशन हो गया है.

अब मेरी समझ में नहीं आता कि वो वादा कहां गया कि हमारा पैसा कालाधन के रूप में विदेश में जमा है, जिसे हम हिन्दुस्तान लेकर आएंगे. उसकी अब कहीं चर्चा नहीं होती. हमने इस देश में गरीबों, सामान्य लोगों या मध्यम वर्ग का वह पैसा नोट बदलने के बाद निकलवाया, जिसे वह अपनी बीमारी, मुसीबत, परेशानी के वक्त घर में कैश के रूप में रखते थे. गरीब से गरीब आदमी भी किसी न किसी तरह पांच से 10 हज़ार रुपए बचाकर मुसीबत के लिए रखता था. अब उस पैसे को कालाधन बताकर देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हम सब चोर नज़र आते हैं. कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करने जाता है तो लोग देखते हैं कि ओ, हो! ये पैसा चोरी का है, ये पैसा छिपाया हुआ है, ये जमा करने आया है. इसकी आड़ में वे सारे लोग बच गए, जो कालाधन का धंधा करते हैं, जो कालाधन की इकोनॉमी चलाते हैं और जिनका पैसा विदेशी बैंकों में जमा है. अब सरकार ने घोषणा की है कि सारा कालाधन वापस आ गया है यानी आज की तारीख़ में देश में कहीं कोई कालाधन नहीं है. हमें सरकार की बात पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग एक लाख, पांच लाख, 10 लाख, 50 लाख की नए नोटों की गड्डियों के साथ पकड़े गए हैं. आज भी टेलीविज़न पर कुछ खबरें नए नोटों के बंडल के साथ दिखाए जाते हैं कि यह-यह रुपया पकड़ा गया. ये सारी चीज़ यह कहकर टाल दी जा रही हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में ही कुछ अपराधी हैं, जो रुपए बदल रहे हैं या रुपयों को बाहर निकाल कर निहित स्वार्थों के हाथों में दे रहे हैं. हमने जब तहकीकात की तो बैंक के लोगों ने कहा कि हमारे पास कितना रुपया आता है, यह रिज़र्व बैंक को पता होता है. छोटे बैंकों में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और बड़े बैंकों में रोज़ 20 लाख रुपए तक की नोटों की आपूर्ति की गई. जब इन नोटों की आपूर्ति हुई, तब हमारे यहां लंबी-लंबी लाइनें लगी थीं. हम लोगों को पैसे दे रहे थे. पर यह 5, 10, 20 लाख, एक करोड़, दो करोड़, 50 करोड़ की संख्या में ये दो-दो हज़ार रुपए के नोट किस बैंक से निकले. बैंकिंग अधिकारियों का कहना है कि ये हमारे यहां से नहीं निकले हैं. ये नोट सीधे या तो जहां छपाई हो रही है, वहां से निकले हैं या फिर ये नोट रिज़र्व बैंक से निकले हैं. ये नोट सामान्य बैंकों की शाखाओं से नहीं निकले हैं. यह सवाल बहुत जायज़ है कि जो रुपया पकड़ा जा रहा है, वह निकल कहां से रहा है?

दूसरा सवाल कि ये सारे लोग जो पकड़े गये, इनका रिश्ता एक विशेष राजनीतिक पार्टी से कैसे है? यह रहस्य कोई नहीं समझ पा रहा है कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उनका सीधा-सीधा रिश्ता एक विशेष राजनीतिक पार्टी से है. वे पकड़े इसलिए गए क्योंकि जो निचले स्तर पर जांच करने वाली एजेंसियां हैं, उन्हें नहीं पता था कि इन लोगों को छोड़ देना है, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया. तीसरा सवाल पांच-पांच, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगाकर एक विशेष राजनैतिक दल की रैलियां हुईं, वो पैसे कहां से आए? पैसा तो दिया गया, बसों को दिया गया, जिनमें लोग भरकर आए. कुर्सी वालों को दिया गया, माइक वालों को दिया गया, टैंट वालों को दिया गया, प्रचार करने वालों को दिया गया, टेलीविज़न चैनलों को दिया गया, ये पैसा कहां से दिया गया. ये नए नोट कैसे दिए गए क्योंकि पुराने नोट तो कहीं चलन में हैं नहीं

> अब मेरी समझ में नहीं आता कि वो वादा कहां गया कि हमारा पैसा कालाधन के रूप में विदेश में जमा है, जिसे हम हिन्दुस्तान लेकर आएंगे. उसकी अब कहीं चर्चा नहीं होती. हमने इस देश में गरीबों, सामान्य लोगों या मध्यम वर्ग का वह पैसा नोट बदलने के बाद निकलवाया, जिसे वह अपनी बीमारी, मुसीबत, परेशानी के वक्त घर में कैश के रूप में रखते थे. गरीब से गरीब आदमी भी किसी न किसी तरह पांच से 10 हज़ार रुपए बचाकर मुसीबत के लिए रखता था. अब उस पैसे को कालाधन बताकर देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हम सब चोर नज़र आते हैं.

और न ही कोई ले रहा है. तब ये पैसे कहां से आए, कहां से निकले? इन सवालों का जवाब मुझे नहीं लगता कि हमें कभी मिलेगा. ये एक ऐसा रहस्य है, जो है तो खुला, लेकिन कभी कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा. जो भी इन सवालों को पूछेगा वह देशद्रोही मान लिया जाएगा. आज एक माहौल बन गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ़ कोई बात करते हैं तो आप देशद्रोही हैं क्योंकि सरकार इस देश को नया बनाने के लिए जी-जान लगाए हुए है.

हमने अगर बचपन में अपने परिवार के किसी सदस्य की जेब से पतंग उड़ाने के लिए चार आने चुराए, तो आज हमसे कहा जा रहा है चूंकि तुमने चार आने चुराए थे, तो इसलिए तुम इस लाखों करोड़ों रुपयों की चोरी पर सवाल नहीं उठा सकते. तुम्हारी और हमारी चोरी में नैतिक रूप से कोई फर्क़ नहीं है, सिर्फ़ मात्रा का फर्क है. तुमने चार आने चुराए, हम चार लाख करोड़ रुपए चुरा लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह तर्क इस समय देश में उन लोगों द्वारा तेज़ी से फैलाया जा रहा है, जो एक विशेष राजनीतिक पार्टी के सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले किराए के लोग हैं. ये लोग 24 घंटे धुआंधार झूठ की बमबारी कर रहे हैं.

अब यहां एक और सवाल उठता है. सवाल यह है कि आजकल देश का माहौल अजीब हो गया है. कश्मीर के लोग, जिनकी संख्या 60 से 80 लाख है, पूर्णतया देशद्रोही हो चुके हैं. देश को समझा दिया गया है कि ये सब पाकिस्तान समर्थक हैं, चाहे वे कितना भी चिल्लाएं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं. हम हिन्दुस्तान से अपनी इज्जत, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या बंगाल के लोग कर रहे हैं. कश्मीर के अलावा दूसरे प्रदेश के लोगों की मांगें-मांगें हैं, कश्मीर के लोगों की मांगें सीधे पाकिस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ती हैं, ये माहौल देश में बना दिया गया है. एक तरफ़ कश्मीर के लोग देशद्रोही हो गए, दूसरी तरफ़ कश्मीर के अलावा सारे देश के लोग बड़ी संख्या में, आप उन्हें 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ कह सकते हैं, ये सारे लोग चोर हो गए हैं, जो चोरी से बैंक में जाते हैं. पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े होते हैं या बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं. वहां उन्हें चोर की नज़र से देखा जाता है. ईमानदार कौन हैं, बस कुछ लोग. क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है और वो सारे देश को चोर बनाने का माहौल सफलतापूर्वक बना चुके हैं. उनका यह मानना है कि जो हम कहते हैं, वही सही है. लोकतंत्र में ये नए मूल्य जिन्हें आज डाला गया है, वो इतने खतरनाक हैं कि उन्होंने संपूर्ण विपक्ष को सकते में डाल दिया है. विपक्ष का कोई नेता सवाल खड़ा करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसे फौरन देशद्रोही या देश के विकास में बाधक घोषित कर दिया जाएगा.

अब अगले हमले के लिए उन चन्द लोगों को तैयार रहना चाहिए, जो कोने में फुसफुसाहट के रूप में ही सही, लेकिन सही बात, सही आवाज़ उठा रहे हैं. देश का ये माहौल ऐसा लगता है कि हज़ारों साल की उस परंपरा को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, जिसे इस देश ने गर्व के साथ मानवीयता, भाईचारा, बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव, सबको एक साथ जीने के समान अवसर के रूप में स्वीकार किया था. आज इन सारे मूल्यों के खिलाफ़ नए मूल्यों को इंट्रोड्यूस करने वाली ताकतें बेखौफ़ मुस्कुरा रही हैं और ये देश धीरे-धीरे अपने मूल्यों को समाप्त होते देख रहा है. कहीं सवाल नहीं उठ रहा है कि भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गयी है? कहीं सवाल नहीं उठा रहा है कि नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? कहीं सवाल नहीं उठा रहा है कि विकास की गाड़ी क्यों रुक गई है? बस सब सकते में हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है?

लोकतंत्र की यह स्थिति लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी आदि के लिए एक सबक़ है. देश के हर आदमी के लिए एक सबक़ है. बस देखना है कि यह सबक़ उनके गले पूरी तरह उतर गया है या नहीं. ■

editor@chauthiduniya.com

'हिंद स्वराज'

> बंग-भंग से जैसे अंग्रेज़ी जहाज में दरार पड़ी है, वैसे ही हममें भी दरार-फूट पड़ी है. बड़ी घटनाओं के परिणाम भी यों बड़े ही होते हैं. हमारे नेताओं में दो दल हो गये हैं, एक मॉडरेट और दूसरा एक्स्ट्रीमिस्ट. उनको हम 'धीमे' और 'उतावले' कह सकते हैं.

बंग-भंग

पाठक: आप कहते हैं उस तरह विचार करने पर यह ठीक लगता है कि कांग्रेस ने स्वराज्य की नींव डाली. लेकिन यह तो आप मानेंगे कि वह सही जागृति नहीं थी. सही जागृति कब और कैसे हुई?

संपादक: बीज हमेशा हमें दिखाई नहीं देता. वह अपना काम ज़मीन के नीचे करता है और जब ख़ुद मिट जाता है तब पेड़ जमीन के ऊपर देखने में आता है. कांग्रेस के बारे में ऐसा ही समझिए. जिसे आप सही जागृति मानते हैं, वह तो बंग-भंग से हुई, जिसके लिए हम लॉर्ड कर्ज़न के आभारी हैं. बंग-भंग के वक्त बंगालियों ने कर्ज़न साहब से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे साहब अपनी सत्ता के मद में लापरवाह रहे. उन्होंने मान लिया कि हिन्दुस्तानी लोग सिर्फ़ बकवास ही करेंगे, उनसे कुछ भी नहीं होगा. उन्होंने अपमान भरी भाषा का प्रयोग किया और ज़बरदस्ती बंगाल के टुकड़े किये. हम यह मान सकते हैं कि उस दिन से अंग्रेज़ी राज्य के भी टुकड़े हुए. बंग-भंग से जो धक्का अंग्रेज़ी हुकूमत को लगा, वैसा और किसी काम से नहीं लगा. इसका मतलब यह नहीं कि जो दूसरे गैर-इन्साफ़ हुए, वे बंग-भंग से कुछ कम थे. नमक महसूल कुछ कम गैर-इन्साफ़ नहीं है. ऐसा और तो आगे हम बहुत देखेंगे. लेकिन बंगाल के टुकड़े करने का विरोध करने के लिए प्रजा तैयार थी. उस वक्त प्रजा की भावना बहुत तेज़ थी. उस समय बंगाल के बहुतेरे नेता अपना सबकुछ न्यौछावर करने को तैयार थे. अपनी सत्ता, अपनी ताक़त को वे जानते थे. इसलिए तुरन्त आग भड़क उठी. अब वह बुझने वाली नहीं है, उसे बुझाने की ज़रूरत भी नहीं है. ये टुकड़े क़ायम नहीं रहेंगे, बंगाल फिर एक हो जाएगा. लेकिन अंग्रेज़ी जहाज़ में जो दरार पड़ी है, वह तो हमेशा रहेगी ही. वह दिन-ब-दिन चौड़ी होती जाएगी. जागा हुआ हिन्द फिर सो जाय, वह नामुमकिन है. बंग-भंग को रद्द करने की मांग स्वराज्य की मांग के बराबर है. बंगाल के नेता यह बात खूब जानते हैं. अंग्रेजी हुकूमत भी यह बात समझती है, इसीलिए टुकड़े रद्द नहीं हुए. ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रजा तैयार होती जाती है. प्रजा एक दिन में नहीं बनती, उसे बनने में कई बरस लग जाते हैं.

पाठक: बंग-भंग के नतीजे आपने क्या देखे ?

संपादक: आज तक हम मानते आये हैं कि बादशाह से अर्ज़ करना चाहिये और वैसा करने पर भी दाद न मिले तो दु:ख सहन करना चाहिये, अलबत्ता, अर्ज़ तो करते ही रहना चाहिए. बंगाल के टुकड़े होने के बाद लोगों ने देखा कि हमारी अर्ज़ के पीछे कुछ ताकत चाहिए, लोगों में कष्ट सहन करने की शक्ति चाहिए. यह नया जोश टुकड़े होने का अहम नतीजा माना जायेगा. यह जोश अख़बारों के लेखों में दिखाई दिया. लेख कड़े होने लगे. जो बात लोग डरते हुए या चोरी-चुपके करते थे, वह खुल्लमखुल्ला होने लगी, लिखी जाने लगी. स्वदेशी का आन्दोलन चला. अंग्रेज़ों को देखकर छोटे-बड़े सब भागते थे, पर अब नहीं डरते, मार-पीट से भी नहीं डरते, जेल जाने में भी उन्हें कोई हर्ज नहीं मालूम होता और हिन्दी के पुत्ररत्न आज देशनिकाला भुगतते हुए (विदेशों में) विराजमान हैं. यह चीज उस अर्ज से अलग है. यों लोगों में खलबली मच रही है. बंगाल की हवा उत्तर में पंजाब तक और (दक्षिण में) मद्रास इलाके में कन्याकुमारी तक पहुंच गई है.

पाठक: इसके अलावा और कोई जानने लायक नतीजा आपको सूझता है?

संपादक: बंग-भंग से जैसे अंग्रेज़ी जहाज में दरार पड़ी है, वैसे ही हममें भी दरार-फूट पड़ी है. बड़ी घटनाओं के परिणाम भी यों बड़े ही होते हैं. हमारे नेताओं में दो दल हो गये हैं, एक मॉडरेट और दूसरा एक्स्ट्रीमिस्ट. उनको हम 'धीमे' और 'उतावले' कह सकते हैं. ('नरम दल' व 'गरम दल' शब्द भी चलते हैं.) कोई मॉडरेट को डरपोक पक्ष और एक्स्ट्रीमिस्ट को हिम्मतवाला पक्ष भी कहते हैं. सब अपने-अपने खयालों के मुताबिक इन दो शब्दों का अर्थ करते हैं. यह सच है कि ये जो दल हुए हैं, उनके बीच ज़हर भी पैदा हुआ है. एक दल दूसरे का भरोसा नहीं करता, दोनों एक दूसरे को ताना मारते हैं. सुरत कांग्रेस के समय क़रीब-क़रीब मार-पीट भी हो गई. ये जो दो दल हुए हैं, वह देश के लिए अच्छी निशानी नहीं है, ऐसा मुझे तो लगता है. लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि ऐसे दल लम्बे अरसे तक टिकेंगे नहीं. इस तरह कब तक ये दल रहेंगे, यह तो नेताओं पर आधार रखता है. ■

मगध स्नातक चुनाव

महागठबंधन के दो राजनीतिक परिवारों की दावेदारी

चौथी दुनिया ब्यूरो

मगध स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव इस वर्ष मार्च अप्रैल माह में होने हैं. इसके लिए राजनीतिक गठजोड़ भी तेज हो गई है. एनडीए की तरफ से विधान परिषद के सभापति भाजपा नेता अवधेश नारायण सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. पेच यूपीए में ही फंसेगा. जिस पर पूर्व विधान पार्षद डॉ. अजय कुमार सिंह एक बार फिर दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं. जबकि पूरे जोशो खरोश के साथ डॉ. पुनीत सिंह भी इसी गठबंधन के समर्थन के लिए जोर लगाए बैठे हैं. यहां बता देना जरूरी है कि डॉ. अजय कुमार सिंह पूर्व सहकारिता नेता सह सांसद स्वर्गीय तपेश्वर सिंह के बेटे हैं. जबकि डॉ. पुनीत बक्सर के पूर्व सांसद जगदानंद सिंह के पुत्र हैं. डॉ. अजय कांग्रेस की राजनीत करते हैं. जबकि डॉ. पुनीत की माने तो वे अपने पिता जगदानंद सिंह के दल के कार्यकर्ता हैं. सवाल यह उठता है कि महागठबंधन इन दोनों नेताओं में से किसे अपना समर्थन देगा. शाहाबाद की राजद राजनीति में जगदानंद सिंह की पकड़ अभी भी पूर्ववत है. अगर डॉ. सुधीर क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जगदा बाबू की मौन सहमती जरूर रही होगी. परंतु अभी तक उन्होंने इस पर अपना मुंह नहीं खोला है. डॉ. अजय सिंह की दावेदारी का आधार मगध स्नातक क्षेत्र की राजनीति पर पहले से रहे पकड़ को माना जाता है. इस सीट पर शुरू से ही कांग्रेस लड़ती रही है. इसलिए उसका दावा इस बार भी रहेगा. अब महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद के तर्कों को भी गठबंधन भर में सुना जाएगा. अगर दोनों दावेदार मजबूती के साथ खड़े दिखे तो महागठबंधन के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट होगा. दोनों दावेदारों ने अब तक चुनाव में डटे रहने की बात हर मतदाता के सामने दुहराई है. अगर स्थिति यही रही, तो महागठबंधन के वोटो का बंदरबाट होना भी तय है. डॉ. अजय को सवर्ण मतों में एक जाति विशेष का अच्छा आर्शीवाद प्राप्त है, जो इनके पिता स्वर्गीय तवेश्वर सिंह के समय से ही

डॉ. अजय कुमार सिंह | अवधेश नारायण सिंह | डॉ. पुनीत सिंह

मिलता आया है. वे महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में लाभ लेने का प्रयास करेंगे. डॉ. पुनीत की दावेदारी महागठबंधन के लिए पिछड़े मतो के ध्रुवीकरण में मजबूती प्रदान करेगी. ऐसे हालातो में पेच दोनों तरफ फंस रहे हैं. दावे भी शाहाबाद के दोनों राजनीतिक परिवारों की तरफ से मजबूती से पेश किए गए हैं. हालांकि भाजपा यहीं चाहती है कि हर हाल में महागठबंधन में दावेदारों की संख्या बढ़े. वैसे हालात पैदा हुए तो मतो का बिखराव काफी तेजी से होगा. जो अवधेश नारायण सिंह को एक बार फिर सदन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा. अवधेश नारायण सिंह की चुनावी तैयारी गति भी पकड़ चुकी है. लेकिन अभी तक एनडीए के घटक दल लोजपा, रालोसपा के दोनों गुट और हम की तरफ से इतनी सक्रियता देखने को नहीं मिल रही है. सिर्फ भाजपा ही वोटर बनाने से लेकर आवेदन पत्र जमा कराने तक की सक्रियता में दिख रही है. इधर डॉ. अजय और डॉ. पुनीत दोनों ही दावेदारों के समर्थक महागठबंधन धर्म को आधार मानकर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं. अगर यह गति अंत तक बनी रहे, तो महागठबंधन का अक्रामक रुख इसके वोटरों को एक तरफ केंद्रित करेगा. भाजपा धीरे-धीरे अपने चुनाव अभियान को गति देने में जुटी हुई है. डॉ. अवधेश नारायण सिंह के अलावा डॉ. अजय और डॉ. पुनीत ही दो ऐसे नाम हैं, जो अभी तक सामने आए हैं. इनके समर्थक पिछले दो महीने से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं. दावेदार भी एक-एक वोटर तक पहुंचने के प्रयास में हैं. गौरतलब है कि ये तीनों ही दावेदार शाहाबाद प्रक्षेत्र से आते हैं. इसमें से एक डॉ. पुनीत कैमूर जिला अंतर्गत रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र व बक्सर लोक सभा क्षेत्र से हैं. जबकि डॉ. अजय और अवधेश नारायण सिंह भोजपुर जिला अंतर्गत आरा संसदीय क्षेत्र से संबंधित हैं. अभी मगध क्षेत्र के अन्य जिलों गया औरंगाबाद आदि से दावेदारों की सक्रियता मुखर होकर सामने नहीं आई है. अगर एनडीए और महागठबंधन की तरफ से इस क्षेत्र में दावेदारों की संख्या बढ़ी, तो राजनीतिक पेच और उलझेगा. जातिय समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे. गठबंधन का आधार भी बिखरेगा. दावेदारों के प्रति व्यक्तिगत रंजीश भी इस चुनाव में रंग दिखा सकता है, क्योंकि फिलहाल सामने आए तीनों नामों की पुरानी राजनीतिक पहचान रही है. इसमें बढ़ते दोस्तों के बीच दुश्मनों की संख्या काफी बड़ी है. भाजपा में भी भीतरघात से इंकार नहीं किया जा सकता. क्योंकि बिहार विभाजन के बाद इस क्षेत्र का लगातार दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके अवधेश नारायण सिंह को भी इस बार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. हाल के दिनों में काफी तेजी से शाहाबाद प्रक्षेत्र की राजनीत ने करवट ली है. महागठबंधन और एनडीए में कई नए राजनीतिक छत्रपों का उदय हुआ है. जिनकी इस चुनाव में परदे के पीछे से अहम भूमिका होगी. मसलन रामगढ में ही राजद द्वारा अपना सीट खो देने से वहां भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है. वहीं रोहतास के नोखा और सासाराम में भाजपा की हार से इसकी स्थिति कमजोर हुई है. कैमूर में चारो विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत ने वहां पर इस चुनाव में महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की है. हर विधायकों के लिए प्राथमिकता होगी कि वह विधानसभा से संबंधित प्रत्याशी को जीत दिलाए. कैमूर को छोड़कर शाहाबाद के बाकी तीन जिलों से एनडीए के पांव गत विधानसभा चुनाव में उखड़ गए थे. अगर यह आधार रहा तो इस चुनाव में महागठबंधन को लाभ मिलेगा. लेकिन यह लाभ तभी संभव है, जब यूपीए की तरफ से किसी एक उम्मीदवार को समर्थन हो. अगर डॉ. अजय और डॉ. पुनीत दोनों मैदान में आए, तो मतो का बंटवारा तय है. इधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने भी समीक्षात्मक बैठकों में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है. भाजपा का प्रयास होगा कि किसी तरह एनडीए के मतो का बिखराव न हो, पिछले विधान परिषद चुनाव वाले मतों को एकत्रित रखा जाए और यूपीए के मतो में सेंधमारी की जाए. अगर ऐसा हुआ तभी एनडीए की जीत सुनिश्चित हो पाएगी. हालांकि जदयू ने अभी तक इस चुनाव में अपनी कोई गतिविधि नहीं दिखाई है. जबकि उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह और संतोष निराला की भूमिका इस चुनाव में अहम होगी. सपा की राजनीति में सक्रिय दिख रहे रोहतास के पुराने दिग्गज रामधनी सिंह की नजदीकियां भाजपा नेता राजेंद्र सिंह से बढ़ी है. इसका यहां चुनाव में कैसा असर होगा, यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी. क्योंकि वोटरों में रामधनी सिंह की पैठ भी काफी मजबूत है. रोहतास के एकलौते चेनारी सुरक्षित विधान सभा से रालोसपा के ललन पासवान की सक्रियता स्नातक चुनाव में पिछली बार भी देखी गई थी. इन्होंने काफी मेहनत भी किया था. देखना यह है कि इस सक्रियता का लाभ इस बार एनडीए को मिलता है या नहीं. इस बार का मगध स्नातक चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि अभी से ही भाजपा, राजद और कांग्रेस की दावेदारी मजबूती से सामने आई है. अन्य दल जिसमें जदयू, लोजपा, रालोसपा आदि अभी चुप्पी साधे बैठे हैं. वैसे इस चुनाव में मगध स्नातक क्षेत्र गठबंधन धर्मों को तोड़ भी सकता है. सभी प्रत्याशियों को भीतरघात का सामना करना पड़ेगा. जातिय गोलबंदी पर धन बल के भारी पड़ने की उम्मीद है. पूरे विधान परिषद क्षेत्र के बीचोबीच गुजरने वाली विभाजक सोन नदी की रेखा यहां भाषा की अंतर भी पैदा करती है. शाहाबाद प्रक्षेत्र में खाटी भोजपुरी तो सोन के इस पार मगध क्षेत्र में खाटी मगही बोली जाती है. भाषा का अंतर भी अगर राजनीतिक ध्रुवीकरण का आधार बना तो लड़ाई और भी दिलचस्प होगी. जहां सबके लिए एक-एक मत के अंतर भारी पड़ेंगे. अभी तो सिर्फ भोजपुरी भाषायी क्षेत्र से ही मजबूत नामों की चर्चा सामने आई है. एनडीए में अगर अंतर विरोध को बाद के समझौतों के आधार पर समाप्त मान लिया जाए, तो भी यूपीए में यह संकट सामने आ सकता है. देखना यह है कि पिछले लोकसभा और विधान सभा चुनाव के बाद बिहार में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच इस बार अवधेश नारायण सिंह के लिए राहें कितनी आसान हो पाती हैं. फिलहाल दावेदारों की दावेदारी हर गठबंधन के लिए सरदर्द का कारण बनी है.■

feedback@chauthiduniya.com

विकास पर माननीयों को घेरने लगी जनता

राजेश सिन्हा

निश्चय यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के समर्थन में उमड़े जनसैलाब से जहां सरकारी अमला गदगद है, वहीं विभिन्न समस्याओं से आजिज लोगों के द्वारा न केवल सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है, बल्कि जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा भी किया जाने लगा है. बकायदा जन अदालत का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाने के बावत नोटिस जारी किए जा रहे हैं. पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधियों से विकास के मुद्दे पर सवाल पर पूछे जा रहे हैं. जनता का नोटिस मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं होने वाले जनप्रतनिधियों को भगोड़ा घोषित कर इनके विरूद्ध आर-पार की लड़ाई का ऐलान भी हो रहा है. इस नई परिपाटी की शुरुआत खगड़िया से हुई है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने के बाद अब आक्रोशित लोग सरकार को घेरने की रणनीति में जुट गए हैं. विकास के सवाल पर जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी सर्किल नम्बर एक की जनता भी

सरकार को घेरने के बावत ठोस रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है. इस बार आर-पार की लड़ाई का मन बनाते हुए जनता न केवल सड़कों पर उतर आयी है, बल्कि यह नारा भी बुलंद किया जाने लगा है कि लाठी-गोली खाएंगे, लेकिन पक्की सड़क बनवाएंगे. युवाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह त्यागी के नेतृत्व में आंदोलन करते आ रहे विजय सिंह, परमानंद सिंह, पूर्व सैनिक घनेश्वर सिंह, रामाशंकर सिंह, मनोरमा देवी, लड्डू यादव, अभय कुमार उर्फ गुड्डू, साकेत सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों का कहना है कि अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे. लेकिन गोगरी के सर्किल नम्बर एक की जनता के साथ सरकार के द्वारा किए जाते रहे सौतेले व्यवहार का न केवल पर्दाफाश करेंगे बल्कि सर्वांगीण विकास की बातों को सरजमीं पर उतरवा कर रहेंगे. आक्रोशित लोगों का कहना है कि विकास नहीं होने का कारण जानने के लिए जन अदालत का आयोजन कर 1990 से जनप्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित होने वाले मुखिया से लेकर सांसद तक को आमंत्रित किया गया था. लेकिन अधिसंख्य जनप्रतिनिधि जन अदालत में नदारद रहे. स्थानीय सांसद ही नहीं विधायकों ने भी इस जन अदालत में आना उचित नहीं समझा. अनुपस्थित रहने वाले जनप्रतिनिधियों को भगोड़ा घोषित करते हुए इनके विरूद्ध आर-पार की लड़ाई का मन बनाते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा अगर फौरी तौर पर इस संदर्भ में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो राज्य सरकार के विरूद्ध भी मोर्चा खोल दिया जाएगा. स्थानीय विधायक पन्ना लाल पटेल कहते हैं कि सोनवर्षा से सतीशनगर तक पक्की सड़क के बावत डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है. विरोधियों द्वारा जनता को मेरे विरूद्ध गोलबंद करने के उद्देश्य से अनाप-शनाप प्रचार किया जा रहा है. हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है. सम्पन्न हुए अधिकार यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ इसी तरह के ज्वलंत मसलों को लेकर खगड़िया की जनता के कोप का सामना करना पड़ा था. युवाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह त्यागी, नगर सभापति मनोहर कुमार यादव, शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह सहित दर्जनों के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी. लेकिन बाद में न्यायालय के द्वारा सभी को अग्रिम जमानत दे दी गई. इस दौरान पूर्व विधायक रणवीर यादव के द्वारा अपनी विधायक पत्नी पूनम देवी यादव के अंगरक्षक से कारबाईन छीनकर लहराए जाने का मामला भी सुर्खियों में रहा था. हालांकि प्रशासनिक पदाधिकारियों का कहना है कि अधिकार यात्रा के दौरान उत्पन्न हुई स्थिति से सीख लेते हुए इस बार पूरी व्यवस्था की गई है.

इधर दशकों पूर्व दान में दी गई तीन बीघे जमीन पर मालिकाना हक जताने को लेकर अक्सर सुलगती रही बलैठा गांव की राजनीति भी मुख्यमंत्री के करीब पहुंचने लगी है. दान में मिली तीन बीघे जमीन पर एक पक्ष कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा है, जबकि एक पक्ष मंदिर होने की बात को लेकर अड़िग है. लगभग छह वर्षों से अलग-अलग पक्षों के सीने में धधक रही घात-प्रतिघात की आग पर राजनीतिक रोटी सेंकने वाले जनप्रतिनिधियों को यह विवाद शायद इसलिए रास आ रहा, क्योंकि यह इनके लिए महज चुनावी मामला बनकर रह गया. वर्षों से दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद पर लगाम लगाने के ख्याल से स्थानीय लोग अब सीधे सरकार से हस्तक्षेप की मांग को लेकर गोलबंद होने लगे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक राजा हरदत सिंह के द्वारा वर्षों पूर्व दान में दी गई जमीन पर कब्रिस्तान तथा मठ मंदिर बनाने के मुद्दे पर लगभग छह वर्ष पूर्व पनपा विवाद अब भयंकर रूप धारण करने लगा है. प्रशासन ने विवादित जमीन पर पुलिस पिकेट तो स्थापित कर दिया है, लेकिन विवाद सुलझाने के प्रति न तो प्रशासन गंभीर है और न ही जनप्रतिनिधि. नतीजतन उपद्रवियों के द्वारा समय-समय पर दो अलग-अलग पक्षों की भावनाओं को उभारने का प्रयास किया जाता है. लेकिन जरूरत है इस विवाद के जल्द से जल्द समाधान की.■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतु सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ

सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ

मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।

Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

वाल्मीकि कुमार

अपने हाल पर आंसू बहा रहा है 52 एकड़ में फैला मत्स्य प्रजनन केंद्र

करोड़ों ख़र्च पर हाथ नहीं लग रही मछली

सीतामढ़ी जिले में तकरीबन ढाई दशक पूर्व मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन सह वितरण केंद्र की स्थापना करायी गयी थी. सीतामढ़ी–शिवहर एनएच–104 के राघोपुर बखरी गांव में मुख्य पथ से करीब एक किलोमीटर पूरब दिशा में स्थापित उक्त केंद्र को जिले के मत्स्य पालकों के लिए बेहतर भविष्य के रूप में देखा जा रहा था. लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण वर्तमान में यह मत्स्य पालन केंद्र अपने हाल पर आंसू बहा रहा है. इसका परिसर अब स्थानीय दबंगों के अतिक्रमण का शिकार हो रहा है. परिसर में चारो तरफ पुआल बिखरा पड़ा है. 16 अक्टूबर 1986 को बिहार सरकार के तत्कालीन मत्स्य सह पशुपालन मंत्री मदन प्रसाद सिंह ने खाद्य दिवस के अवसर पर इस केंद्र का उद्घाटन किया था. करीब 52 एकड़ जमीन पर स्थापित इस मत्स्य पालन केंद्र को विश्व बैंक के तत्कालीन अभियंता एससी खोभारी चाईना ने डिजाइन किया था. 1980 में चीन से प्रशिक्षण प्राप्त कर के आये अभियंता नंद किशोर सिंह का इस केंद्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था. इसके प्रत्येक तालाब की खुदाई करीब डेढ़ एकड जमीन में करायी गयी थी, जिनमें तकरीबन एक दर्जन तालाब मत्स्य प्रजनक थे. गौरतलब है कि संपूर्ण भारत में इस प्रकार के दो ही केंद्र थे, एक राजधानी पटना में और दूसरा सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में. पटना वाले को बंद कर वहां एम्स की स्थापना करा दी गयी. वहीं राघोपुर बखरी का केंद्र तकरीबन तीन साल पहले तक साल में चार माह मत्स्य बीज प्रजनन का कार्य करता रहा है.

केंद्र परिसर में जल की समस्या से निजात के लिए 20 एचपी का दो समरसिबल पंप भी लगाया गया था. 40 केबी का एक जेनेरेटर एवं 80 हजार गैलन क्षमता वाली एक पानी की टंकी भी उपलब्ध करायी गयी थी. इसके साथ ही तीन हैचिंग व दो ग्रिडिंग पुल का भी निर्माण कराया गया था. तब केंद्र को चलाने के लिए एक प्रभारी मो. अख्तर जमाल के अलावा 3 चौकीदारों की नियुक्ति भी हुई थी. केंद्र के लिए हैचरी प्रबंधक के अलावा 4 मत्स्य तकनीशियन और 6 मछुआरों का पद भी सृजित किया गया था. केंद्र के तत्कालीन प्रभारी मो. जमाल ने इस बारे में बताया कि सबसे पहले 1986 में उड़ीसा के बासकेट हैचरी से केंद्र का श्रीगणेश किया गया था, जो कि 1989 तक कार्य करता रहा. 1990 में चाईनीज सर्कुलर हैचरी के कार्यरत होने के बाद लाखों की लागत से निर्मित बासकेट हैचरी का प्रयोगशाला बेकार होकर रह गया. प्रयोगशाला का पाईपलाईन व भवन जर्जर होने लगा. भवन के खिडकियां–दरवाजे सड़ गए. इस मत्स्य पालन केंद्र में पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य प्रांतों से भी

> केंद्र व राज्य की सरकारें प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करती हैं, लेकिन पूर्व से चल रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जाता. भारत–नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढी जिला के राघोपुर बखरी में तकरीबन तीन दशक पूर्व मत्स्य प्रजनन एवं मत्स्य बीज वितरण केंद्र की स्थापना हुई थी. लेकिन आज यह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. 'चौथी दुनिया' ने इसकी दुर्दशा पर 27 मई–02 जून 2013 अंक में विस्तार से एक रिपोर्ट प्रकाशित कर सरकार व स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया था. परंतु प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा. इस मत्स्य पालन केंद्र के जरिये अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाले हजारों मछली पालक कई सालों से वादों और आश्वासनों के मायाजाल में फंसते आ रहे हैं.

फिशरी कॉलेजों के छात्र आकर मत्स्य प्रजनन पर प्रयोग करते थे. लेकिन यहां पर छात्रों के ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण महज चंद दिनों बाद ही उनके वापस जाने की मजबूरी बनी रही.

वर्तमान में जिले का विभागीय आंकड़ा बताता है कि सीतामढ़ी जिले के मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण के लिए अन्य स्थानों पर भेजने में लाखों खर्च किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2014–15 में मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण की योजना से संबंधित प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्य से बाहर 90 प्रशिक्षण के लिए 9 लाख रुपये खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. जिसके आलोक में कुल 60 प्रशिक्षण पर 5 लाख 37 हजार रुपये खर्च किये गये हैं. जबकि 270 जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए निर्धारित 4 लाख 72 हजार में से 264 प्रशिक्षण पर तकरीबन पौने 4 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है. एक ओर जहां इतनी बडी संस्था मृतप्राय बनी है, वही दूसरी ओर जिले के अलग–अलग प्रखंडों में हेचरी की स्थापना के लिए केंद्र व राज्य सरकार व्यापक स्तर पर अनुदान दे रही है. सीतामढ़ी जिले में ही तकरीबन डेढ़ दर्जन हैचरी हैं. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत 281 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. इस राशि से बत्तख सह मछली, बागवानी सह मछली एवं गाय सह मछली पालन की भी व्यवस्था करायी जानी थी. इसके अलावा फिशरी कॉलेजों के छात्रों की सुविधा के लिए एक छात्रावास निर्माण की भी योजना थी. जिन उद्देश्यों के लिए यह राशि प्रस्तावित थी, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित एक केंद्र आज जर्जर हाल में है. अगर यह प्रस्तावित राशि राघोपुर बखरी मत्स्य पालन केंद्र को उपलब्ध करा दी गयी होती, तो बहुत हद तक इसका विकास हो गया होता. साथ ही सूबे के मत्स्य पालकों को आंध्रप्रदेश समेत अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए जाने की समस्या से निजात भी मिलता और प्रशिक्षण मद में खर्च की जाने वाली सरकारी राशि भी बच जाती. तकरीबन तीन साल पूर्व तक इस मत्स्य पालन केंद्र में मई से अगस्त माह के बीच बीज प्रजनन कार्य के साथ उत्पादित बीज को 5 सौ रुपये प्रति लाख की दर से वितरित किया जाता रहा है. जिससे प्रतिवर्ष तकरीबन ढाई से तीन लाख रुपये तक की आमदनी होती थी.

हाल ही में केंद्र सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए नीली क्रांति योजना को स्वीकृति प्रदान की है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. राज्य सरकार के द्वारा भी 20 प्रतिशत अतिरिक्त टॉप अप अनुदान का प्रस्ताव है. इस योजना में नये तालाबों के निर्माण, आर्द्रभूमि के

> जिन उद्देश्यों के लिए यह राशि प्रस्तावित थी, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित एक केंद्र आज जर्जर हाल में है. अगर यह प्रस्तावित राशि राघोपुर बखरी मत्स्य पालन केंद्र को उपलब्ध करा दी गयी होती, तो बहुत हद तक इसका विकास हो गया होता. साथ ही सूबे के मत्स्य पालकों को आंध्रप्रदेश समेत अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए जाने की समस्या से निजात भी मिलता और प्रशिक्षण मद में खर्च की जाने वाली सरकारी राशि भी बच जाती.

विकास, अंगुलिकाओं के संचयन, केज में मछली पालन, हैचरी निर्माण व फिश शेड मील की स्थापना को भी शामिल किया गया है. वहीं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के मत्स्य पालकों को मछली के विपणन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 90 प्रतिशत सब्सीडी के रूप में अनुदान पर मोपेड सह आइस बॉक्स, थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर वाहन उपलब्ध कराने वाली है. सरकारी तालाब के जीर्णोद्धार व चौकीदार शेड निर्माण पर भी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाने वाला है. जिला मत्स्य पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने बताया है कि राघोपुर बखरी के बंद पड़े मत्स्य प्रजनन व बीज वितरण केंद्र का 5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कराया जायेगा. केंद्र के 35 एकड़ जमीन में मॉडल ब्रूड बैंक बनाया जायेगा. जिसमें सूबे में विलुप्त हो रही कवई, देशी मांगुर, सिंघी, गैंचा, बाश व टेंगरा के बीज का उत्पादन होगा. बताया गया है कि परियोजना मंजूरी के लिए फाइल नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद के पास मंजूरी के लिए भेजी गयी है. इसमें 90 प्रतिशत लागत राशि एनएफडीबी और शेष 10 प्रतिशत बिहार सरकार की होगी. अब देखना यह है कि इस फाईल का गंतव्य जमीनी हकीकत से जुड़ता है यह पहले की तरह यह फाइल भी धूल फांकती रह जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

गया के वस्त्र कारोबारी का कारनामा

40 करोड़ के कालेधन को कराया सफ़ेद

सुनील सौरभ

नोटबंदी के बाद जहां एक तरफ हर आम और खास व्यक्ति परेशान है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से कालाधन के रूप में करोड़ों की राशि जमा करने वाले लोग उसे सफेद करने से बाज नहीं आ रहे. बैंक कर्मियों की मिलीभगत से कालेधन वाले अपने करोड़ों की राशि को विभिन्न बेनामी और नामी खातों के सहारे सफेद करने में सफल भी हो गये हैं. फर्जीवाड़े का यह रूप भी सामने आया है कि खाता धारक को कोई जानकारी नहीं है और उनके खाते में करोड़ों का ट्रांजेक्शन भी हो गया. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया के मानपुर पटवाटोली में. जहां एक बड़े वस्त्र कारोबारी द्वारा सरकारी राजस्व को करोड़ों का चूना लगाये जाने का मामला प्रकाश में आया है. आयकर विभाग की टीम ने जब अचानक मानपुर के वस्त्र व्यापारी मोतिलाल पटवा के घर सहित तीन स्थानों पर छापामारी की, तब पता चला कि नोटबंदी के बाद 40 करोड़ रुपये को 36 विभिन्न खातों के सहारे सफेद कराया गया है. गौर करने की बात यह है कि जिन खातों में करोड़ों का कालाधन जमा किया गया, उनकी जानकारी खाता धारकों को भी नहीं थी. आयकर की छापेमारी में यह भी पता चला कि वर्षों से कारोबार कर रहे मोतिलाल पटवा न तो सेल्स टैक्स दे रहे थे और न ही इनकम टैक्स. मोतिलाल पटवा के द्वारा बेनामी खातों में कालाधन जमा कराने में एंट्री ऑपरेटरों की भूमिका की बात भी सामने आ रही है. मानपूर में मोतिलाल पटवा के 800 से अधिक पावरलूम हैं. वे बिना एंडवांस टैक्स चुकाए काम कर रहे थे.

साथ ही कारोबार के लिए दूसरों के खातों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था. मोतिलाल पटवा का कारोबार कोलकाता और झारखंड में भी फैला है. कोलकाता में इनकी गद्दी है, जबकि झारखंड में इन्होंने पहाड़ खरीदकर पत्थर का कारोबार शुरू किया है. मानपुर में इनके 5 मकान हैं. गाड़ियों के शोकीन मोतिलाल के पास तीन एसयूवी है. आयकर विभाग की टीम ने जब 13 दिसम्बर 2016 को मानपुर पटवाटोली में मोतिलाल के घर छापामारी की, तो उस समय नोटबंदी के बाद 20 करोड़ के कालेधन को सफेद करने का मामला सामने आया. लेकिन जैसे–जैसे जांच बढ़ती गई, वैसे–वैसे उस कालेधन की राशि भी बढ़ती गई, जिसे सफेद करने के तमाम उपाय किए जा रहे थे. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि मोतिलाल पटवा ने अपने कारोबार के लिए बैंक ऑफ इंडिया के जीवी रोड, गया ब्रांच में 36 खाते खुलवा रखे थे. कई खाते उनके ड्राइवर और कई रिक्सा चालकों के नाम पर भी थे. सभी खातों का एकाउंट अपडेटशन मोतिलाल पटवा खुद करते थे. कालेधन को सफेद करने के इस बड़े खेल में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की भूमिका की भी जांच की जा रही है. आयकर विभाग की टीम इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. आयकर विभाग के अधिकारी मोतिलाल पटवा द्वारा विभिन्न खातों में जाम किये गये रुपयों की पूरी जानकारी ले रहे हैं. माना जा रहा है कि जांच का दायरा बढ़ेगा तो बेनामी खातों की संख्या भी बढ़ सकती है. आयकर विभाग के निदेशक एके सिन्हा ने बताया कि कालेधन को सफेद बनाने के लिए कई बेनामी व जनधन खातों का इस्तेमाल किया गया है. सबकी जांच की जा रही है.

जांच में बैंक ऑफ इंडिया की इस शाखा में आधा दर्जन फर्जी खातों का भी पता चला है. आयकर विभाग की टीम इन खातों में किये गये लेन–देन में बैंक कर्मियों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है. शक के दायरे में आने वाले खाताधारकों से जब आयकर विभाग ने पूछताछ शुरू की, तो सभी ने न्यायालय का शपथ पत्र देते हुए जांच में सहयोग करने और सरकारी गवाह बनने पर सहमती जता दी. बैंक ऑफ इंडिया की इस शाखा में पांच अन्य ऐसे खातों का पता चला है, जिनमें 12 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन खाताधारक की जानकारी के बिना ही हो गया. हालांकि यह अब तक पता नहीं चल पाया है कि ये 12 करोड़ रुपये किसके हैं. पुलिस को शक है कि यह बड़ी राशि माओवादियों की हो सकती है. बैंक ऑफ इंडिया की जीवी रोड गया शाखा के ऐसे लगभग 60 खातों को आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया है, जिनमें नोटबंदी के बाद लाखों–करोड़ों के ट्रांजेक्शन हुए हैं. बहरहाल, करोड़ों के कालेधन को सफेद करने का मामला सामने आने के बाद पूरे जिले के बैंककर्मियों और कालाधन को विभिन्न रूपों में सफेद कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.■

feedback@chauthiduniya.com

नौनिहालों को पेट की समस्या
वात्सल्य चाईल्ड केयर सेन्टर
डाकबंगला रोड, विष्णुपुर, बेगूसराय, काली स्थान से 100.मीटर पूरब

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

बेगूसराय के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभात कुमार, पूर्व में राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली एवं वर्तमान में वात्सल्य चिकित्सा चाईल्ड केयर सेन्टर, बेगूसराय ने बच्चों को होने वाले पेट संबंधी रोग के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि यदि नवजात बच्चों में ज्यादा पेशाब और पैखाना हो रहा है तो चिंतित नहीं हो यदि वह मां के दूध के पीने के बाद हो रहा है तो। उस वक्त जरूरत है माँ को स्वस्थ रखने की बच्चा अपने आप स्वस्थ होगा। जरूरत है बच्चे की मां के खान–पान का खास ख्याल रखने की।

लेकिन यदि वही बच्चे को बाहर के दूध यानि काउ मिल्क, बोतल वाला दूध आदि से हो रहा है तो जरूरत है तुरंत अपने पेडियाट्रिक्टस डॉक्टर से सम्पर्क करने की। इस परिस्थिति में बच्चों को जिक द्वाप, एन्टीबॉयोटिक एवं ओआरएस का घोल दिया जाता है। यदि आपका बेबी दाना–दाना टाइप पौटी करता है तो जरूरत है बच्चे को डॉक्टर से इलाज कराने की। कड़ा टायलेट की स्थिति में डॉक्टर से सम्पर्क करें। बड़े बच्चे में यदि इस तरह की समस्या है तो उसे फाइबर युक्त चिजें खानी चाहिए। अधिक से अधिक पानी पिना चाहिए। साथ ही बच्चों में रेगुलर टायलेट की ट्रेनिंग देनी चाहिए। हरी सब्जी, फल और दूध के साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पिलायें कुछ परिस्थति में सुबह हल्का गर्म पानी में निंबू, शहद मिलाकर भी पिला सकते हैं। चार पांच दिनों पर यदि टॉयलेट नहीं होता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर इलाज करवायें तथा समय समय पर कुशल चिकित्सक से सलाह लेते रहें। कुछ खास बातें–• यदि दूध पीने के बाद बच्चे के पेट में गैस बने, या गैस मुंह से निकले तो इसे साधारण मानने की गलती न करें। • यदि 100.4 डिग्री फेरनहीट से ज्यादा बुखार हो। •यदि दस्त लगे •यदि बच्चा 2-3 बार से ज्यादा दूध न पिये। •पेशाब कम होना, दिनभर में बच्चे ने 4 से भी कम बार पेशाब की हो • बच्चे का चेहरा पीला पड़ जाए, गुस्सा करे व एनर्जी की कमी महसूस हो। • बच्चे के एंबुलिकल कॉर्ड (नाभि के आसपास) के आस पास लाल दाग या पस जमा हो जाए। • त्वचा पीली पड़ जाए।•

Dr. PRABHAT KUMAR
MD. PED. (BEGUSARAI)
नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylcobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA

मायावती का मुस्लिम प्रेम

बहेलिए का दाना

एस आर दारापुरी

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती ने मुसलामानों का वोट प्राप्त करने के लिए उन्हें 97 टिकट दिए हैं. इस बार दलित–ब्राह्मण कार्ड खेलने के बजाय मायावती दलित–मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं. ऐसे में इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि मायावती मुस्लिमों के कल्याण का कितना काम करती रही हैं. मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं. उल्लेख्य है कि मायावती तीन बार मुसलमानों को नहीं सुहाने वाली भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर के सरकार बना चुकी हैं. आगे भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर वह भाजपा से फिर हाथ नहीं मिलाएंगी. वर्ष 2002 में मायावती ने गुजरात जाकर मोदी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था और मोदी को 2000 से अधिक मुसलमानों की हत्याएं करवाने के मामले में क्लीनचिट भी दी थी. मायावती का मुस्लिम प्रेम उस बहेलिए जैसा है, जो चिड़ियों को फंसाने के पहले खूब सारे दाने डालता है.

पिछले दिनों आजमगढ़ रैली में मुसलमानों को फुसलाने के लिए मायावती ने कहा था, 'निर्दोष मुसलमानों को आतंक के मामलों में झूठा फंसाया जाता है.' मायावती के मुसलमानों के बारे में पूर्व रिकार्ड को देखते हुए उनका यह कथन केवल चुनावी जुमला है. यह सर्वविदित है कि मायावती के 2007 वाले मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे अधिक निर्दोष मुसलमान आतंकी गतिविधियों के आरोप में फंसाए गए थे. मुसलमानों को इन बम विस्फोटों के मामलों में फंसाया गया था–

(1) 22 मई, 2007– गोरखपुर बम विस्फोट कांड
(2) 23 नवम्बर 2007– वाराणसी कचहरी विस्फोट कांड
(3) 23 नवम्बर, 2007– फैजाबाद कचहरी विस्फोट कांड
(4) 23 नवम्बर, 2007 – लखनऊ कचहरी विस्फोट कांड.

विडंबना यह है कि 2008 में गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिद्दीन ग्रुप के लोगों ने यह स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में उक्त सिलसिलेवार बम विस्फोट उन लोगों ने किए थे. फिर उन्हीं विस्फोट मामले में पहले ही दूसरे लोगों को पकड़ कर जेल में क्यों ठूंस दिया गया और जब इसकी सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राप्त हो गई तब निर्दोष मुसलमानों को जमानत पर क्यों नहीं छुड़वाया गया? लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्हीं निर्दोष लोगों में खालिद मुजाहिद नाम का एक व्यक्ति भी था, जिसकी बाद में फैजाबाद से बाराबंकी अदालत में पेशी पर लाते समय संदेहास्पद मौत हो गई. आरोप था कि उसकी हत्या कर दी गई थी. उन्हीं आरोपों में बंद किए गए कुछ लोग हाल में छूटे हैं, पर अधिकतर अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं. लिहाजा, आजमगढ़ रैली में मायावती का कथन झूठा है, क्योंकि उसके लिए मायावती ही जिम्मेवार हैं.

मायावती का दलित प्रेम भी बेजोड़

मायावती का दलित प्रेम भी नायाब है. उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय के लोग उनके तथाकथित दलित प्रेम का बिंदुवार उदाहरण देते हैं. वे कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मायावती की वकालत दलित और पिछड़ा विरोधी है. पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मायावती की वकालत भी दलित विरोधी बताई जाती है. इसी तरह मायावती ने अपने शासनकाल (2007–12) में अनुसूचित जातियों के पदोन्नति में आरक्षण की बहाली हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी नहीं की, जिससे दलित अधिकारियों को पदावनत होना पड़ा. मायावती ने 2001 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लागू करने पर रोक लगा दी थी, जिससे दलितों का भारी अहित हुआ. उस आदेश के कारण दलितों के उत्पीड़न के मामले इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज नहीं हुए, जिसके कारण न तो उन्हें कोई मुआवजा मिल सका और न ही दोषियों को दंडित किया जा सका.

मायावती ने कांशीराम के प्रयासों से बनी फिल्म 'तीसरी आज़ादी' तथा रामास्वामी नायकर द्वारा लिखी पुस्तक 'सच्ची रामायण' पर रोक लगा दी थी. जानकार कहते हैं कि मायावती ने स्पोर्ट्स कॉलेज में दलितों के आरक्षण का आदेश कुछ सवर्णों द्वारा विरोध करने पर रद्द कर दिया था. मायावती ने सरकारी विद्यालयों में दलित रसोईयों द्वारा भोजन बनाने का विरोध करने पर भी दोषियों को दंडित करने के बजाय दलित रसोईयों की नियुक्ति का आदेश ही रद्द कर दिया था. इससे सरकारी स्कूलों में छुआछूत को बढ़ावा मिला. मायावती ने दलितों के आवास की भूमि को उनके पक्ष में नियमित किए जाने के आदेश का सवर्णों द्वारा विरोध करने पर उसे भी रद्द कर दिया था. मायावती ने 2007 में उत्तर प्रदेश में अंबेडकर महासभा को कार्यालय के लिए मिले सरकारी भवन का आवंटन रद्द करके उसे अपने मंत्री को आवंटित कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश पर महासभा को स्टे मिला. मायावती ने 2008 में लागू हुए वनाधिकार कानून के अंतर्गत वनवासियों और आदिवासियों को भूमि का मालिकाना अधिकार देने के बजाय उनके 81 प्रतिशत दावों को रद्द कर दिया था, जिस कारण उन्हें अपने कब्ज़े की ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आदेश प्राप्त करना पड़ा था. मायावती ने उत्तर प्रदेश के 2 प्रतिशत आदिवासियों के लिए विधानसभा की दो सीटें आरक्षित करने संबंधी बिल का विरोध किया था, जिस कारण उन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिल सकी थी. अब जाकर आदिवासियों के लिए दो सीटें आरक्षित हो सकी हैं.

इसी तरह जब 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं, तो उन्हीं दिनों दिल्ली में बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ कांड हुआ था. उस मुठभेड़ में आजमगढ़ के तीन लड़के मारे गए थे और आजमगढ़ को आतंक की नर्सरी घोषित किया गया था. इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह आरोप भी लगा कि दूसरे राज्यों की पुलिस उत्तर प्रदेश से आतंकियों को गिरफ्तार कर के ले जा रही है, लेकिन यूपी पुलिस कुछ नहीं कर रही है. इस पर यूपी पुलिस ने भी बाटला हाउस जैसी मुठभेड़ की योजना बनाई. इसमें 4/5 अक्टूबर 2007 की रात में सेना और पुलिस द्वारा मिलकर सेना के कार्यालय पर फर्जी आतंकी हमला दिखाने की योजना बनाई गई. इस मुठभेड़ में सेना और पुलिस को शामिल होना था और दो कश्मीरी आतंकवादियों को मार गिराया जाना था. किसी तरह इस षड्यंत्र की खबर सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को मिल गई. प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता व मैगसेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय ने एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक से इसे रुकवाने का अनुरोध किया. उन महाशय ने इस बारे में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से बातचीत की और उक्त फर्जी मुठभेड़ को रुकवाने के लिए कहा. फर्जी मुठभेड़ रुक गई, क्योंकि इस बारे में प्रेस को भी सूचित कर दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने संदीप पांडेय से ही पूछताछ का त्रासद दौर चलाया. दो कश्मीरी लड़कों को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की घटना उस समय तो टल गई, लेकिन उन्हें 25 जनवरी 2008 को दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर पर फर्जी मुठभेड़ कर मार गिराया गया. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने मुसलमानों को कितनी सुरक्षा और न्याय दिया था. मुसलमान यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या मायावती के सख्त प्रशासन की यही परिभाषा है?

मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में ही 6 फरवरी 2010 को सीमा आज़ाद और उनके पति को इलाहाबाद में माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर अन्य आरोपों के साथ–साथ देशद्रोह का भी आरोप लगाया गया था. सीमा आज़ाद एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. सीमा आज़ाद पीयूसीएल उत्तर प्रदेश की संगठन सचिव भी हैं. उन्होंने इलाहाबाद में बालू का अवैध खनन करने वाले माफिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी. सीमा ने मायावती के प्रिय प्रोजेक्ट गंगा–एक्सप्रेस के लिए जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण का भी कड़ा विरोध किया था. इस कारण रेत माफियाओं के इशारे पर सीमा आज़ाद को माओवादी कहकर गिरफ्तार किया गया था. उसे कई साल तक जेल में रहना पड़ा और जिला न्यायालय ने सीमा आजाद और उसके पति को उम्र कैद की सजा सुना दी. इस घटना से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायावती ने मुसलामानों के साथ–साथ खनन माफिया के इशारे पर किस तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया. सीमा आज़ाद के मामले में जब पीयूसीएल के एक प्रतिनिधि मंडल ने मायावती के उस समय के चहेते अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) बृजलाल जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, से मिलने के लिए समय मांगा तो उन्होंने इन्कार करते हुए कहा था, 'आप लोग तो माओवादियों की हिमायत करते हैं.'

आतंकवाद के मामले में मायावती की हिन्दू आतंकवादियों से सहानुभूति की सबसे बड़ी मिसाल कानपुर में बम विस्फोट की घटना है. इस घटना में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता बम बनाते समय मारे गए थे. यह घटना 23 अगस्त 2008 की है. मौके से बम बनाने का बहुत सा सामान भी मिला था. इस मामले में पुलिस ने इसे केवल एकल घटना मान कर इसके पीछे के गिरोह का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया. बाद में पता चला कि उनका इरादा जन्माष्टमी में बम विस्फोट कर के मुसलमानों के विरुद्ध माहौल पैदा करना था. लेकिन पुलिस ने इसे दबा दिया और मामले को रफा–दफा कर दिया गया. ■

उत्तराधिकार का यह कैसा अधिग्रहण!

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

सुलह–समझौते की कोशिशें सफल न होने पर समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव ने अंततः सार्वजनिक रूप से घोषित कर ही दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं और उनके बेटे ने अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष अवैध रूप से घोषित कर रखा है. मुलायम ने दावा किया कि साइकिल चुनाव चिन्ह उनका है, इस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं जता सकता. इसके साथ ही उन्होंने अपनी पीड़ा भी जता दी, 'अखिलेश मेरा बेटा है, पार्टी के ज्यादातर लोग उसके साथ चले गए, मेरे साथ तो थोड़े ही बचे हैं, बेटा है, उसे मैं क्या कर सकता हूं.' मुलायम ने प्रो. रामगोपाल यादव द्वारा बुलाई गई सभा को अवैध बताया और कहा कि 30 दिसम्बर को ही रामगोपाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तो उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार नहीं था. अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है

समाजवादी पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन के नए दौर में पहुंच चुकी है. इसमें व्यावहारिक रूप से अखिलेश यादव ने निर्णायक बढ़त बना ली है. संभव है अब नामकरण में भी परिवर्तन हो. चुनाव निशान के बारे में अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को करना है. जाहिर है सपा में परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है. मुलायम ने कभी अपने पुत्र की ताजपोशी का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा उन्हें ही बेदखल कर देगा.

सैफई परिवार में से एक घोषित बाहरी किरदार को निकाल दें, तो अन्य सभी लोग एक परिवार से ही संबंधित हैं. इस परिवार में दंगल दिखाई दिया, बर्खास्तगी, बहाली, नाराजगी, खुशी, जय, पराजय, तंज, भावुकता, एक से बढ़कर एक डायलॉग, सस्पेंस, सभी कुछ दिखाई दिए. किसी ने कहा कि इसकी पटकथा एक विदेशी चुनाव–प्रबन्धक ने लिखी थी. लेकिन इस बात में कोई दम नहीं दिखता. यदि कोई चुनावी–प्रबंधक ऐसी पटकथा लिखता है तो उससे तौबा ही कर लेनी चाहिए. इस पटकथा ने तो समाजवादी पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा. सत्ता–सुख और हार–जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन. इस दंगल से सपाई दिग्गजों को क्या लाभ मिला. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवा हैं, उनके पास सत्ता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम बुजुर्ग हैं, उनके पास उनका विराट अनुभव है. एक पीढ़ी से दूसरी में उत्तराधिकार का हस्तांतरण स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जिस अस्वाभाविक तरीके से उत्तराधिकार का अधिग्रहण हुआ, उसने राजनीतिक इतिहास में एक कसक डाल दी है. ऐसा नहीं होना चाहिए था.

feedback@chauthiduniya.com

यूपी की दो विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित, लंबे जन-संघर्ष की जीत

अब मिली असली आज़ादी

चौथी दुनिया ब्यूरो

देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ हो लेकिन उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को 4 जनवरी 2017 को आजादी मिली, जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा की. आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब जनजातीय बहुल यूपी के सोनभद्र जिले के गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चेरो, भुईंया और भुनिया न केवल मताधिकार का प्रयोग करेंगे बल्कि अपने लिए आरक्षित सीटों से अपनी उम्मीदवारी भी ठोकेंगे. साढ़े पांच लाख की आबादी के बावजूद यूपी में जनजातियों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं थी. निर्वाचन आयोग द्वारा यूपी की दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीटों को जनजातियों के लिए आरक्षित घोषित किए जाने के बाद से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे सोनभद्र में उत्सव सरीखा माहौल है. जगह-जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं और करमा गाये जा रहे हैं. गौरतलब है कि यूपी में छह वर्ष पूर्व हुए परिसीमन के बाद यह दो विधानसभाएं अस्तित्व में आईं. हालांकि 2012 में यह सीटें सामान्य थीं. समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार में मंत्री रहे विजय सिंह गोंड, जो कि दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में जनजातियों के नेता रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहते हैं कि न्यायालय का स्पष्ट आदेश था, लेकिन फिर भी सीटों को आरक्षित करने में हिला-हवाली की जा रही थी. गोंड ने कहा कि अब सही मायनों में सोनभद्र के आदिवासी आजाद हैं.

अजीबोगरीब आरक्षण, अजीबोगरीब चुनाव, केंद्र सरकार की अजीबोगरीब हिला-हवाली और न्यायिक प्रक्रिया की अजीबोगरीब दुलमुल नीति ने उत्तर प्रदेश के जनजातियों को उनके मौलिक अधिकारों से हमेशा वंचित रखा. आदिवासी या तो मुकदमा लड़ते हैं या टैक्स देते हैं. शायद ही सोनभद्र का कोई ऐसा आदिवासी हो जिसके खिलाफ जंगल विभाग ने मुकदमा कायम न कर रखा हो. लेकिन मौजूदा कवायद के बाद लगता है अब हालत बदलेंगे. जिले के आदिवासी इस बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे. इसके अलावा नगर और ग्राम पंचायतों में भी इनका चर्चस्व होगा. यह छोटा मजाक नहीं था कि पूर्व में जिले में दो विधानसभा सीटें थीं और दोनों ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थीं. हालत इस हद तक खराब थे कि केवल लोकसभा और विधानसभा में ही नहीं, जिन गांवों में जनजातियों की जनसंख्या 99 फीसदी थी और महज एक फीसदी घर अनुसूचित जाति के लोगों के थे, वहां पर भी ग्राम प्रधान अनुसूचित जाति का हुआ करता था. स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य की सीटों पर योग्य उम्मीदवारों की प्रर्याप्त दावेदारी नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत सदस्यों की दो तिहाई सीटें खाली ही रह जाती थीं.

यूपी में सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली जनजाति बहुल जनपद हैं. 2004 से पहले जब प्रदेश के आदिवासियों को जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया था, वो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा करते थे, जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहती हैं. बेहद लम्बी लड़ाई लड़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में यहां की नौ आदिवासी जातियों को, जिनमें गोड़, खरवार, बैगा, चेरो, पनिका, अगरिया, मांझी, पठारी और पहरिया शामिल हैं, अनुसूचित जनजाति की मान्यता दे दी गई. मगर अफ़सोस, सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को ज्यों का त्यों रखा गया. नतीजा यह हुआ कि मान्यता प्राप्त जनजातियां चुनाव लड़ने के अधिकार से ही वंचित हो गईं. मजाक सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, सरकार ने धांगर, बंसोर, घसिया, कोल, बैसवार समेत अन्य 15 आदिवासी जातियों को इस आरक्षण से अलग कर दिया, जबकि इन्हें भी जनजातियों में शामिल करने की मांग आजादी के बाद से ही की जा रही थी. दूसरी तरफ जिन जातियों को मान्यता दी गई, उनमें भी जमीनी वास्तविकताओं की जानबूझ कर अनदेखी की गई. पहरिया और पठारी सोनभद्र में नहीं के बराबर हैं, इन्हें भी जनजाति में शामिल कर लिया गया. वहीं गोंड और मांझी सोनभद्र में एक ही आदिवासी जातियां हैं, पर इन्हें अलग-अलग करके दो बार मान्यता दे दी गई. चुनाव आयोग का मौजूदा निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2012 में दिए गए आदेश के क्रम में आया है. यह आदिवासियों की बड़ी विजय है और इससे इस बेहद पिछड़े जिले की स्थिति बदलेगी, यह तय है.

आदिवासियों की इस लड़ाई में जन-संघर्षों की लंबी भूमिका रही है. पिछले दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर जब भारी तादाद में आदिवासी जमा हुए थे, तब भी यह एहसास पुख्ता हुआ था कि आदिवासियों का संघर्ष कितने समय की यात्रा के बाद इतना मजबूत हुआ है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में आदिवासियों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) समर्थित आदिवासी अधिकार मंच ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया था. पिछले लंबे अर्से से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और अन्य आदिवासी बहुल इलाकों में चल रहे आंदोलन के क्रम में आदिवासी समुदाय के लोगों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने बड़ी तादाद में राजधानी दिल्ली के धरना-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था.

उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदाय की आबादी 11 लाख से अधिक है. हाईकोर्ट ने 2012 में आदिवासी समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में विधानसभा में सीट आरक्षित करने का आदेश दिया था. इसके अनुपालन में तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश और विधेयक के जरिए दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना जारी कर दी. लेकिन विडंबना यह रही कि केंद्र सरकार ने 4 जुलाई 2014 को राज्यसभा में विधेयक वापस ले लिया. इस वजह से अधिसूचना लागू नहीं हो पाई और उत्तर प्रदेश के आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व से ही वंचित हो गए. राजधानी दिल्ली में आयोजित धरना-प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर दुद्धी और ओबरा विधासभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी. इस संबंध में प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था.

लंबे जन संघर्ष ने यह साबित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीट छीने जाने से देश में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है. आदिवासी अधिकार मंच के संयोजक व आईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर और आदिवासी नेता पूर्व विधायक विजय सिंह गोंड़ ने कई फोरमों पर कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में 4 जुलाई 2014 को संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक (तीसरा) 2013 वापस लेकर आदिवासी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया है. यह बड़ा सवाल था कि जिस समय मोदी सरकार संसद से बिल वापस ले रही थी, उस समय आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी सांसद और भाजपा से जुड़े अन्य आदिवासी सांसद चुप्पी साधे बैठे थे. आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से काट दिए जाने की कोशिश के खिलाफ आदिवासियों को व्यापक पैमाने पर गोलबंद किया गया.

यह विडंबना ही तो है कि सरकार लगातार दलितों और आदिवासियों के बजट में कटौती करती रही. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी का चार माह से भुगतान नहीं किया. परिणामतः भीषण सूखे और वर्षा के कारण संकटग्रस्त ग्रामीण परिवार भुखमरी के शिकार हैं. वृक्षारोपण के लिए कैम्पा कानून बनाकर वनाधिकार कानून को खत्म करने में केंद्र सरकार लगी हुई है. सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली का यह दलित-आदिवासी बहुल पहाड़ी अंचल उत्तर प्रदेश का कालाहांडी बना हुआ है. आजादी के साठ साल बाद भी चुआड़, नालों और बांधों का प्रदूषित पानी पीकर ग्रामीण बेमौत मर रहे हैं. आज भी इन क्षेत्रों में गांवों में जाने को सड़कें नहीं हैं और बीमारी की हालत में खटिया पर लादकर लोग इलाज के लिए ले जाते हैं. मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आदिवासियों और दलितों के विकास के लिए बजट में आवंटित होने वाली धनराशि में भी 32,105 करोड़ रुपये की भारी कटौती कर दी. आदिवासियों के लिए 2014-15 में आंवटित 26,714 करोड़ को घटाकर 2015-16 में 19,980 करोड़ और 2016-17 में 23,790 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही आदिवासी जीवन के लिए जरूरी मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य व छात्रवृत्ति के बजट में भी भारी कटौती कर दी गई है. दस लाख से भी अधिक आदिवासी समाज के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सरकार हनन कर रही है. वनाधिकार कानून के अंतर्गत आदिवासियों को मिलने वाली ज़मीन के 92,406 दावों में से 74,701 अर्थात 81 प्रतिशत दावे रद्द कर दिए गए हैं और मात्र 17,705 दावों में ही ज़मीन दी गई है. इसमें सोनभद्र जनपद के 65,526 प्राप्त दावों में से 53,506 दावे खारिज किए जा चुके हैं. इसमें भी सत्तर प्रतिशत दावे दुद्धी तहसील के आदिवासियों के हैं. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार आदिवासियों व वनाश्रित जातियों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर अधिकार देने को तैयार नहीं है. इससे उत्तर प्रदेश के आदिवासियों में घोर निराशा और आक्रोश व्याप्त है. इसके साथ ही सरकार वृक्षारोपण के लिए कैम्पा कानून बनाकर वनाधिकार कानून खत्म करने पर आमादा है.

आदिवासियों ने समवेत रूप से यह आवाज उठाई कि दुद्धी व ओबरा विधानसभा सीट को आदिवासी समाज के लिए आरक्षित करने के आदेश को हर हाल में लागू किया जाना चाहिए. इसके अलावा वनाधिकार कानून के तहत जमीन पर अधिकार देने, कोल, धांगर समेत सात अन्य जातियों को आदिवासी का दर्जा देने व गोंड़, खरवार समेत आदिवासियों का दर्जा पा चुकी 10 जातियों को चंदौली समेत पूरे प्रदेश में आदिवासी का आधिकारिक दर्जा देकर आबादी के अनुसार उन्हें बजट में हिस्सा देने जैसे सवालों पर भी आदिवासी अधिकार अभियान शुरू किया गया है. आदिवासी अधिकार को लेकर कई सम्मेलन हुए, जिनमें हजारों की संख्या में जुटे आदिवासियों ने इस बात पर गहरा रोष जताया कि केंद्र व प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस, भाजपा और सपा, बसपा की सरकारों ने आदिवासियों के अधिकार नहीं दिए. गोंड़, खरवार समेत दस जातियों को जब आदिवासी का दर्जा दिया गया था, उस समय केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार थी, पर उसने उनके लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की. उसके बाद बनी सरकारों ने तो आदिवासियों के आरक्षण को ही रोकने की कोशिश की. 2010 में उच्च न्यायालय ने आदिवासियों के लिए पंचायत में आरक्षण देने का निर्णय दिया था, पर उस समय मायावती सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और इसे स्टे करा दिया. बाद में आधे अधूरे मन से अखिलेश सरकार ने आंदोलन के दबाव में सीट आरक्षित की, पर इसमें भी बेईमानी हुई. कुशीनगर, जहां आदिवासी हैं ही नहीं, वहां आदिवासी आरक्षण दे दिया गया.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दुद्धी व ओबरा विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व मंत्री विजय सिंह गोंड़ ने इसे लोकतांत्रिक ताकतों के लम्बे संघर्ष का परिणाम बताया. चुनाव आयोग के इस निर्णय को उन्होंने भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में आदिवासी विरोधी मंसूबे के खिलाफ एक तमाचा माना है. उन्होंने बताया कि इन दलों के नेता अभी भी मोर्चा बनाकर आदिवासियों को उत्तर प्रदेश की राजनीति की मुख्यधारा में आने से रोकने में लगे हैं और आदिवासियों की आरक्षित सीट के खिलाफ इधर-उधर की दौड़ लगा रहे हैं. लेकिन इसमें उनका आदिवासी विरोधी चेहरा और बेनकाब हो रहा है और आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने में वह असफल साबित होंगे. ज्ञातव्य हो कि इन दलों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने 11 जनवरी को निर्वाचन कार्यालय दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की थी, लेकिन उनके आदिवासी सीट निरस्तीकरण के प्रतिवेदन को आयोग ने अस्वीकार कर दिया था. विजय सिंह गोंड़ ने बताया कि ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के आदिवासी अधिकार मंच और स्वराज इंडिया के सक्रिय सहयोग से आदिवासियों को यह अधिकार मिला है. इसलिए इस संघर्ष के लिए वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पंचायत चुनाव में ही बज गई थी मुनादी

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में ही तीन सौ से ज्यादा आदिवासियों ने पंचायत प्रमुख का चुनाव जीतकर खुद के ताकतवर होने के संकेत दे दिए थे. आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चेरो, भुईंयां और भुनिया जैसी आदिवासी जातियां अपनी मूल पहचान और आबादी के अनुपात में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ी थीं. सोनभद्र जैसे आदिवासी बहुल जिले में भी पिछले डेढ़ दशक से करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पा रहा था. पहली बार उत्तर प्रदेश की आदिवासी जातियों के तीन सौ से ज्यादा लोग अपनी मूल पहचान पर त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रमुख बने. ■

-चौथी दुनिया ब्यूरो

कहानी पार्ट 2

पर्स

(जिस चीज़ का वजन कम हो तो उसकी गति अधिक होती है)

विमल चन्द्र पाण्डेय

पिछले अंक से जारी

तुम मेरी लक्ष्मी हो जान. मैं पत्नी को मनाने का यत्न करता हूं. उसकी पत्नी अगर घरबोरन है तो होने दो. उसे नहीं समझ कि भविष्य के लिये बचत करनी चाहिये, लेकिन हम तो यह बात समझते हैं. सोचो अभी ईश्वर न करे उनके घर में कोई बीमार पड़ गया तो? उनके पास इलाज के पैसे तक नहीं होंगे. हम भी घूमेंगे थोड़ी बचत तो कर लें. मेरी पत्नी समझदार है. समझाने पर मान जाती है वरना मेरे कई दोस्तों की बीवियां जब से उनकी ज़िंदगी में आयी हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क बन गयी है. रासबिहारी जैसा छुट्टा खर्च करने वाला है, उसकी बीवी भी दो कदम मिलाने वाली मिली है. मुझे अक्सर चिंता होने लगती है कि आख़िर उसकी दोनों संतानों की पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी? आजकल की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो आप जानते ही हैं, इतनी महंगी है कि आदमी बिक जाय.

इस बार तो रासबिहारी ने हद ही कर दी. अपने जन्मदिन पर सब दोस्तों को घुमाने ऋषिकेश ले जायेगा. वह तो पूरे ऑफिस को ले जाने का प्लान बना रहा था लेकिन मणि और दिवाकर के समझाने पर तय रहा कि पुराने दोस्त चलेंगे यानि उनमें मैं भी हूंगा. मैं इस प्रकार की किसी भी बेवकूफी से दूर रहने का पूरा प्रयत्न करता हूं, लेकिन ये पट्ठा रासबिहारी भी ज़िद का पक्का है. पत्नी ने समझाया कि इतनी ज़िद कर रहे हैं, रविवार पड़ भी रहा है उस दिन, घूम आइये, वैसे भी ऐसे तो आप जाने से रहे. खैर, भाईसाहब, मैंने सोचा दोस्त का दिल क्या तोड़ूं, चला चलता हूं. श्रीमती जी ने मेरा बैग तैयार किया और मैंने अपने पैसे अंडरवियर समेत चार जगहों पर अलग अलग रख लिये. इसके बारे में आपकी भी मां ने आपको बताया ही होगा कि एक जगह का पैसा अगर चोरी हो जाय तो कम से कम दूसरी जगह का पैसा मुसीबत में मदद करे.

हम चारों की दिल्ली यात्रा सुखद रही. रास ने कहा था कि सारे बिल वह वहन करेगा इसलिये मैंने सोचा कि उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिये, आखिर उसका जन्मदिन है. लेकिन मणि और दिवाकर ने वहां का बाकी का खर्चा ज़बरदस्ती अपने ऊपर ले लिया. अरे यार, उसका जन्मदिन है, वह ज़िद कर रहा है तो करने दो खर्चा, मैंने उन दोनों की ज़िद से खुद को अलग रखा. वे दोनों हंसने लगे, दिवाकर ने तो बद्तमीज़ी से यह भी कहा कि भाई तेरा तो मैं जोड़ कर चल ही रहा हूं. इस पर तीनों काफी देर तक हंसते रहे. मुझे बुरा नहीं लगा. अपने दोस्त हैं, यही तो मज़ाक उड़ाएंगे, पैसे की ज़रूरत जब हम चारों के सामने एक साथ आयेगी तो सबको पता चल ही जायेगा कि कौन कितने पानी में है.

अगले दिन घूमने का प्लान था. हम होटल से तय समय से निकल गये. रास्ते में दिवाकर ने गाड़ी रुकवा कर सबको नाश्ता कराया. नाश्ता कर हम पहाड़ों की ओर निकले. वहां रोपवे पर आनंद लेने की योजना बनी. रोपवे पर जाने के लिये टिकट कटवाने के बाद लाइन लगा कर ऊपर की ओर चढ़ना था. वहां थोड़ी भीड़ भी थी. हमने यात्रियों को चढ़ाने वाले भाई साहब से मनुहार किया कि हम चारों दोस्तों को एक ही साथ जाने का मौका दिया जाय. वह भला आदमी था. दो लोगों का नंबर हमसे पहले था, उसने उन्हें रोक कर हम चारों को एक साथ एक ही झूले में जाने का मौका दिया.

झूला अपनी गति से चल रहा था और नीचे अंनत अथाह दूरी पर दिख रही थी ज़मीन. मैंने नीचे की ओर देखा तो मुझे झांई सी आने लगी. मैंने नज़रें ऊपर कर लीं. मैं भी पहाड़ों की ओर देखने लगा जहां की तस्वीरें मणि धड़ाधड़ लिये जा रहा था. मणि बाकायदा खड़े होकर तस्वीरें ले रहा था. वह वाकई बहुत साहसी है. रासबिहारी बैठे-बैठे पहाड़ों को बड़े प्यार से देख रहा था. पता नहीं उसे क्या ख़ूबसूरती नज़र आ रही थी. उसके चेहरे से यह भी लग रहा था कि वह बड़ा भावुक हो रहा है. दिवाकर के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव थे. मैंने देखा पहाड़ों के ऊपर बादल थे. पहाड़ों के ऊपर बादल ही तो होंगे कोई नदी थोड़ी होगी. पता नहीं रासबिहारी क्या देख रहा था कि अचानक वह उत्तेजना में झूला पकड़ कर खड़ा हो गया, वो देख दिवाकर इंद्रधनुष! आवाज़ सुनकर मणि ने भी सिर घुमाया. उसने एक बार कैमरा हटा कर देखा फिर कैमरा आंख पर लगा ही नहीं पाया.

अद्भुत सुंदर है यार! और कितना करीब. लगता है हम इसे हाथ से छू सकते हैं. मणि ने मुग्ध भाव से कहा. कैमरा उसने गले में लटका लिया. उसने कैमरे के लेंस का कवर पिछली जेब से निकाला ताकि कैमरे का लेंस बंद कर उसे थोड़ी देर का विराम दे. अचानक पिछली जेब से उसका पर्स उसकी हथेली के साथ सरक कर बाहर आया और गिर गया. मैंने पूरे चौकन्नेपन के साथ खुद को संभाले हुये एक झपट्टा मारा कि गिरते पर्स को पकड़ सकूं, लेकिन पर्स की गति मेरी गति से अधिक थी क्योंकि उसका वज़न कम था. किसी भी चीज़ का वजन कम हो तो उसकी गति अधिक होती ही है. मेरे मुंह से चीख निकल गयी. ओह तुम्हारा पर्स! मणि चौंक गया. उसने पलट कर नीचे की ओर देखा. उसका पर्स हवा में गोते खाता नीचे की ओर जा रहा था. उसमें से कुछ कागज़ भी निकल कर बाहर उड़ रहे थे. मणि ने दुखी भाव से नज़र ऊपर उठा कर मेरी ओर देखा. उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं थीं. उसने जल्दी से अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और जब उसका पंजा बाहर आया तो उसकी उंगलियों में कुछ सौ और पांच सौ के नोट फंसे हुये थे. उसने फिर से चेहरे पर दुख लिये एक बार नीचे की ओर देखा जहां उसका पर्स अब नज़रों से ओझल होने वाली सीमा पर था. अच्छा हुआ जो ये पैसे मैंने आलसवश पर्स में नहीं डाले थे, भाई इसे तू रखे रह, इस काम के लिये सबसे सही आदमी है तू. मैं बहुत लापरवाह हूं यार. मैंने उसकी अमानत अपने पास सुरक्षित की. यह ज़िम्मेदारी मेरे लिये एक तरह से मेरे चौकन्नेपन का सम्मान है. मेरे दोस्त भले मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन इसी बात के लिये मेरी कद्र तो करते ही हैं. मैं उसके पैसे अपने पर्स में एक तरफ सुरक्षित कर ही रहा था कि वह फिर से रासबिहारी के पास जाकर इंद्रधनुष देखने लगा.

इसका पर्स गिर गया भाइयों नीचे. मैंने रासबिहारी को सुना कर कहा. उसने एक बार मेरी ओर देखा और कहा, ओह! और फिर से इंद्रधनुष देखने लगा. अबे इसका पर्स गिर गया और तुम लोगों को कोई परवाह ही नहीं है. मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा तो मणि ने पलट कर संक्षिप्त जवाब दिया और फिर उसी ओर देखने लगा, अरे आरटीओ में मेरा परिचित है, डीएल दुबारा बन जायेगा, कार्ड ब्लॉक करा दूंगा, कैश ज़्यादा था नहीं.

मुझे आश्चर्य हुआ कि यह पर्स गिर जाने जैसी बड़ी घटना को इतना छोटा करके क्यों देख रहा है. फिर मुझे लगा कि ये लोग मेरा इतना मज़ा लिया करते हैं कि इसी संकोच में वह ज़्यादा चिंता दिखा नहीं सकता, अंदर से तो परेशान होगा ही. मुझे लगा जिस फालतू काम में सब खुद को इतना व्यस्त दिखा रहे हैं उसमें मुझे भी अपना उत्साह दिखाना चाहिये. मैंने दोनों हाथों से झूले को मज़बूती से पकड़ा और दूसरी ओर यानि रासबिहारी की ओर जाने लगा. रासबिहारी ने मुझे रुकने का इशारा किया और खुद मेरी तरफ आ गया ताकि झूले का वज़न बराबर रहे. मैं मणि और दिवाकर के पास जाकर इंद्रधनुष देखने की कोशिश करने लगा.

कहां हैं इंद्रधनुष? मैंने मणि से पूछा. उसने भौंहों से सामने की ओर इशारा किया और फिर मुग्ध-भाव से उसी ओर देखने लगा. मैंने फिर से देखने की कोशिश की. आसमान साफ था और लगता था जैसे किसी ने सूखी रेत बिखेर दी हो. मुझे कुछ दिखायी नहीं दिया. कहां है, मुझे तो नहीं दिख रहा. मैंने हर तरफ गर्दन घुमायी, मुझे सात रंग क्या एक भी रंग दिखायी नहीं दिया.

मैंने रासबिहारी की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया. उसने भी उंगली से जिस ओर इशारा किया उधर कुछ नहीं था. वे सब मेरे लिये चिंतित होने लगे. ये चिंता करने वाले भी कैसी कैसी बातों पर चिंता करने लगते हैं. अरे ठीक है यार, मुझे नहीं दिखायी दे रहा है उधर क्या है. मुझे लग रहा है उधर कुछ नहीं है तो दिक्कत क्या है? और उधर कुछ होता भी तो क्या हो जाता, इंद्रधनुष ही है न, मैंने कितनी ही बार देखा है.

मुझे लगता है मेरी दृष्टि कमज़ोर हो गयी है. वापस जा कर पहला काम यही करुंगा कि नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अनिल से अपनी आंख चेक कराउंगा. परिचित हैं, फीस लेंगे नहीं और दवाइयां पड़ोसी के एमआर से कह दूंगा कि दे जाये.

हर बात को ले कर चौकन्ना रहता हूं भाई साहब. यह मेरे चौकन्नेपन का ही नमूना है कि समस्या आयी नहीं कि मेरे पास उसका निदान मौजूद रहता है. ■

(लेखक युवा कथाकार और ज्ञानपीठ की ओर से दिए जाने वाले नवलेखन अवार्ड से सम्मानित हैं)

feedback@chauthiduniya.com

श्रद्धांजलि

पानी के पहरेदार को नमन

चौथी दुनिया ब्यूरो

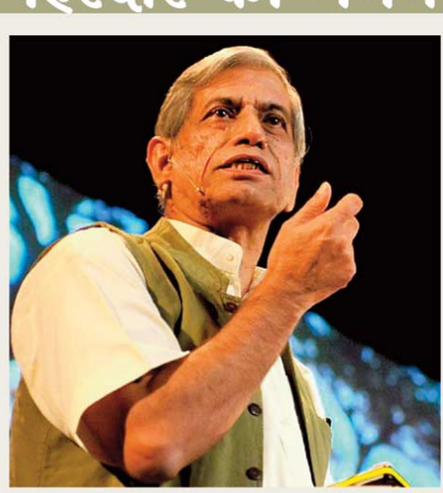

अनुपम मिश्र जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद् थे. पर्यावरण-संरक्षण के प्रति जनचेतना जगाने और सरकारों का ध्यानाकर्षित करने की दिशा में वह तब से काम कर रहे थे, जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था. शुरू में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस तल्लीनता और बारीकी से खोज-खबर ली है, वह कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए भी आज तक संभव नहीं हो पाया है. उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा. इसी तरह उत्तराखण्ड और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है.

इनका जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में श्रीमती सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिन्दी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहां सन् 1948 में हुआ. दिल्ली विश्वविद्यालय से 1968 में संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की. गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में उन्होंने पर्यावरण कक्ष की स्थापना की. वह इस प्रतिष्ठान की पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे. उन्होंने बाढ़ के पानी के प्रबंधन और तालाबों द्वारा उसके संरक्षण की युक्ति के विकास का महत्त्वपूर्ण काम किया था. वे 2001 में दिल्ली में स्थापित सेंटर फार एनवायरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. चंडी प्रसाद भट्ट के साथ काम करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में जंगलों को बचाने के लिये सहयोग किया था.

'आज भी खरे हैं तालाब' के लिए 2011 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अनुपम मिश्र ने इस किताब को शुरू से ही कॉपीराइट से मुक्त रखा है. 1996 में उन्हें देश के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. 2007-2008 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इन्हें कृष्ण बलदेव वैद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. इनकी प्रमुख रचनाओं में,'राजस्थान की रजत बूंदें' और 'आज भी खरे हैं तालाब' को शामिल किया जाता है. आज भी खरे हैं तालाब को ब्रेल लिपि सहित तेरह भाषाओं में प्रकाशित किया गया और इसकी एक लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं.

अपनी किताब में अनुपम मिश्र लिखते हैं कि 'तालाब कोई जानवरों के खुर से बन गया गड्ढा नहीं होता जो अपने आप बन जाएगा या अपने आप भर जाएगा. उसे बनाना पड़ता है.' अनुपम मिश्र जैसे तालाबों के विषय के जानकार भी अपने आप नहीं बनते, उसके लिए बरसों की साधना चाहिए. उनके फैलाए ज्ञान से कई क्षेत्र जल संरक्षण के मामले में स्वाबलंबी हो गए. अनुपम मिश्र का जाना परंपरागत जल संरक्षण अभियान के लिए एक बडी क्षति है. बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि सीएसई की स्थापना में अनुपम मिश्र का बहुत योगदान रहा है. इसी तरह नर्मदा पर सबसे पहली आवाज अनुपम मिश्र ने ही उठायी थी. अनुपम मिश्र लोकजीवन और लोकज्ञान के साधक थे. वे मानते थे कि केवल पर्यावरण की संस्थाएं खोल देने से पर्यावरण नहीं सुधरता. वैसे ही जैसे सिर्फ थाने खोल देने से अपराध कम नहीं हो जाते. जाहिर है, ये सन्देश हम करोड़ों भारतवासियों के साथ ही देश की सरकार के लिए भी है कि अगर हम आज नहीं चेते तो कल बहुत खराब होने वाला है. पानी के इस पहरेदार को नमन. ■

श्री चंद्र जैन बने अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 जनवरी को दिल्ली के विवेक विहार फेज-2 स्थित ग्रेंड रॉयल बैंकवेट में हुआ. इस अधिवेशन में आमामी वर्ष के लिए महासभा के अध्यक्ष और महामंत्री का मनोनयन हुआ. राष्ट्रीय महामंत्री ज्वाला प्रसाद 'अनिल' जी ने आगामी वर्ष के लिए अध्यक्ष पद हेतु श्री चंद्र जैन जी और महामंत्री के लिए अवधेश अग्रवाल जी के नाम का प्रस्ताव रखा. सभी प्रांतों के अध्यक्षों और महामंत्रियों सहित सभी ने सर्वसम्मती से दोनों के नामों पर सहमती जताई.

इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र जैन जी ने अपने स्वागत भाषण में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की. जिसमें कई प्रस्तावों को सर्वसम्मती से पास किया गया. जैसे- दिल्ली में महाराजा श्री अग्रसेन जी का भवन मंदिर स्थापित करना साथ ही वरिष्ठ नागरिक क्लब की स्थापना और अस्पताल की स्थापना, महाराजा अग्रसेन जी की बावडी का विस्तार एवं अग्रसेन जी का संग्रहालय निमार्ण, गरीब एवं विधवाओं की सहायता, सामूहिक विवाह का आयोजन कराना आदि. ■

अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र जैन (दाएं से दूसरा)

साईं वंदना

साईं भक्ति-प्रवाह के रहस्य

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

शिरडी के श्री साईंबाबा जब शारीरिक-रूप में शिरडी में थे, तो विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं वर्गों के हजारों लोग उनके पास आया करते थे. बाबा की सहायता एवं कृपा-प्राप्ति के लिए छोटे-बड़े, विवाहित एवं अविवाहित तथा समाज के प्रायः सभी वर्गों के लोग उनके पास आते थे. सांसारिकता से ग्रस्त व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आध्यात्मिक साधक अपने आध्यात्मिक मार्ग-दर्शन के लिए बाबा के पास आते थे. 'श्री साईं सच्चरित्र' में इन चरित्रों का उल्लेख मिलता है. हालांकि और भी बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे, जिनके विषय में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है.

श्री शिरडी साईं बाबा जैसे सद्गुरु एक समय में चेतना के दो स्तरों पर कार्य करते हैं. उनके कुछ क्रिया-कलाप प्रकट और कुछ अप्रकट एवं रहस्यमय होते हैं. गरीबों एवं भक्तों को भोजना कराना, उनकी शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों को ठीक करना, उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं धार्मिक कार्यों में सहायता करना आदि बाबा के प्रकट क्रिया-कलापों के कुछ उदाहरण हैं. बाबा जिस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, वह कभी-कभी तो बहुत ही चमत्कारिक था. शिरडी और शिरडी से बाहर रहने वाले सैकड़ों परिवार अपने कष्टों से छुटकारा पाने एवं जीवन-यापन के लिए बाबा पर ही निर्भर रहा करते थे. जो भी व्यक्ति साईं बाबा के पास आया, उन्होंने कभी भी उसे सहायता के लिए मना नहीं किया. हर रोज वे अपने भक्तों की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे. एक बार उन्होंने अपने एक भक्त से कहा कि वे (बाबा) पिछली रात सो नहीं पाए क्योंकि वे उस भक्त के विषय में रात भर सोचते ही रहे. वे अक्सर कहा करते थे, 'अगर मैं लगातार अपने बच्चों पर नजर न रखूं तो उनका क्या होगा?' उनकी यह भूमिका 'दाता' एवं 'रक्षक' की थी.

लेकिन श्री साईं बाबा की दूसरी भूमिका बहुत ही सूक्ष्म एवं रहस्यमय है, जिसने उनसे संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन को बदलकर एक स्थायी महत्व का बनाया है. एक सद्गुरु होने के नाते श्री शिरडी साईं बाबा का ईश्वरीय कर्तव्य भक्तों को इस दृष्टि से तैयार करना था कि उनके मानसिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास हो और वे अंततः मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो.

जारी...

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

कप्तानी से माही का किनारा ...पर धोनी की धुन बरक़रार

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय टीम के बेहद सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार वनडे और टी-20 की कप्तानी से भी किनारा कर लिया है. बीते कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट में कई बदलाव देखने को मिले हैं. दरअसल भारतीय क्रिकेट बोर्ड में लोढ़ा कमेटी को लेकर उठापटक का दौर देखा जा सकता है. लोढ़ा कमेटी के लागू होने के बाद बीसीसीआई के कुनबे में आग लग गई. इस कमेटी के आते ही बोर्ड के कई बड़े अधिकारियों की कुर्सी चली गई है. इतना ही नहीं अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई से अलग-थलग कर दिया गया है. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के अचानक कप्तानी छोड़ने को लेकर कई कयास लगाये जा रहे हैं. जानकारों की माने तो बीसीसीआई में आये सत्ता परिवर्तन ने माही को कप्तानी से अलग करने में अहम भूमिका निभायी है. बीसीसीआई में अब पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है. लोढ़ा कमेटी में कई ऐसे नियम हैं, जो शायद भारतीय क्रिकेट की पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं. इतना ही नहीं, सालों से बीसीसीआई को अपना घर बनाकर बैठे कई धाकड़ पदाधिकारी जो राज्य खेल संघों में मलाई काटते, उनकी भी लोढ़ा कमेटी के आने के बाद छुटटी हो गई. दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम विराट की कप्तानी में लगातार नया इतिहास बनाने में जुटी हुई है. विराट टेस्ट कप्तानी में लगातार अपना जलवा दिखा रहे हैं. माही टेस्ट क्रिकेट को पहले ही छोड़ चुके हैं. ऐसे में विराट के दमदार प्रदर्शन के आगे उनका रंग का फीका पड़ता दिख रहा है. उनपर लगातार वनडे और टी-20 की कप्तानी छोड़ने का दबाव बढ़ रहा था. इतना ही नहीं, हाल ही में वह मुख्य चयनकर्त्ता एमएसके प्रसाद से मुलाकात कर चुके थे. हालांकि कप्तानी छोड़ने के बाद भी माही विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में बने रहेंगे. कई स्वर्ण जीत के गवाह रहे माही ने हमेशा भारतीय क्रिकेट को बुलन्दियों पर पहुंचाया. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नम्बर वन टीम का तमगा हासिल किया. भारत ने उनकी कप्तानी में ही 2011 में विश्व कप जीतकर क्रिकेट जगत में भारत का डंका बजाया. माही के कप्तानी छोड़ने को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं. क्रिकेट के जानकारों की माने तो शायद माही को पता चल चुका है कि बतौर कप्तान उनके दिन लद चुके हैं. उसपर से लोढ़ा कमेटी का आना शायद माही के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ है. कुछ लोगों का मानना है कि माही अब बतौर विकेटकीपर 2019 का विश्व कप खेलना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि वह बतौर कप्तान अब अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. ऐसे में विराट को कप्तानी सौंप कर वह अपने खेल को फिर से पुरानी धार देने में सफल रहेंगे. कप्तानी के दबाव से अलग होकर वह अपने करिश्मायी बल्लेबाजी का नमूना एक बार फिर पेश कर सकते हैं.

जब भी टीम इंडिया के स्वर्णिम युग की बात की जायेगी, तो धोनी का नाम सबसे पहले लिया जायेगा. टीम इंडिया को धोनी का करिश्मा पहली बार 2007 में देखने को मिला. उस दौर में भारतीय टीम सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे बड़े खिलाड़ियों के बल पर विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना रही थी. हालांकि इन तीनों अनुभवी खिलाड़ियों ने टी-20 में खेलने से मना कर दिया था. टी-20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया को कप्तान की तलाश थी. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने माही की काबिलियत को पहचाने हुए उन्हें टी-20 विश्व कप की कप्तानी सौंपने में देर नहीं की. उस समय की खबरों की माने तो कैफ जैसे खिलाड़ी को भी कप्तानी देने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में यह अफवाह साबित हुई. माही की टीम एकदम युवा जोशों के साथ लबरेज दिख रही थी. टीम के कई खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी हुनर की बदौलत देश का मान बढ़ाने का दावा भी पेश कर रहे थे. युवा टीम के सहारे नया इतिहास गढ़ने की कला तो केवल माही से सीखी जा सकती है. उन्होंने इस टी-20 में शानदार कप्तानी कर भारत को टी-20 विश्व कप का खिताब दिलाया. धोनी ने इस विश्व कप में मैच के दौरान कई चौंकाने वाले फैसले लिये, लेकिन उनका हर दाव सटीक बैठा और टीम इंडिया ने इतिहास बनाया. यहीं से लगने लगा कि माही भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल सकते हैं. उन्होंने इसके बाद वनडे और टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की बागडोर अपने हाथों में ले ली. भारतीय टीम में फैब फोर के रूप में जाने जाने वाले द्रविड़, सचिन, गांगुली और लक्ष्मण जैसे क्रिकेटरों ने माही को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. हालांकि यह भी सत्य है कि इन्हीं की बदौलत माही ने खूब सुर्खियां बटोरी. इसके बाद धोनी अपने हिसाब से टीम इंडिया को बनाने में जुट गये. टीम बनाने के चक्कर में कई बड़े खिलाड़ियों से टकराव भी सामने आया. वीरू से उनके संबंध को लेकर हमेशा मीडिया में कई बातें सामने आयीं. सहवाग का करियर खराब फॉर्म की भेंट चढ़ गया. इस दौरान दोनों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली. इतना ही नहीं, हरभजन सिंह और युवराज सिंह का करियर भी माही की कप्तानी में उतना सफल होता नहीं दिखा. दोनों ही खिलाड़ी अपनी खराब फिटनेस और फॉर्म के चलते टीम इंडिया से बाहर होते रहे. दूसरी ओर रैना को माही की कप्तानी में खूब मौका मिला. एक समय रैना का बल्ला लम्बे अरसे से खामोश था, लेकिन कप्तान धोनी ने उन्हें खूब मौके दिये. इसको लेकर माही की पहले खूब किरकिरी हुई, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की. धोनी की कप्तानी में सचिन ने लगातार कई रिकॉर्ड बनाये. यहां से टीम इंडिया जीत की पटरी पर दौड़ती नजर आयी. कई बड़े टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा. 2011 विश्व कप में टीम इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए कप अपने नाम किया. यह जीत इसलिए खास थी क्योंकि 1983 के बाद पहली बार भारतीय टीम विश्व क्रिकेट का सरताज बनी. सचिन ने अपने करियर में तमाम उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन विश्व कप जीतना उनके क्रिकेट करियर के लिये बेहद खास था. बाद में दिग्गज खिलाड़ियों के सन्यास का सिलसिला भी शुरू हो गया. एकाएका टीम बदली हुई नजर आने लगी. इस टीम में माही एक अलग किरदार के रूप में सामने आये. टीम के हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका से अवगत कराने में माही ने कोई कसर नहीं छोड़ी. 2011 का विश्व कप जीतने के बाद धोनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई. छोटे शहर के बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले धोनी का क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का यह सफर एक चमत्कार से कम नहीं है. एक लीडर के तौर पर उन्होंने भारत को कई सीरीज तोहफे में दिये. धोनी के नेतृत्व में ही भारतीय टीम ने 2008 में कंगारूओं को सीबी सीरीज में परास्त किया था. यह जीत इसलिए अहम थी, क्योंकि इस टीम में दादा और द्रविड़ को मौका नहीं दिया गया था. धोनी लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन टीम के दो भागों में बटने की खबर से पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल सा आ गया. दरअसल माही टीम बनाने के चक्कर में कई अनुभवी खिलाड़ियों को साथ रखना नहीं चाहते थे. जानकारों की माने तो माही सचिन, गम्भीर, सहवाग व दादा जैसे उम्रदराज खिलाड़ियों को टीम में रखना नहीं चाहते थे. वह अक्सर खराब फिटनेस के लिए इन खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए दिखे. धोनी भारत के अकेले ऐसे कप्तान हैं, जिनकी अगुवायी में भारत ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में चैम्पियन का ताज पहना है. माही ने 199 मैचों में टीम की बागडोर संभाली और 110 में जीत का परचम लहराया, जबकि टेस्ट क्रिकेट को वह पहले ही अलविदा कह चुके हैं. उन्होंने 60 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए 27 जीत दिलायी.

उनके कप्तानी छोड़ने के बाद पूरी दुनिया में उनके द्वारा बनाये गये रिकॉर्ड की चर्चा हो रही है. पूर्व खिलाड़ी उनकी शान में कसीदा गढ़ते दिख रहे हैं. धोनी के बाद उनकी जगह लेने वाले विराट कोहली ने भी माही की जमकर तारीफ की और यहां तक कह डाला कि धोनी ने ही उन्हें टीम से बाहर होने से बचाया. विराट के अनुसार, करियर के शुरुआती दौर में उनकी बल्लेबाजी बेहद खराब थी लेकिन माही के सपोर्ट से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया. धोनी ने अब भारतीय क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है और अब बेफिक्र होकर खेलना चाहते हैं. माही की निगाह 2019 में होने विश्व कप पर है. उनकी फिटनेस को देख कर लग रहा है कि वह अगला विश्व कप खेल सकते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में उनका बल्ला कितना दहाड़ता है. इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास काबिलियत है. उनके शॉट में अब भले ही पुरानी बात न हो, लेकिन अब भी वह भारतीय क्रिकेट में लम्बा योगदान दे सकते हैं. अब देखना रोचक होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज में वह कैसा प्रदर्शन करते हैं. ■

धोनी भारत के अकेले कप्तान हैं जिनकी अगुवायी में भारत ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में चैम्पियन का ताज पहना है. माही ने 199 मैचों में टीम की बागडोर संभाली और 110 में जीत का परचम लहराया जबकि टेस्ट क्रिकेट को वह पहले ही अलविदा कह चुके हैं. उन्होंने 60 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए 27 जीत दिलायी.

हार कर भी जीत गए धोनी

भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी को अपने आखिरी कप्तानी मैच में हार तो मिली लेकिन वे अपने प्रशंसकों का दिल जीतने में कामयाब रहे. धोनी के प्रशंसकों ने उनका जितना सम्मान मैदान के अंदर किया, उससे ज्यादा मैदान से बाहर और सोशल मीडिया पर किया गया.

धोनी ने क्रिकेट के लिए जो किया, उसका रिकॉर्ड छू पाना मुश्किल है. धोनी ने अपने 11 साल के करियर में रिकॉर्डों की ऐसी झड़ी लगाई कि उन्हें तोड़ पाना किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल है. धोनी भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर भी हैं. आंकड़े भी ऐसा ही बोलते हैं. विकेटकीपर धोनी पहले भारतीय हैं, जिनके नाम 350 विकेट (261 कैच और 89 स्टंपिंग्स) हैं. उनसे आगे सिर्फ कुमार संगकारा (482), एडम गिलक्रिस्ट (472) और मार्क बाउचर (424) हैं. कोई दूसरा भारतीय धोनी के आस-पास भी नहीं है.

धोनी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक कुल 14,706 (तीनों फॉर्मेट जोड़कर) रन बनाए हैं. धोनी ने अपने करियर की शुरुआत में ही श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी खेली थी. वनडे में किसी भी विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा खेली गई यह सबसे बड़ी पारी है. दूसरे नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट की 172 रनों की पारी है. धोनी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 302 छक्के लगाकर धोनी इस सूची में अन्य भारतीय बल्लेबाजों से कोसों आगे हैं. वर्तमान का कोई भी बल्लेबाज उनके आस-पास भी नहीं है. धोनी सबसे सफल भारतीय कप्तान के रूप में तो स्थापित हो ही चुके हैं. धोनी की कप्तानी में भारत ने 107 वनडे और 27 टेस्ट मैच जीते हैं. दूसरे नंबर पर सौरव गांगुली हैं, जिनकी कप्तानी में 76 वनडे मैच और 21 टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीते. इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के सभी टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं. भारत ने धोनी की कप्तानी में 50-50 ओवरों का वर्ल्ड कप, टी-20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती. ऐसा कारनामा करने वाले धोनी विश्व के इकलौते कप्तान हैं. ■

युवराज की वापसी पर उठे सवाल बेमानी

भारतीय टीम से लम्बे अरसे से बाहर चल रहे युवराज सिंह एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी को लेकर कई सवाल उठाया जा रहा है. दरअसल माही के कप्तानी छोड़ने के बाद उनकी टीम में एकाएक जगह बन गई, तो इस पर सवाल उठने शुरू हो गए. जबकि युवी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. युवराज ने रणजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ मुकाबलों में 724 रन बनाकर अपने बल्ले की ताकत दिखाई. उन्होंने इस सीजन में 260 रन की जबरदस्त पारी खेल कर अपनी वापसी का दावा ठोका था. ■

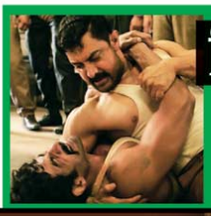

फिल्म दंगल सोशल साइट फेसबुक पर दूसरे दिन ही लीक हो गई. ख़बर आई कि एक पाकिस्तानी यूज़र ने फेसबुक पर फिल्म अपलोड की थी. ढाई घंटे की इस फिल्म को फेसबुक पर ही चार लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

फेसबुक पर फिल्म को लीक करने वाले का नाम हाशमी बताया गया. हाशमी की प्रोफाइल के मुताबिक वो पाकिस्तानी है और दुबई में रहता है.

फिल्म लीक होने का असर बॉक्स ऑफिस पर नहीं पड़ा

फिल्म के लीक होने के बाद से ऐसा लग रहा था कि इसका असर फिल्म के व्यवसाय पर पड़ेगा. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. 70 करोड़ के बजट में तैयार हुई इस फिल्म को सुपरहिट होने के लिए 100 करोड़ तक का कलेक्शन करना था, जो इसने अपने पहले वीकेंड में ही पूरा कर लिया.

अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी दंगल, साल 2016 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई है. ■

बॉक्स ऑफिस का असली सुल्तान आमिर खान

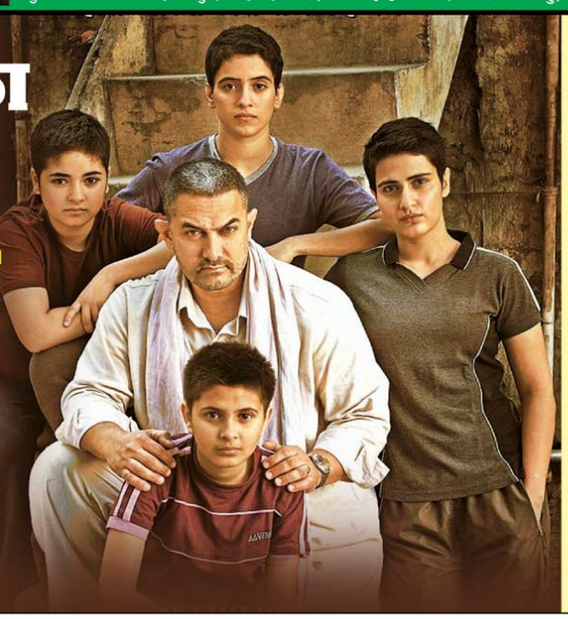

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

साल 2016 की मोस्ट अवेटेड फ़िल्मों में शामिल आमिर ख़ान की फिल्म *दंगल* का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. फिल्म 23 दिसंबर को बिना किसी कंट्रोवर्सी के रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज तीन दिनों में ही सफलता के झंडे गाड़ दिए. भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बॉक्स ऑफिस पर दंगल का मंगल ही मंगल हो रहा है. डोमेस्टिक मार्केट में दंगल 4300 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फ़िल्म को 1000 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया है. आमिर ख़ान स्टार फ़िल्म दंगल को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. भारत में फ़िल्म की एडवांस बुकिंग अच्छी रही और फिल्म 10-12 दिनों तक हाउसफुल रही. जिसके चलते फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. इस शुरुआत को शानदार माना जा रहा है. गौरतलब है कि फिल्म दंगल रेसलर महावीर सिंह फोगट की बायोपिक फ़िल्म है.

फिल्म का दर्शकों में इतना जबरदस्त क्रेज देखने को मिला कि भारत में दंगल ने मात्र तीन दिनों में ही 100 करोड़ और एक सप्ताह में 197 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर लिया. दंगल का कलेक्शन एक सप्ताह बाद भी कम नहीं हुआ और फिल्म ने 10 दिनों में लगभग 270 करोड़ का आंकड़ा छू लिया. तीसरे सप्ताह में फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया जो कि एक रिकॉर्ड है.

दंगल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. विदेशों में दंगल ने लगभग 192 करोड़ का बिजनेस किया है. भारत में फिल्म 370 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. दंगल का वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 700 करोड़ हो चुका है. फिल्म अभी भी देश-विदेश में बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और आने वाले समय में कुछ और रिकॉर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है. ये सभी आंकड़े शुरुआती 25 दिनों के हैं.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन में दंगल अभी टॉप -5 में दूसरे स्थान पर है. पहले स्थान पर आमिर खान की ही पीके (792 करोड़) है. दूसरे स्थान पर दंगल (698 करोड़), तीसरे स्थान पर सलमान की बजरंगी भाईजान (626 करोड़), चौथे स्थान पर सुल्तान (589 करोड़) व पांचवे स्थान पर आमिर की ही धूम-3 (542 करोड़) है. यानि टॉप पाइव में आमिर और सलमान का जलवा छाया रहा है.

दंगल से नाराज हैं गीता का यह पूर्व कोच

दंगल की सफलता से आमिर खान और फिल्म से जुड़े अन्य लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इसकी कहानी ने गीता फोगाट के कोच को नाराज कर दिया है. उनका आरोप है कि फिल्म से उनकी छवि को आघात पहुंचा है और वे इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं. महिला रेसलर गीता फोगाट के कोच प्यारा राम फिल्म दंगल में खुद की नकारात्मक छवि दिखाए जाने से नाराज़ हैं. उन्होंने कानूनी कार्रवाई पर विचार करने की भी बात कही है. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि जब लुधियाना में दंगल की शूटिंग चल रही थी, तब मैं वहां गया था. मैंने वहां अभिनेता आमिर खान और निर्देशक से बात की. दोनों ने फिल्म की कहानी के बारे में मुझसे कोई बातचीत नहीं की. सिर्फ यह बताया गया कि फिल्म महावीर फोगाट और उनकी रेसलर बेटियों गीता-बबिता की कहानी पर बन रही है. मुझे नहीं पता था कि फिल्म में मेरी छवि को नकारात्मक दिखाया जाएगा.

प्यारा राम ने दावा किया कि फिल्म को रोचक बनाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है. हकीकत से इसका कोई सरोकार नहीं है. दरअसल, 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता की प्रतिद्वंद्वी का नाम एमिली बेंस्टेड था. क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि गीता फाइनल में बड़ी मुश्किल से जीतीं, जबकि गीता ने एमिली को एकतरफा मुकाबले में 8-0 से शिकस्त दी थी. तब टीम के कोच प्यारा राम सोंधी थे.■

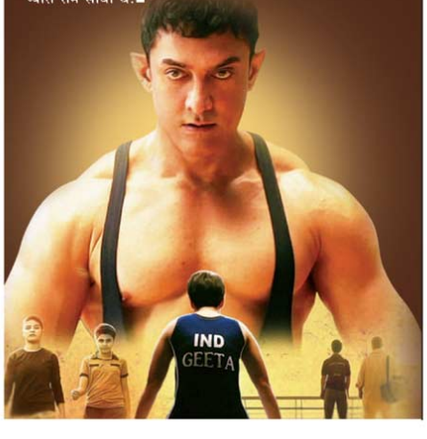

वर्ल्ड आइकॉन अवार्ड-2017

यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रमुख शहर दुबई में आगामी 25 मार्च 2017 को वर्ल्ड आइकॉन अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है. समारोह में दुनिया के तकरीबन 8 देशों की हस्तियां अपनी आमद दर्ज करायेंगी, चौथी दुनिया के तत्वावधान में आयोजित होने जा रहे इस समारोह के सह आयोजक के रूप में मायापुरी, हिंट मीडिया, ब्राइट आउटडोर, कंपलीट सिनेमा सहित देश के अग्रणी मीडिया संस्थान जुड़े हुए हैं. समारोह की चयन समिती का नेतृत्व पूर्व राज्य सभा सांसद व चौथी दुनिया के प्रधान संपादक श्री संतोष भारतीय कर रहे हैं. प्रमुख सदस्यों में डॉ. कृष्णबीर चौधरी, श्री कमल शेखरी, श्री पी.के. बजाज, श्री आचार्य एच.डी. गुप्ता, डॉ. कमलजीत इत्यादि हैं. चयनित शख़्सियतों में थाइलैंड की प्रिंसेज, हर हाइनेस मांम लुथिंग राजादासारी जयंकूरा, श्री योगेश लखवानी, श्री सुरेश यादव सहित कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हैं. कार्यक्रम के प्रस्तुता मस्ताना बासमती राइस है, व मुख्य संयोजक श्री अनिल खुराना हैं. अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर व सिखोस्की ज्वैल्स के प्रमुख श्री राजेन्द्र जैन जैसी शख़्सियतें समारोह की शोभा बढ़ायेंगी. समारोह का निर्देशन दुष्यंत सिंह करेंगे.■

25 MARCH 2017 LIVE IN DUBAI

MAZZA... MASTI ... MASTANA...
MASTANA®
BASMATI RICE
PRESENTS

WORLD ICON AWARDS

Dushyant Pratap Singh

Santosh Bhartiya

Dr. Kamaljit

Yogesh Lakhani

Dr. H.D. Gupta

Archana Kochhar

Manjari Phadnis

India Brand Partner
चौथी दुनिया Pioneer alliance News मायापुरी BRIGHT OUTDOOR MEDIA PVT. LTD MASTANA
COMPLETE CINEMA Mallic's हिन्ट हिन्दी

Digital Media Partner
DainikBhaskar.com

Directed by Dushyant Pratap Singh
www.facebook.com/m4udushyant